

हरियाणा विधान सभा की

कार्यवाही

19 जनवरी, 1976

खण्ड 1 अंक 6

अधिकृत विवरण

विषय—सूची

सोमवार, 19 जनवरी, 1976

पृष्ठ

सख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(6) 1

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर..

(6) 20

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

(6

) 31

43

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

(6) 48

वर्ष 1975-76 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त)का

(6) 46

पेश करना

प्राक्कलन समिति का वर्ष 1975-76 के अनुपूरक

(6) 46

अनुमान (दूसरी किस्त) पर प्रतिवेदन पेश करना

वर्ष 1976-77 के बजट पर सामान्य चर्चा क्रमशः

(6)46- 82

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 19 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल,
विधान भवन, सैक्टर— 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई । अध्यक्ष

(चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Question Hour.

तारांकित प्रश्न संख्या 1408

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य,
चौधरी— राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1436

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य,
चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1456

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य,
चौधरी देवी लाल, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Plots Allotted to Harijans

***1509. Rao Dalip Singh :** Will the Minister for

Revenue be pleased to state the district-wise total number of residential plots allotted to Harijans in the State during the year 1974-75 to-date ?

State Minister for Agriculture & Revenue

(Chaudhri Surjit Singh Mann) : During the year 1974-75, no homestead sites were allotted to Harijans and members of notified Backward Classes. The scheme was started during the current year (1975-76) and the position regarding allotment of plots to Harijans and members of notified Backward Classes is given below :—

Sr. No.	District	No. of plots allotted to :		
		Harijans	Backward Classes	Total
1.	Ambala	4,176	2,720	6,896
2.	Kurukshetra	6,421	2,768	9,189
3.	Karnal	16,889	11,355	28,244
4.	Sonepat	5,956	4,786	10,742
5.	Rohtak	8,315	3,247	11,562
6.	Hissar	17,449	6,708	24,157
7.	Bhiwani	5,882	2,160	8,042
8.	Sirsa	9,370	2,977	12,347

9. Narnaul	5,645	2,850	8,495
10. Gurgaon	11,338	8,959	22,297
11. Jind	4,670	2,218	6,888
Total	98,111	50,748	1,48,859

राव दलीप सिंह : क्या वजीर साहब बताएंगे कि ये जो डेढ़ लाख के करीब प्लॉट्स दिए गए हैं, इन पर हरियाणा सरकार ने कुल कितना खर्च किया है ?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : ये सारे प्लॉट्स शामिल जमीन में से दिए गए हैं ।

चौधरी राम प्रशाद : क्या वजीर साहब बताएंगे कि ये जो प्लॉट्स दिए गए हैं, क्या इसी तरह से शहरों में जो हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लोग रहते हैं, उनको भी दिए जाएंगे?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : अभी तक शहरों में इश्तेमाल नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो उनको भी दे देंगे ।

चौधरी पीर चन्द : क्या वजीर साहब बताएंगे कि ये जो प्लॉट्स दिए गए हैं, इन पर मकान बनाने के लिए सांठ्हा या लोन्ज देने की सरकार का कोई तजवीज जेरे गौर है?

राजस्व मन्त्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) : ऐसी कोई

तजवीज इस वक्त जेरे गौर नहीं है ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये जो हमारे शहरों में रहने वाले हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के भाई हैं, उन के पास भी रिहायशी प्लाट्स नहीं हैं और उनको भी रिहायशी प्लाट देने पर सरकार गम्भीरता के साथ विचार कर रही है । लेकिन इस बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम उनको बिल्कुल मुफ्त प्लाट नहीं दे पाएंगे, जमीन ऐक्वायर करेंगे और फिर उन से 'नो प्रोफिट नो लोस' के आधार पर उनकी कीमत वसूल करेंगे, परन्तु यह रकम काफी आसान किशतों पर वसूल करेंगे । तो इस प्रकार से यह सुविधा उनको देने पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : क्या वजीर साहब बताएंगे कि बहुत से ऐसे गांव भी हैं, जिनमें शामलात जमीन नहीं है, तो वहां पर भी हरिजनों और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को ये प्लाट देने का सरकार का विचार है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : जहां पर शामलात जमीन नहीं है, वहां पर इस काम के लिए जमीन ऐक्वायर करने के लिए डी०सीज० को आर्डर कर दिए हैं ।

चौधरी रिजक राम : वजीर साहब ने अभी फरमाया था कि शहरों में उस वक्त ये प्लाट देने का विचार है, जब वहां पर

इश्तेमाल हो जाएगा, तो क्या सरकार शहरों में इश्ते— माल कराने का विचार रखती है और अगर रखती है, तो कब तक हो जाएगा?

Pandit Chiranji Lal Sharma : There is no such proposal under consideration of the Government.

चौधरी रिजक राम : क्या इसका मतलब यह है कि कन्सालीडेशन से पहले वहां देना नहीं चाहते और कन्सालीडेशन कराना नहीं चाहते, तो फिर प्लॉट कैसे उनको मिलेगे?

श्री बनारसी दास गुप्त : जैसे मैंने अभी—अभी अर्ज किया है, उसी प्रकार से वहां पर देना चाहते हैं ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या वजीर साहब बताएंगे कि ये जो डेढ़ लाख के करीब प्लॉट दिए गए हैं, क्या इनके अलावा भी ये दिए गए हैं, और इलिजिबल केसिज हैं देने के लिए?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : जी हां । 32, 345 और केसिज हैं ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या वजीर साहब बताएंगे कि क्या इन सारे प्लॉट्स का फिजीकल पुजेशन दे दिया गया है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : जी हां, दे दिया गया है और अब रजिस्ट्री करवाने की जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : क्या वजीर साहब बताएंगे कि जो इलिजिबल केसिज बाकी रहते हैं, उनका जिलावार ब्रेक-अप क्या है?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : अम्बाला में पांच हजार इलिजिबल हरिजन थे और उन में चार हजार को दे दिए गए हैं, तीन हजार बैकवर्ड क्लासिज के इलिजिबल थे और उनमें से 2770 को दे दिए हैं । कुरुक्षेत्र में 6872 हरिजन केसिज हैं, जिन में से 6431 को दे दिए हैं, बैकवर्ड क्लासिज के 3074 केस थे और इनमें से 2768 को दे दिए हैं । करनाल में 20,305 हरिजन केस थे, जिन में से 16,888 को दे दिए हैं, बैकवर्ड क्लासिज के 13 हजार केसिज में से 11 हजार को दे दिए हैं । सोनीपत में हरिजनों के 11,002 केसिज में से 5,956 को दे दिए हैं, बैकवर्ड क्लासिज के 9,324 में से 4,776 को दे दिए हैं । रोहतक में 11,975 हरिजन केसिज थे, जिनमें से 8,315 को दे दिए हैं, बैकवर्ड क्लासिज के 5,677 केसिज थे, जिनमें से 3,224 को दे दिए हैं । हिसार में 17,534 हरिजनों के केसिज थे, जिनमें से 17,449 को प्लॉट्स दे दिए हैं, बैकवर्ड क्लासिज के 6,712 थे, जिनमें से 8,708 को दे दिए गए हैं । भिवानी में 7,452 हरिजनों के केसिज थे, जिनमें से 5,882 को दे दिए हैं, बैकवर्ड क्लासिज के 2,795 केसिज थे, जिन में से 2,160 को दे दिए हैं । सिरसा में 9,770 हरिजन केसिज थे, जिनमें से 9,370 को दे दिए हैं, बैकवर्ड क्लासिज के 2,997 केसिज थे और इनमें से 2,997 को

दे दिए गए हैं । महेन्द्रगढ़ में 6, 403 हरिजन केसिज थे, जिन में से 5, 645 को दे दिए हैं, बैकवर्ड क्लासिज के 3, 202 में से 2, 850 को दे दिए गए हैं । गुड़गांव में 15, 219 हरिजन इलिजिबल केसिज थे, जिनमें से 13, 338 को दे दिए हैं, बैकवर्ड क्लासिज के 9,735 केसिज में से 8, 959 को दे दिए हैं । इसी तरह से जींद में हरिजनों के 6, 951 इलिजिबल केसिज थे, जिन में से 4, 770 को प्लाट दे दिए हैं, और बैकवर्ड क्लासिज के 3, 333 इलिजिबल केसिज में से 2, 118 को ये प्लाट दे दिए गए हैं । बाकी कितने रह गए हैं, यह आप तफरीक करके निकाल लें । (हंसी)

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : गवर्नमेंट की दयादृष्टि से यह मसला तो हरिजनों का हल हो गया है, लेकिन क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि कितने परसैन्ट हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज की आबादी को ये प्लाट दिए हैं?

चौधरी सुरजीत सिंह मान : जो इलिजिबल केसिज थे, उनके 82 परसैन्ट को दे दिए गए हैं ।

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : टोटल आबादी की कितनी परसैन्टेज है?

श्री बनारसी दास गुप्त : ये खुद ही निकाल लें, इनके पास सेंसिज रिपोर्ट है, उसमें देख लें कि हरिजनों की आबादी कितनी परसैन्ट दिखाई गई है ।

चौधरी अब्दुर रजाक खां : स्पीकर साहब, देहातों में हर

आदमी को प्लाट दिए गए हैं, क्या मन्त्री साहब बताएंगे कि शहरों में भी हर आदमी को प्लाट देगे?

श्री बनारसी दास गुप्त : इसके बारे में अभी अर्ज किया था ।

Mr. Speaker : The reply has come.

Buses in Sub-Depots of the Haryana Roadways

***1513. Shri Om Parkash Garg** : Will the Minister for Transport **be** pleased to state the total number of buses in each of the Karnal, Ambala, Kaithal and Yamuna-Nagar Depots/Sub-Depots as on 30.11.1975 ?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

करनाल	164
अम्बाला	206
कैथल	136
यमुनानगर	42

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि जो बसें उन्होंने बताई हैं वे किस-किस माडल की कितनी-कितनी बसें हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : आप कौन से डिपो की जानना चाहते हैं?.. (व्यवधान) ये 8 साल से कम की बसें हैं. (व्यवधान

)

श्री ओम प्रकाश गर्ग : मन्त्री महोदया मेरा सवाल नहीं समझीं । मेरा सवाल यह है कि क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि इन डीपोज में किस-किस माडल की कितनी कितनी बसें हैं? मेरा सप्लीमेंटरी यह है, मैंने उनकी टाईप नहीं पूछी ।

श्रीमती प्रसन्नी देवी : करनाल डिपो में एक वर्ष से कम की बसें 22

एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम 28

दो वर्ष से अधिक और 3 वर्ष— से कम 37

तीन वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम 42

चार वर्ष से अधिक ओर 5 वर्ष से कम 16

पांच वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम 19

8 वर्ष से अधिक की करनाल डिपो में कोई बस नहीं ।

कैथल डिपो में 1 वर्ष से कम की बसें 15

एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम 15

दो वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम 32

तीन वर्ष से अधिक और 4 वर्ष. से कम 24

4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम 21

5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम 29, और इसके बाद कोई नहीं ।

अम्बाला डिपो में 1 वर्ष से कम की बसे 37

1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से दाम 18

2 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष से कम 53

3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम 20

1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम 36

5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम 41 और इसके बाद कोई नहीं ।

चौधरी बृज लाल : स्पीकर साहब, मेरा एक सवाल है लेकिन बहु इस सब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं रखता, उम्मीद है मन्त्री महोदया जवाब दे देंगी । मैं पूछना चाहता हूं कि सरला तो डिस्ट्रिक्ट बन गया है लेकिन वहां डिपो नहीं है, क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि वहां डिपो कब बनेगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : इस पर विचार किया जा रहा है, जल्दी ही बना देंगे ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : स्पीकर साहब, यातायात

में बढ़ावा हो रहा है, क्या अधिक बसों की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो क्या मन्त्री महोदया इस तरफ ध्यान देंगी कि बसों की संख्या बढ़ाई जाए?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : हूर साल पुरानी बसें जो कंडम हो जाती हैं, उनको निकाल देते हैं और नई डारन देते हैं । अपनी तरफ से काफी स्वान दिया जाता है और जितनी जनता की जरूरत होती है उसके मुताबिक पूरी कोशिश करते हैं । अब 200 के करीब गाड़ियां और आनी हैं ।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने सब की बात की है लेकिन यमुनानगर की बात नहीं की । क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि वहां कितनी बसें हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : यमुनानगर में डिपो नहीं है, सब-डिपो है । मैं आनरेबल मैम्बर की इत्तलाह के लिए बता देती हूं कि यमुनानगर सब-डिपो में 42 बसें हैं, उन में से 24 तो चार साल से कम की हैं और 18 चार साल से अधिक की हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1526

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी चांद राम, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Residential Quarters for Police Employees

***1533. Lala Rulya Ram :** Will the Chief Minister be

pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct residential quarters for the Police Employees posted in Police Stations situated on the G. T. Road (Ambala-Delhi Road) ;

(b) if so, the time by which the proposal is likely to be materialised ; and

(c) whether the Police Station Gharaunda is covered under the proposal referred to in part (a) above ?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(क) हां ।

(ख) एक वर्ष ।

(ग) हाँ । पुलिस थाना घरौन्डा के पुलिस कर्मचारियों के लिए क्वार्टरज बनाने के लिए आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

लाला रुलिया राम : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि घरौन्डा में कितने क्वार्टर बनाए जा रहे हैं?

श्रीमती शारदा रानी : 1 ए० एस० आई०, 1 हेड कंस्टेबल और 4 कंस्टेबल्ज के बना रहे हैं ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : जहाँ-जहाँ क्वार्टरों की कमी है, क्या वहाँ पर क्वार्टर बनाने की कोई प्रपोजल है?

श्रीमती शारदा रानी : इस साल ऐसा विचार किया गया है कि जहाँ-जहाँ पुलिस स्टेशन हैं और क्वार्टर की कमी है, उनको फेज्ड प्रोग्राम में बनाया जाये ।

लाला रुलिया राम : घरौंडा में 1 3 आदमी (कंस्टेबल) रहते हैं लेकिन क्वार्टर 8 बनाए जा रहे हैं । क्या मन्त्री महोदया उन सब के लिए क्वार्टर बनाने पर विचार करेगी?

श्रीमती शारदा रानी : जो क्वार्टर बनाए जा रहे हैं वे फैमिली क्वार्टर हैं । सब की फैमिली साथ नहीं रहती । बाकिरों के लिए बैरेक होते हैं ।

श्री के० एन० गुलाटी : क्या मन्त्री महोदया फरमायेगी कि फरीदाबाद और बन्लभगढ में जितने पुलिस अधिकारी हैं उन सब के लिए कब क्वार्टर बना दिए जाएंगे?

श्रीमती शारदा रानी : इस विषय में अभी तुरन्त कोई प्रपोजल नहीं है ।

Electricity Connections for Tubewells

***1548. Chaudhri Ram Parshad :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give electricity connections for tubewells to the farmers in Bawal Assembly Constituency ; if so, the time by which the electricity connections are likely to be given ?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar

Harmohinder Singh Chatha) : There is no separate proposal under consideration of Government to give electricity connections for tubewells in Bawal Constituency. However, such connections are being given throughout the State by the State Electricity Board.

चौधरी राम प्रशाद : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि बावल क्षेत्र बहुत बैकवर्ड है और जिला भी बैकवर्ड है, क्या दूसरे डिवैल्पड जिलों की निस्बत इस जिले को ट्यूबवैल कुनैक्शन देने में प्रायरिटी देने का विचार है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा : बावल कांस्टीच्युएंसी रिवाडी डिवीजन में पड़ती है । इस में 2111 टैस्ट रिपोर्टस 3 नवम्बर को पैडिंग थी लेकिन पिछले डेढ़ महीने से कुछ कुनैक्शन दिए गए हैं और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का फैसला है कि जितनी टैस्ट रिपोर्टस पैडिंग हैं, इन में से 65 परसेंट 31 मार्च तक क्लीयर कर देंगे और सारी स्टेट टैस्ट रिपोर्टस दो साल में क्लीयर हो जाएंगी ।

चौधरी रिजक राम : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि ऐसे कितने ट्यूबवैल कुनैक्शन हैं जो एक साल और एक साल से ज्यादा के पैडिंग हैं? क्या हमारी गवर्नमेंट के नोटिस में है कि बहुत से लोगों ने कर्जे लै कर मोटरें लगा रखी हैं और उन को कुनैक्शन न नित्यने की वजह से नुकसान उठाना रहे रहा हे?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा : स्पीकर साहब, यह बात

दुरुस्त है कि कुछ एप्लीकेशनज भी पैन्डिंग हैं और कुछ टैस्ट रिपोर्टस भी पैन्डिंग हैं लेकिन टैस्ट रिपोर्टस जब आती हैं तो कुछ प्रायरिटीज होती हैं । जिनको प्रायरिटीज दी जाती हैं वे हैं आर्मी के आदमी, ऐक्स आर्मीमैन, हरिजन, गवर्नमेंट के ट्यूबवैल्ज जैसे एम ० आई० टी ० सी ० और एस० एफ० डी० यु ० के, या 2500 रुपये जो दे दे या मैटीरियल खरीदकर जो ले आए । दूसरी रिपोर्ट. स नम्बरवार चलेगी और नम्बरदार ही कुनैक्शंज दिए जाएंगे ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : स्पीकर साहब, बावल के बारे में तो मिनिस्टर साहब ने जिक्र कर दिया लेकिन इसी तरह से झज्जर, नाहड और साल्हावास के इलाके की भी बहुत सी ऐप्लीकेशनज और टैस्ट रिपोर्टस पैन्डिंग पड़ी हैं । क्या उनको भी जल्दी से जल्दी कुनैक्शन देने की कोशिश की जाएगी?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा : मैंने अभी-अभी अर्ज किया है कि आने वाले कढ़ाई महीने में तीन हजार और टैस्ट रिपोर्टस को क्लीयर कर दिया जाएगा ।

चौधरी रिजक राम : क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि इस वक्त स्टेट में कितने ऐसे ट्यूबवैल्ज कुनैक्शंज पैबिंग हैं जिनकी टैस्ट रिपोर्टस आ चुकी हैं?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह बड्डा : जिनकी टैस्ट रिपोर्टस 30 नवम्बर, 1975 की आई हुई थीं उनकी संख्या है 8887 और छः

महीने पुरानी 4482 हैं इसके बाद बहुत से कुनैक्शन दे चुके हैं और बाकी के दे दिए जाएंगे ।

मलिक सत राम दास बतरा : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ब्रेकिश वाटर की वजह से जो कुएं नाकारा हो चुके हैं उनकी तारे और खम्भे आदि 'दूसरी जगह प्रयोग किए जाएंगे?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्टा : जहाँ कुए का मालिक कह दे कि मेरे ट्यूबवैल का कुनैक्शन डिसकनेक्ट कर दिया जाए वहाँ के तार और खम्भे दूसरी जगह इस्तेमाल किए जाते हैं ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, कुनैक्शन एक साल या दो साल तक न मिलने की वजह से बैंकों से लिए कर्जे पर फार्मर को बहुत सा सूद देना पडता है । क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि को-आप्रेटिव बैंक के जो कर्जाजात हैं उनका इंट्रैस्ट तब तक जब तक कि फार्मर को कुनैक्शन न मिल जाए, माफ करने के लिए गौर की जाएगी?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, एक रोज पहले भी मैंने यह बात सदन के सामने पूरी तरह स्पष्ट की थी । सरकार के ध्यान में यह बात पूरी तरह है कि काफी जमींदारों ने लैंड मार्गेज बैंक या दूसरे बैंकों से कर्जे लेकर ट्यूबवैल लगाए हैं और उनको आज तक कुनैक्शन नहीं मिले हैं । सरकार बड़ी गम्भीरता के साथ इस बात पर विचार कर रही है कि चारों तरफ से साधन जुटाकर जितनी पैडिंग टैस्ट रिपोर्ट्स हैं उन

सबको कुनैक्शन दे दिए जाएं । हम ए० आर० सी० से लोन जैने की बात कर रहे हैं । इसी तरह से जहां-जहां से भी साधन उपलब्ध होते हैं, वे हम प्राप्त करेंगे और सभी को कुनैक्शन देंगे । अगले साल कोई टेस्ट रिपोर्ट पैडिंग नहीं रहेगी जिसको बिजली का कुनैक्शन नहीं देंगे । (थम्पिंग) जहाँ तक इंटरैस्ट माफ करने की बात है, यह पोसीबल नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक से हमें पैसा मिलता है और हम आगे उसे एडवांस करते हैं ।

Primary School in every Village of the State

***1568. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Education be pleased to state -

(a) whether a Primary School has been opened in every village of the State ;

(b) if not, the district-wise number of villages which are still deprived of such schools ;

(c) the district-wise names of villages where schools are functioning in the name of Branch Primary Schools ; and

(d) whether the number of teachers in the said Branch Schools meet the requirement ?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :
(ए), (बी), (सी) तथा (जी) रू सूचना एकत्रित करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे विशेष लाभ नहीं होगा ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मती महोदया बताएंगी कि प्राइमरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल की ब्रांच में क्या अन्तर होता है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : प्राइमरी स्कूल इंडीपैन्डैन्ट होता है और नार्मज के मुताबिक उस पर पूरा खर्च किया जाता है लेकिन ब्रांच स्कूल किसी भी मन्जुरशुदा स्कूल में से ही होता है । उसमें जरूरत के मुताबिक कुछ टीचर्ज लगा लिए जाते हैं । उसे जरूरत महसूस होने पर या 35 से ज्यादा बच्चे यदि किसी गांव में हो जाएं और पंचायत स्कूल खोलने के लिए जगह दे दे तो पास के एरिया के स्कूल से टीचर लेकर ब्रांच स्कूल खोला जाता है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : अगर वहाँ पर अलग टीचर्ज ने ही पढ़ाना है तो क्या मैली महोदया बताएंगी कि अलग स्कूल खोलने में क्या कोई ज्यादा खर्च पड़ता है?

शिक्षा मन्त्री (श्री माडू सिंह मलिक) : ब्रांच स्कूल तीन जमात तक का होता है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : वह तो पांच तक चल रहा है?

श्री माडू सिंह मलिक : पांच तक कोई ब्रांच स्कूल नहीं चल रहा है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ब्रांच स्कूल में जितने बच्चे होते हैं उनके अनुसार टीचर्ज लगाए जाते हैं?

श्री माडू सिंह मलिक : कोशिश तो यही की जाती है कि उसके मुताबिक हों ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या लगे हुए हैं?

श्री माडू सिंह मलिक : इसके लिए तो नोटिस दे दें, बता देंगे ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि उनको यह बता दिया जाए कि फलां जगह अध्यापक पूरे नहीं हैं, वे उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयत्न करेंगे?

श्री माडू सिंह मलिक : कोशिश करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं ० 1409

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न सं० 1437

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्रश्न सं ० 1467

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य,

चौधरी देवी लाल, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Ghost Ration Cards

***1510. Rao Dalip Singh :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the district-wise number of Ghost Ration Cards detected in the State during the year 1973-74 and 1974-75 to-date ; and

(b) the action taken thereon ?

Excise and Taxation Minister (Shri Shyam Chand)

:

(a) Information is placed on the table of the House as per Annexure 'A'.

(b) The services of one Inspector, two Sub-Inspectors and one Clerk were terminated. The disciplinary action is pending against one Sub-Inspector.

Annexure 'A'

Statement showing ghost ration cards weeded out

Sr. Name of No. district.	No. of cards weeded out.	Number of units reduced.
1. Sirsa	3963	28,009
2, Kurukshetra	2357	19,720

3. Hissar	7079	53,987
4. Narnaul	1964	13,991
5. Rohtak	20,306	1,49,043
6. Ambala	6185	40,466
7. Sonapat	5791	45,614
8. Jind	1804	22,529
9. Karnal	9905	73,520
10. Gurgaon	3898	34,586
11. Bhiwani	4575	26,014
Total:—	67,827	5,07,479

राव दलीप सिंह : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने बताया कि सारी स्टेट में 67, 827 राशन कार्डज ऐसे मिले हैं जो बोगस थे, घोस्ट थे । यह बहुत बड़ी तादाद है । क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने उन अफसरान के खिलाफ कोई खास कदम उठाए हैं जिन्होंने बोगस राशन कार्डज बनाए थे?

Shri Shyam Chand : Sir, actually the Officers of the Department are not involved. It was the practice previously that on the advice or attestation of the Sarpanches of the Villages, the ration cards were issued.

राव दलीप सिंह : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन

सरपंचों ने गलत राशन कार्ड अटैस्ट किए हैं और ऐसा करके समाज के खिलाफ बड़ा भारी जुर्म किया है, उनके खिलाफ ऐक्शन लैने के लिए कोई कमेटी बनाई गई है या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है?

Shri Shyam Chand : Sir, the magnitude of the problem is so great that it will not be possible to prosecute every Sarpanch.

चौधरी मेहर चन्द : मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि इंकवायरी पैन्डिंग है । क्या वे यह बताएंगे कि डिस्पलनरी ऐक्शन कब से पैन्डिंग है और कितने असे में फाइनेलाइज हो जाएगा?

Shri Shyam Chand : The enquiry is being conducted and, as early as possible, it will be finalised.

श्री जगजीत सिंह टिक्का : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि देहात में सरपंचों ने फार्म अटैस्ट किए थे । क्या वे बताएंगे कि शहरों में, जैसा कि अम्बाला कौन्ट है, राशन कार्ड फार्म किसने अटैस्ट किए थे और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी?

Shri Shyam Chand : Sir, it is the Municipal Commissioners and the M.L.As.

Buses from Indri and Ladwa

***1514. Shri Om Parkash Garg** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) the number of buses which start daily from

Indri and Ladwa

alongwith the places of their destination and

(b) the names of the places of their stoppage which fall on their routes and whether such buses are running in profit or loss ?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :
वांछित सूचना "स्टेटमेंट" के रूप में,— सदन के पटल पर रखी जाती है ।

स्टेटमेंट

(क) 1. इन्दरी से देहली ।

2. लाडवा से करनाल ।

3. लाडवा से शाहबाद ।

4. लाडवा से कुरुक्षेत्र ।

(ख) 1. इन्दरी से देहली बस सेवा में बस स्टाप निम्नलिखित हैं :—

इन्दरी, न्योरता, जनेसरू, समौरा, राम्बा, कुराली, सलारू, करनाल, एच ० ए ० पी० मधुवन, धरौंडा, पानीपत, समालखा, गन्नौर, मूर्थल, बहालगढ, अलीपुर, देहली वार्डर, और देहली । यह सेवा लाभ में चल रही है ।

2. लाडवा करनाल बस सेवा में बस स्टाप निम्नलिखित हैं रू—

लाडवा, खानपुर, इन्दरी, न्योरता, जनेसरी, सुमौरा, राम्बा, कुराली, सलाख और करनाल । यह बस सेवा लाभ में चल रही है ।

3. लाडवा शाहबाद बस सेवा के बस स्टाप निम्नलिखित प्रकार हैं :-

लाडवा, वलोलपुर, वहरू, बवैन, सूरजा, खारेण्डवा, डीग और शाहबाद । यह बस सेवा लाभ में चल रही है ।

4. लाडवा-कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बस सेवा के बस स्टाप निम्नलिखित हैं रू— लाडवा, सोन्टी, मथना गेट, पीपली, कुरुक्षेत्र, बिडला मन्दिर और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय । यह बस सेवा लाभ में नहीं चल रही है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मंत्री महोदया को इल्म है कि लाडवा से जो बस करनाल को जाती है वह सीधी न जाकर के इन्दरी कांस्टिच्यूएंसी के दो गांव गोलगढ और बीबीपुर होते हुए जाती है और एक घंटे की बजाय दो घंटे में वहां पहुंचती है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, गोलगढ मेन रोड पर आता ही नहीं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : मेरा सप्लीमेंटरी भी सीकर साहब

यही है कि वह मेन रोड पर नहीं आता और इन्दरी कांस्ट्रिक्ट्यूएन्सी में आता है । बोर्ड तो बस पर लाडवा से करनाल लगा हुआ होता है लेकिन बस गोलगढ और बीबीपुर होकर जाती है । सवारी तो सोचती है कि वह सीधी करनाल जाएगी और एक घंटे में पहुंच जाएगी लेकिन वह पहुंचती है दो घंटे में । क्या यह बात मिनिस्टर साहिबा के नोटिस में है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : स्पीकर साहब, छोटे रूट पर नजदीक के छोटे-छोटे गांव को कवर करना पड़ता है ।

श्री अध्यक्ष : इतनी छोटी सी बात का तो इन्दरी में बैठकर हल निकल सकता है । (हंसी)

श्री ओम प्रकाश गर्ग : मंत्री महोदया ने अभी फरमाया कि छोटे-छोटे गांव ऐडजस्ट करने पड़ते हैं । क्या वे बताने की कृपा करेंगी कि अगर ऐसे छोटे-छोटे गांव में और बता दू तो वे उन्हें ऐडजस्ट करेगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी : पूरी कोशिश करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं० 1527

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि माननीय सदस्य, चौधरी चांद राम, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Common Facility Workshop

***1534. Lela Rulya Ram :** Will the Minister for

Agriculture be pleased to state —

(a) the total expenditure incurred by the Government for setting up Common Facility Workshop at Village Kairon, Tahsil and District Karnal;

(b) the expenditure incurred on the said Facility Workshop for the years 1973-74 and 1974-75 ; and

(c) the profit earned and loss suffered, if any, by the said Workshop during the years, 1973-74 and 1974-75 ?

State Minister for Development and Local Government (Chaudhri Gordhan Dass Chauhan) ; (a) Rs. 52,000.00

(b) Expenditure	1973-74	1974-75
	Rs. 15,476.14	Rs. 15,399.71

(c) The question of profit and loss does not arise as the Common Facility Workshop is a service centre for rural people.

Drinking Water Supply Schemes

***1549. Chaudhri Ram Parshad :** Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) the date by which the following drinking water supply schemes are likely to be completed :—

- (i) Jarthal Scheme ;
- (ii) Jabhwa Scheme ;
- (iii) Pranpura Scheme ; and

(b) whether there is any scheme under consideration of the Government to provide sweet water to the following villages of the Bawal Assembly Constituency :—

Bharas, Bithwana, Kamalpur, Karanwas, Deodhi, Lalpur, Sulka, Nanwalka, Budhrana, Bandhor, Anuka, Dahaki, Goliaki, Dhuryaki, Rajyaki, Naglighoda, Toothwalka, Damlawas, Pithrawas, Mehlawas, Gumina, Harjipur, Hussainpur, Narainpur, Sundroj, Rajpura, Paligothra, Mamrka, Pranpura and Chaimnawas ?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(क) (1) जारथल स्कीम - कोई तिथि नहीं बतलाई जा सकती ।

(2) झाबवा स्कीम - कोई तिथि नहीं बतलाई जा सकती ।

(3) परानपुरा स्कीम - परानपुरा की कोई अलग स्कीम नहीं है । गांव परानपुरा मोरी ग्रुप में शामिल है । पूर्ण होने की कोई तिथि नहीं बतलाई जा सकती ।

(ख) हां जी । गांव लालपुर तथा तीन ढानीक, बनवालका, अनुका और धुरिया की को छोड़कर ।

चौधरी राम प्रशाद : क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि लगाने की तो काई बात नहीं है लेकिन इन गांवों में इतना खारा पानी है कि लोग पी नहीं सकते, क्या इन गांवों को प्रायरिटी दी

जाएगी? वैसे भी ये राजपूतों के गांव हैं ।

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, न लगाने की तो कोई बात कही नहीं, लगाने की बात कहा है जिसमें केवल दो चार ढानीज शामिल नहीं हैं, उनको भी शामिल कर लिया जायेगा । जहां तक इनकी बावल कांस्टीच्यूंसी का सवाल है इसमें 145 गांव हैं जिनमें 9 गांवों की स्कीम पूरी हो चुकी है, पांच अन्डर प्रोग्रैस हैं और बाकी 126 गांवों की स्कीम प्रिपेयर कर ली है, अन्डर प्रौसैस है । पांच गांवों की स्कीम बनायी जा रही है । कोई भी इनका गांव छोड़ा नहीं है ।

चौधरी राम 'प्रशाद : क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि प्राणपुरा की जो स्कीम बनायी है वहां पर ट्यूबवैल लगा दिया गया, चौधरी बसी लाल जी के टाईम पर लगाया गया था लेकिन उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है, क्या भली जी उसकी तरफ ध्यान देंगे? मेरे ख्याल में जो ये बता रहे हैं कागजों पर ही यह प्लान है ।

Mr. Speaker : Put a supplementary. It is not a question.

चौधरी कूल सिंह कटारिया : मंत्री महोदया ने बावल कांस्टीस्यूंसी का बता दिया तो क्या झज्जर और साहलावास कांस्टीच्यूंसी में कई स्कीमें पैन्डिंग हैं उनकी तरफ भी सरकार गौर करेगी और उनको कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

Mr. Speaker : Order Please कई स्कीमो नाम क्या है ?
hypothetical question and not a supplementary one.

श्रीमती लेखवती जैन : क्या मंत्री महोदया से मैं यह पूछ सकती हूँ कि जहां पर देहातों में मीठा पानी दिया जा रहा है वहां शहरों में भी मीठा पानी देने का प्रबन्ध किया जायेगा? जैसे कि हमारे यहां अम्बाला शहर में खारी पानी है?

श्री अध्यक्ष : बहिन जी, यह सप्लीमेंटरी नहीं बनता ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : क्या मंत्री महोदया के ध्यान में है कि हमारे साबका चीफ मिनिस्टर साहब चीमनी वाटर वर्क. स का एलान करके आये थे लंकिन वह काम आज तक शुरू नहीं हुआ ? उसका पूरा कब कर दिया जायेगा?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय एलान करके आये थे तो जरूर उसके ऊपर काम किया जायेगा ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि नीलोखेडी में अमीन गांव है, जो बहुत ही ऊंचे पर बसा हुआ है, बरसात के दिनों में वहां पर पानी ले कर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तथा वहां पर भी पानी का कोई प्रबन्ध किया जायेगा?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, यह क्वेश्चन तो बावल कांस्टीच्यूसी के बारे में है । अगर और गांवों के बारे में पूछना चाहते हैं तो अलग से नोटिस दें ।

राव अभय सिंह : क्या मंत्री महोदया बतायेगी कि जडथल स्कीम कब सैकशन हुई थी और कितना रुपया मंजूर हुआ है?

श्रीमती शारदा रानी : अध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सन 1975 में हुई थी । इसके लिए एक लाख 61 हजार रुपया दे दिया गया है ।

Electricity for Agricultural Purpose.

***1569. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the electricity is being supplied for agricultural purposes in the State for the whole day ;

(b) the number of hours per day for which electricity was supplied for agricultural purposes to the tubewells in the month of December, 1975 ;

(c) whether any cut has been imposed on the supply of electricity; and

(d) if so, the reasons for the cut, if any, imposed on the supply of electricity to the Agricultural tubewells togetherwith the quantity of cut being imposed Circle-wise ?

State Minister for Irrigation & Power (Sardar Harmohinder **Singh** Chatha) : a, b, c, & d : A statement containing the requisite information is laid on the table of the House.

Statement

(a) No.

(b) 1.12.75 to 15.12.75 : 24 hours daily.

16.12.75 to 31.12.75 : 12 to 18 hours daily.

(c) Some staggering of rural loads has been resorted to.

(d) The reasons which led to the staggering of loads after 15.12.75 were as under :-

(i) Reduction in power generation at the Bhakra Nangal Complex in order to conserve water for irrigation needs in February, March and April ;

(ii) Frequent outages at the Badarpur Thermal Power Station ;

(iii) As a consequence of (i) and (ii) above, low voltage conditions in the System, particularly during day time ;

The information regarding circle-wise supply to tubewells is as under:—

Sr. Circle No.	Supply to agriculture tubewells.
1 . Chandigarh	10 to 12 hours daily.
2 . Karnal	—do—

- 3 . Rohtak (i) 10 to 12 hours daily in case of Rohtak and Jind division.
(ii) 8 to 10 hours daily in case of Jhajjar, Dadri and Narnaul division.
- 4 . Hissar (i) 10 to 12 hours daily in all divisions except Bhiwani.
(ii) 8 to 10 hours daily in case of Bhiwani Division.
- 5 . Delhi (i) 10 to 12 hours daily in all divisions except Rewari division.
(ii) 8 to 10 hours daily in case of Rewari Division.
- 6 . Faridabad 10 to 12 hours daily.

चौधरी शिव राज वर्मा : मंत्री महोदय नें बताया है कि 10- 12 घन्टे के हिसाब से बिजली दी जा रही है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अभी तक बरसात नहीं हुई है और फसल को पानी

की जरूरत है तो कहीं पर ज्यादा टाईम तक बिजली देने का प्रबन्ध करेंगे?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्टा : स्पीकर साहब । कल हमारे यहां ऐसा कोई कट नहीं हुआ । बदरपुर से भी बिजली आ रही है, थर्मल प्लांट भी चल गया है । आज हमारे पास इन्फर्मेशन है कि जो हमारा थर्मल प्लांट खराब था वह भी ठीक चल रहा है । हमारे यहां कोई कट नहीं है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो खेतों को पानी देने वाले ट्यूबवैल्ज हैं उनको दिन में बिजली देने का विचार है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्टा : स्पीकर साहब, इससे पहले भी सवाल आया था उसका भी मैंने जवाब दिया था कि यह मुश्किल है कि सारे ट्यूबवैल्ज को दिन में बिजली दी जाये, कुछ को रात को भी दी जाती है । हमने हमेशा ख्याल रखा है कि जब भी बिजली में कमी आयी है हमने एग्रीकलचरिस्ट को बिजली की कमी नहीं होने दी ।

मलिक सतराम दास बतरा : मंत्री महोदय ने बताया है कि पावर कट नहीं होता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि एवरेज कितने घन्टे बिजली दी जाती है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्टा : 15 सितम्बर से इस सूबे में कोई पावर कट नहीं था । एवरेज 6 से सात घन्टे तक

ट्यूबवैल्ज को बिजली दी जाती है । बारिश ज्यादा होने पर तो कम हो जाती है लेकिन एवरेज छः और सात घंटे के बीच में है ।

चौधरी रिजक राम : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जैसे दिन में और रातको ट्यूबवैल्ज को बिजली दी जाती है, उसके लिए कोई छुरिया सैप्सीफायी किया हुआ है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्टा : सारे एरियाज को हिसाब से दी जाती है । बैकवर्ड एरिया के हिसाब से या दूसरे एरियाज के हिसाब से बिजली दी जाती है । कभी किसी एरिया में दिन के वक्त भी बिजली दी जाती है । आलू वाले एरिया का खासतौर से ख्याल रखा जाता है क्योंकि आलू में पानी रात को नहीं दे सकते । उनको दिन में बिजली दी जाती है ।

लाला रुलिया राम : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे जैसा कि उन्होंने कहा कि कल कट नहीं हुआ । मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूं कि परसों बिजली में कट था कल से बिजली ठीक चल रही है । यह कट बन्द होना चाहिए?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री निहाल सिंह : स्पीकर साहब दिनऔर रात का बड़ा झगड़ा रहा है । तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब आप 12 घण्टे बिजली देते हैं तो वहां 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक देने की कृपा करेंगे?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्टा : स्पीकर साहब, इनकी दिन और रात की बात नहीं है । इनका तो 12 बजे से ताल्लुक है । (हंसी)

चौधरी रिजक राम : सोनीपत और पानीपत के एरिया में इस साल में या इससे पिछले साल कितने अर्से के लिए दिन में ट्यूबवैल्ज को बिजली दी गई?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्टा : यह तो बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए तो सैपरेट नोटिस चाहिए ।

Mr. Speaker : Yes, it is not a supplementary.

चौधरी रिजक राम : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस साल में कभी एक दिन के लिए दिन में बिजली दी गई?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्टा: जी हां कल दी है ।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जब भी पावर कट लगता है तो अम्बाला जिले के किसानों को रात को ही बिजली दी जाती है सारे जमींदारों को एक जैसा टूटि क्यों नहीं किया जाता है?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

राव बंसी सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि बैकवर्ड एरिया में कितने घन्टे बिजली दी जाती है? दिन के टाइम कितने घन्टे दी जाती है और रात के टाइम कितने घन्टे दी जाती है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा : दस या बारह घन्टे देते हैं । मैंने अभी बताया है कि पहले दिक्कत थी, अब दिक्कत नहीं है । इसी तरह से थर्मल प्लांट चलता रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगी ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो सुझाव राव निहाल सिंह ने दिया कि दिन के बारह बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जमींदारों को बिजली दी जायेगी क्योंकि इससे काफी सुविधा हो जायेगी?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : स्पीकर साहब कुछ इलाकों में ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि रात के बारह बजे से दिन के बारह बजे तक बिजली दी जाये ।

चौधरी मनफूल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो पावर कट लगाते हैं उसको रिलीज करने की कौन कम्पीटेन्ट अथोरिटी है?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा : इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ।

मलिक सतराम दास बतरा : क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो बिजली में फलकचुएशन होती है उससे कितनी ही लाइने कमजोर हो गई हैं, ऐसा होने से मोटर जलने का डर होता है, उसके लिए क्या उपाय किये हैं?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा : स्पीकर साहब जहां

जहां लाइने ढीली होती हैं और जल्दी बिजली के हमने गांवों में कुनैक्शन दिये हैं वहां वहां पर लाइनों को बिजली बोर्ड मजबूत करता जाता है ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि अब 10-12 घन्टे ट्यूबवैल्ज को बिजली दी जाती है तो क्या फरवरी के महीने में कनक को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, इस महीने में भी बराबर पानी मिलता रहेगा?

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा : फरवरी, मार्च और सात अप्रैल तक भाखडा मैनेजमेंट बोर्ड ने भी पानी रिलीज करने के लिए कहा है और बिजली भी ज्यादा पैदा करेगा । बिजली ज्यादा पैदा होगी तो जमींदारों को ज्यादा मिलेगी ।

चौधरी मनफूल सिंह : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि कहीं पर तो एक्स० ई० एन० यह कहता है कि कट मैंने करना है और कहीं वह कहता है कि कट बोर्ड करता है? मैं यह जानना चाहता हं कि इन दोनों में से कौन सी बात दरुस्त है

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा : एक्स० ई० एन० भी बोर्ड का एक पार्ट है लेकिन अल्टीमेट फ़ैसला इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड करता है ।

(इस समय चौधरी बंसी लाल जी ने सदन में प्रवेश किया ।) (थम्पिंग)

श्री हरि सिंह : मंत्री महोदय ने एक तरफ तो यह बताया कि 10— 12 घंटे डेली बिजली दी जाती है और दूसरी तरफ फरमाया है कि एक जमींदार को 6 घंटे एवरेज बिजली की जरूरत है, इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है और अगर 6 घंटे वाली बात ठीक है तो क्या वे 8 घंटे बिजली जमींदार को दिन में देकर बाकी के 4 घंटे किसी और काम में इस्तेमाल करने की कृपा करेंगे

सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ढा : बातें तो दोनों ठीक हैं लेकिन नलवा साहब की सोच ठीक नहीं । जो 12 घंटे' बिजली देते हैं, उसमें यह बात नहीं कि डेढ़ लाख ट्यूबवैल एक दफा ही चलते हैं । एक जमींदार एक टाईम चलाता है तो दूसरा दूसरे टाईम चलाता है लेकिन जो एवरेज कन्जम्पशन है वह 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक है, और 8 घंटे से ऊपर कभी एवरेज नहीं आयी ।

Mr. Speaker : The Question Hour is over.

ताराकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Requirement of Electricity for Agricultural and Industries purposes.

***1408. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Irrigation **and Power** be pleased to state—

(a) the total number of electricity units required in the State for Agriculture and Industries , separately , during the month of January, 1975 ; and

(b) the total number of electricity units supplied for Agriculture and Industries, separately, during the period as referred to in part (a) above ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) :

(क) जनवरी 1975 में कृषि और उद्योगों के लिये बिजली की पृथक-पृथक आवश्यकता निम्नलिखित थी :-

(1) कृषि के लिये 35 लाख यूनिट प्रति दिन

(2) उद्योगों के लिये 34 लाख यूनिट प्रति दिन

(ख) जनवरी 1975 में कृषि और उद्योगों के लिये दी गई बिजली का विवरण इस प्रकार है :--

(1) कृषि के लिये 17. 5 लाख यूनिट प्रति दिन

(2) उद्योगों के लिये 14. 5 लाख यूनिट प्रति दिन

Culpable Homicides committed in the State

***1436. Chaudhri Dal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the district-wise total number of culpable Homicides committed in the State during the years 1973-74 and 1974-75, separately ;

(b) the number of cases referred to in part (a) above in which challans were presented in the courts; and

(c) the number of such cases in which accused

were convicted ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : (क), (ख) और (ग) मांगी गई सूचना से सम्बन्धित विवरण सदन में प्रस्तुत है ।

विवरण

जिला	(क)		(ख)		(ग)	
	विवरण	वर्ष 1973-74 और 1974-75 में राज्य में सदोष मानव वध के मामलों का जिलेवार	भाग 'क' में सन्दर्भित मामलों में से जितने चालान हुए	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषियों को सजा मिली	1973-74	1974-75
हिसार	17	20	16	20	8	1
रोहतक	7	9	5	9	1	2
गुड़गांव	17	18	16	17	--	--
करनाल	7	3	7	3	2	-
अम्बाला	1	11	1	10	1	1
नारनौल	1	2	--	2	--	1

जीन्द	3	2	3	2	-	1
भिवानी	9	9	9	9	6	5
सोनीपत	2	5	2	5	--	--
कुरुक्षेत्र	10	3	10	3	5	-
जोड़	74	82	69	80	23	11

Elections to Gram Panchayats

***1456. Chaudhri Devi Lal :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state -

(a) the district-wise total number of Panchayats in the State to which elections are over-due together with the date since when the elections are due; and

(b) the reasons for delay, if any, for the said elections ?

कृषी मंत्री (कर्नल महा सिंह) :

(ए तथा बी) अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में सदन की मेज पर रखी जाती है ।

(ए) विवरण

जिले का	पंचायतों	जिस तारीख से चुनाव डियू है
नाम	की कुल	

संख्या
जिन के
चुनाव
ओवर
डियू है ।

सोनीपत	शून्य	शून्य
हिसार	शून्य	शून्य
रोहतक	शून्य	शून्य
करनाल	शून्य	शून्य
भिवानी	3	5— 11— 75, 11— 4—75 तथा 16— 12— 74
जीन्द	शून्य	शून्य
सिरसा	शून्य	शून्य
महेन्द्रगढ़	शून्य	शून्य
कुरुक्षेत्र	शून्य	शून्य
गुडगावां	शून्य	शून्य
अम्बाला	शून्य	शून्य

(बी) नवीनतम मतदाता सूचियां न होने के कारण ।

Incomplete Roads in Babain Assembly Constituency.

***1526. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of roads which still remain incomplete alongwith the names of the villages which have no link roads in Babain Assembly Constituency of Kurukshetra District ; and

(b) the time by which incomplete roads are expected to be completed and link roads provided to the remaining villages in the said Constituency ?

राजस्व मन्त्री (पंडित चिरन्जी लाल शर्मा) :

(ए) अनुबन्ध 1 तथा 2 पर दी विवरणी सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(बी) कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह पुर्णतः धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

अनुबन्ध 1

सड़कें जो अभी तक अधूरी पड़ी हैं और जो गांव इन सड़कों द्वारा जोड़ने बाकी रहते हैं के नामों को दर्शाती हुई

विवरणी ।

क्रमांक	सडक का नाम	गांवों के नाम जो इन सडकों द्वारा जोड़े जाने रहते हैं ।	रिमार्कस
1	2	3	4
1	जी. टी. सडक से गांव अहमद पुर	हिवाबा, अहमदपुर	
2	गांव धानू पूरा की अप्रोच सडक	अमलोहा तथा धानुपुरा	
3	गांव बैन्दी की अप्रोच सडक	खजूरी तथा बैन्दी	
4	गांव खिरकी ब्राहमना की अप्रोच सडक	पूरन गढ़ तथा खिरकी वाहमन	
5	मदन पुर थानेसर आगा सडक से ब्रहाम तक कतलाहेडी तथा अटवान को सम्पर्क सहित (रडौर ब्लाक का भाग)	हरिपुर काबलहरी अटवान तथा वरहम	

6	लक्सी वास वरास्ता-रशन की अप्रोच सड़क	वरशान तथा लक्खी वास
7	राडार खेड़ी लखा सड़क से सिवाय डबल लिंग	नागल मनसूर पुर तथा वसन्त पुर
8	गांव भगू माजरा की अप्रोच सड़क	मसाना जाट तथा भागू माजरा
9	गांव गन्दरोली की अप्रोच सड़क	भगवान गढ़, भगवान पुर, रापडी, फतेहगढ़ राजहेडी तथा गन्दरोली
10	गांव मेवा खेडी की अप्रोच सड़क	वरखाल, नखराजपुर, तथा मेवाखेडी
11	मुस्तफावाद से गजलाना	भागपुर तथा गजलाना
12	गांव जन्डौला की अप्रोच सड़क (रडौर ब्लाक)	भूखरी तथा जन्डौला
13	गांव वीर भरतौली की	वीर भरतौली

अप्रोच सड़क

- | | | |
|----|---|---|
| 14 | गांव वीर छपार की
अप्रोच सड़क | वीर छपार |
| 15 | अकाल गढ़ वबैन
सड़क बरास्ता सुनैरिया
(सिवाय तीन
किलोमीटर के डबल
लिंक) | मंगोली, राना रान,
घनानी शीम पलवाल
तथा सुनैरिया |
| 16 | यारा से गांव वीरथाला
तथा वीरथाली | वीरथाला तथा
वीरथाली |
| 17 | एसएल. सड़क से
छपरा तथा छपरी | छपरी तथा छपरा |
| 18 | लाडवा गजलाना सड़क
से गांव घलौर छपरा | घलौर तथा छपरा |
| 19 | गांव छारी की अप्रोच
सड़क | छारी |
| 20 | लाडवा गजलाना सड़क
(रडौर ब्लॉक में) | रडौर ब्लॉक में पड़ने
वाले भाग पर कोई
गांव नहीं पड़ता है |

- | | | |
|----|---|--------------------------------------|
| 21 | नांव कलेसरा की
अप्रोच सड़क | दोली तथा कलेसरा |
| 22 | साहब पुर की अप्रोच
सड़क | गढ़ी तथा साहब पुर |
| 23 | अकालगढ बबैन सड़क
बरास्ता संघौर | घीसर पुरी, संघौर तथा
मांगली जाटां |
| 24 | थानेसर आसा सड़क
से सराय सूखी (रडौर
ब्लाक) | सराय सूखी |
| 25 | मुस्तफा बाद गजलाना
सड़क से मोदी यानी | गोन्दीयाना तथा गोन्दी
यानी |
| 26 | रडौर जथलाना सड़क
से गांव हाला हर | पाला वाला, करतारपुर
तथा हालाहार |
| 27 | रदौर खेडी लखा सिंह
से हीरन छपार | दौलतपुर तथा
हीरनछपार |
| 28 | गांव हौदिया की अप्रोच
सड़क | हौदिया |
| 29 | मुस्तफाबाद गजलाना
सड़क से मोहमत पुररु | जमालपुर तथा मुहम्मत
पुर |

- 30 मुस्तफाबाद गजलाना झीवरहेडी
सड़क से झीवर हेडी
- 31 एस.एल. सड़क से गांव बीरसुजरा, बीरमुजरी
मोरथाला तथा कलाल माजरा
- 32 थसका खादर की खुर्दवन तथा थसका
अप्रोच सड़क खादर
- 33 लखमरी की अप्रोच लखमरी
सड़क
- 34 रदौर जथलाना से मधुवास तथा मंधार
मधुवास
- 35 गांव अनहेरी बरास्ता मारुपुर तथा अनहेरी
मारुपुर की अप्रोच
सड़क
- 36 मुस्तफाबाद से खेडी मसाना रांगरान
लखा सिंह
- 37 रदौर जथलाना सड़क नाचरौन
से गांव नाचरौन
- 38 बकाना से गांव पालाका
पालाका

- 39 फलसन्दा रागरान की फलसन्दा रागरान
अप्रोच सड़क
- 40 अकालगढ बबैन सड़क फलसन्दा जाटां
बरास्ता संघोर से गांव
फलसन्दा जाटां
- 41 मुस्तफाबाद गजत्नाना रामगढ
सड़क से गांव रामगढ
- 42 गांव राम सरन का रामसरन का माजरा
माजरा की अप्रोच
सड़क
- 43 गुंरथाला सेराव राव
- 44 रदौर जथलाना से रतनगढ
गांव रतनगढू
- 45 मुस्तफाबाद खेडी लखा सदगौली
सिंह से सदगौली
- 46 हरतान से गांव सिकन्दरा
सिकन्दरा तक अप्रोच
सड़क
- 47 गांव सिली खुर्द की सिलीखुर्द

	अप्रोच सड़क	
48	एस०के० सड़क से गांव सूरा	सरा
49	गांव हरि सिंह का माजरा की अप्रोच सड़क	हरि सिंह का माजरा
50	रदौरखेडी लखा सिंह से गांव हरतान	अटवान माजरी तथा हरतान

अनुबन्ध 2

गांव जिनके लिये लिंक सड़क बनानी अभी आरम्भ नहीं हुई है के नामदर्शाती हुई विवरणी

क्रमांक	गांव का नाम	रिमार्कस
1	काबुलपुर	
2	सिली कलां	
3	वीरवाल सूहा	
4	वालसूहा	

Posts of J.B.T. and B.Ed. Teachers.

***1409. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the

Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of posts of J.B.T. and B.Ed. Teachers referred to the Subordinate Services Selection Board Haryana for selection during the years 1973-74, 1974-75 and 1975-76 (to-date) separately;

(b) the total number of persons recommended by the Subordinate Services Selection Board for the posts referred to in part (a) above ; and

(c) whether all recommended persons as referred to in part (b) above have been absorbed in service, if not, the reasons therefor?

शिक्षा मन्त्री (श्री माडू सिंह मलिक) :

(ए)	वर्ष	जे० बी०	
		टी०	बी० एड०
	1973—74	शून्य	शून्य
	1974—75	शून्य	शून्य
	1975—76	शून्य	1101
(बी)	1973—74	शून्य	शून्य
	1974—75	शून्य	शून्य
	1975—78	शून्य	शून्य

प्रश्न उत्पन्न नहीं
(सी) होता ।

Class I, II, III and IV Employees in the State

***1437. Chaudhri Dal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of Class I, II, III and IV Government Employees in the State as on 31-3-74 and 31-3-75, respectively; and

(b) the number of Class I, II, III and IV Government Employees out of those referred to in part (a) above, who belong to the Scheduled Castes and Backward Classes, separately ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द) : (ए)
31- 3- 74 की स्थिति के अनुसार ।

क्र. सं.	कर्मचारियों की संख्या	श्रेणी I	श्रेणी II	श्रेणी III	श्रेणी IV
1	कर्मचारियों की कुल संख्या	891	3230	100655	25373
31-3-75 की स्थिति के अनुसार ।					
2	कर्मचारियों की कुल संख्या	942	3389	108904	26768

(बी) 31-3-74 की स्थिति के अनुसार

(I) अनुसूचित जाति के

1 कर्मचारी	27	82	8,457	8557
------------	----	----	-------	------

(II) पिछड़े वर्ग के कर्मचारी	2	27	4585	2591
--------------------------------	---	----	------	------

31-3- 75 की स्थिति के अनुसार

(I) अनुसूचित जाति के

2 कर्मचारी	31	99	8773	7481
------------	----	----	------	------

(II) पिछड़े वर्ग के कर्मचारी	2	23	4925	2684
--------------------------------	---	----	------	------

Remission of Sentences in the Jails of Haryana

***1467. Chaudhri Devi Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of life prisoners and other prisoners, separately, who have been given remission by the Government, and the Inspector General of Prisons, separately, during the years 1974 and 1975 (to-date) together with the names of prisoners and the period of remission given to them, separately ?

Transport Minister (Shri K.L. Poswal) : The following number of life/other prisoners were awarded special remission in Haryana Jails during:—

	1974		1975
	Lifers	Others	Lifers
Others			

(i) By Government - — —

(ii) By Inspector 27 30 —

General of

Prisons, (lists attached)

Haryana.

List I

List of lifer prisoners who were granted special remission by Inspector General of Prisons, Haryana during the year, 1974

Sr. No.	Name & Father's Name.	Days of remission sanctioned
1.	Chahat Khan s/o Pir Khan.	10
2.	Chander Parkash s/o Garth Dass.	2
3.	Chander Singh s/o Bhim Singh.	1
4.	Dharam Singh s/o Gian Singh.	8
5.	Dindar s/o Sumer Khan.	2
6.	Hari Singh s/o Ram Singh.	10

7.	Harbhajan Singh s/o Sher Singh.	2
8.	Jagtar Singh s/o Shingara Singh.	5
9.	Ishwar Singh s/o Rakhle Ram.	1
10	Jawahar s/o Kultara .	1
11.	Kishan Lal s/o Basanta	25
12.	Kapur Singh s/o Rishala.	8
13.	Mangal Singh s/o Panjab Singh,	1
14.	Mehnga s/o Sagar Ram.	6
15.	Mukhtiar Singh s/o Ram Singh.	2
16.	Prabhu s/o Dharma.	2
17.	Dalip s/o Chuni.	28
18.	Mithu Singh s/o Pohla.	40
19.	Balwant Singh s/o Ram Sarup.	36
20.	Ashok s/o Net Ram.	32
21.	Partap s/o Udmi.	24

22.	Jagtar Singh s/o Singhara Singh.	28
23.	Banwari s/o Bhartu.	20
24.	Mohan Lal s/o Dewan Chand.	20
25.	Om Parkash s/o Dalip Singh.	20
26.	Teja Singh S/o Tehal Singh.	20
27.	Badan Singh s/o Amar Singh.	20

List II

List of lifer prisoners who were granted special remission by Inspector General of Prisons, Haryana during the year, 1974

Sr. No.	Name of Prisoner	Days of remission
1 .	Rain Kishan s/o Gobinda.	40
2 .	Basakhi s/o Kishna.	36
3 .	Sant Singh s/oGurmukh	36

Singh.

4	Jas Ram s/o Har Bhaj.	44
5.	Ram Niwas s/o Bhagat Ram.	16
6.	Jasbir Singh s/o Hari Singh.	32
7.	Jit Singh s/o Rur Singh.	32
8.	Bhup Singh s/o Chandgi Ram.	16
9.	Ram Singh s/o Des Raj.	28
10.	Jogpal s/o Mulakh Raj.	36
II.	Ram Kishan s/o Harbhaj.	16
12.	Tara Singh s/o Sant Singh.	24
13.	Sheo Karan s/o Sheo Nath.	12
14.	Dalip Singh s/o Hazara Singh.	16
15.	Balbir Singh s/o Ram Singh.	16
16.	Kartar Singh s/o Biru.	12
17.	Swaran Singh s/o Gurbachan Singh.	24

18.	Prem s/o Maman.	20
19.	Chatra s/o Sarupa.	20
20.	Suraj Bhan s/o Chatra.	12
21.	Pritam Singh s/o Mohan Singh.	28
22.	Gettarpal Singh s/o Saroka.	30
23.	Bal Mukand s/o. Mangat.	25
24.	Maman s/o Hari Singh.	30
25.	Raghbir S/o Mam Raj.	20
26.	Gulab S/o Mahabir.	40
27.	Ram Kumar s/o Sunda.	30
28.	Rattan s/o Sis Ram.	15
29.	Sada Singh s/o Chander Singh.	55
30.	Siri Ram s/o Hukma.	30

Allotment of Evacuee Lands

***1527. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of evacuee unallotted land that

came to the share of Haryana on the reorganisation of Punjab ;

(b) the total area out of the said land that was auctioned amongst members of the Scheduled castes and to persons other than Scheduled Castes in each district year-wise after formation of Haryana; and

(c) the total area of land that still remains to be auctioned tehsilwise ?

राजस्य मंत्री (पण्डित चिरन्जी लाल शर्मा) :

(ए) निम्नलिखित भूमि पंजाब पुनर्गठन के समय :- 11-1966 को हरियाणा राज्य के हिस्से में आई -

कृषि योग्य	9559 स्टैडर्ड एकड़
बंजर	7627 साधारण एकड़
गैर मुमकिन	4578 साधारण एकड़

(बी) जो भूमि पंजाब पुनर्गठन के समय हरियाणा राज्य के हिस्से में 1-11-1966 को आई तथा वह भूमि जो उस समय के पश्चात अब तक बरामद की गई उस सारी भूमि में से हरिजनों तथा गैर हरिजनों को 31-10-1975 तक निम्नलिखित भूमि बेची गई -

हरिजनों को गैर हरिजनों को

कृषि योग्य	18238 स्टैडर्ड एकड़	11	822
------------	---------------------	----	-----

स्टैंडर्ड एकड़

बंजर

8946 साधारण एकड़ 7174

साधारण एकड़

गैर मुमकिन

4982 साधारण एकड़ 4664

साधारण एकड़

प्रत्येक जिला की वार्षिक सूचना को एकत्रित करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उस से विशेष लाभ नहीं होगा ।

(सी) वह भूमि जो 31- 10-75 को निपटारे के लिए बकाया थी ।

कृषि योग्य

4972 स्टैंडर्ड एकड़

बंजर.

2837 साधारण एकड़

गैर मुमकिन

5531 साधारण एकड़

प्रत्येक तहसील की सूचना को एकत्रित करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उस से कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Panchayat Bhawans

485. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the district-wise number and names of

Panchayat Bhawans constructed by the State Government in the State upto 31-12-1975, togetherwith the amount spent on each Bhawan, separately; and

(b) the district-wise number and names of the Panchayat Bhawans; if any proposed to be constructed in the State during the year of 1976 togetherwith the amount likely to be spent on each such Bhawan, separately ?

कृषि मन्त्री (कर्नल महा सिंह) : (ए तथा बी) शून्य । अलबत्ता ऐसे पंचायत भवन पंचायतों द्वारा अपनी निधि से बनाये जा रहे हैं । एक पंचायत भवन का करनाल में निर्माण किया जा चुका है और एक अन्य की आधारशिला भिवानी में रखी जा चुकी है । वर्ष 1976 के दौरान पंचायतों द्वारा गुडगावां, अम्बाला तथा रोहतक में पंचायत भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।

Blood Banks

486. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Industries be pleased to state -

(a) the district-wise number and names of Blood Banks functioning in the State as at present togetherwith the storage capacity of each such Blood Bank ;

(b) the district-wise quantity of blood donated by the people to the Blood Banks as referred to in part (a) above, during the years 1974 and 1975, separately ; and

(c) the district-wise quantity of blood given to patients in the Hospitals by the above mentioned Blood Banks

during the years 1974 and 1975, free of cost and at cost, separately ?

उद्योग मन्त्री (श्री हरपाल सिंह) : (क) इस समय हरियाणा राज्य में रक्त के तीन बैंक चिकित्सा महाविद्यालय हस्पताल, रोहतक, सिविल हस्पताल, करनाल तथा सिविल हस्पताल, अम्बाला में हैं । इन रक्त बैंकों में रक्त जमा करने का प्रबन्ध निम्नलिखित प्रकार से है रू—

1. चिकित्सा महाविद्यालय हस्पताल, रोहतक 130 बोतलें
2. सिविल हस्पताल, करनाल 60 बोतलें
3. सिविल हस्पताल, अम्बाला 100 बोतलें

(ख) इन बैंकों में जिलावार जो रक्त दान द्वारा इकट्ठा हुआ है, वह 1974 तथा 1975 के बारे में अलग—अलग निम्नलिखित प्रकार से है रू—

क्र.

स. संस्था का नाम

वर्ष

1974

1975

(सी० सी०

(सी० सी०))

1.

चिकित्सा महाविद्यालय हस्पताल,

5,11,000

8,34,000

रोहतक

2.	सिविल हस्पताल, करनाल	1,47,300	1,24,500
3.	सिविल हस्पताल, अम्बाला	1,34,400	1,45,200

(ग) इन बैंकों द्वारा जिलावार जौ रक्त मरीजों को 1974 तथा 1975 में दिखा गया, वह निम्न प्रकार है :-

क्र.	संस्था का नाम	वर्ष	
		1974	1975
		(सी० सी०)	(सी० सी०)

चिकित्सा महाविद्यालय हस्पताल,			
1.	रोहतक	4,89,250	6,45,500
2.	सिविल हस्पताल, करनाल	1,42,500	1,18,200
3.	सिविल हस्पताल, अम्बाला	1,29,900	1,25,400

यह रक्त मुक्त दिया गया था ।

**Raids made by the Weights and Measures
Authorities**

487. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Industries be pleased to state the district-wise number of raids made **by the** Weights and Measures Authorities of the State to check the weights and measures in the State during the years 1974 and 1975, separately, togetherwith the cases of wrong weights and measures detected and the action taken against the defaulters ?

Industries Minister (Shri Harpal Singh): Two statements, one each for 1974 and 1975, are given below :-

STATEMENT-I

Raids conducted to check weights and measures during the year 1974

Sr. No.	Name of district.	No. of raids conducted.	No. of wrong weights & measures detected.	Cases of deci-weights the- & Courts.	Cases pending in the Courts.	Fine imposed by the Courts.
1	2	3	4	5	6	7
						Rs.
1.	Ambala	1522	25	20	5	1125/-

2.	Bhiwani	1253	5	—	5	-
3.	Gurgaon	2051	169	76	93	4155/.
4.	Hissar	828	23	—	23	-
5...	Jind	389	1	—	1	-
6.	Karnal	4608	47	2	45	85/-
7.	Kurukshetra	---	----	—	—	-
8.	Mohindergarh	1466	5	—	5	-
9.	Rohtak	419	—	—	—	-
10.	Sonepat	1555	9	—	9	-
11.	Sirsa	521	31	12	19	245/-
	Total	1461	315	110	205	5610/-
		2				

STATEMENT II

Raids conducted to check weights and measures during the year 1975

Sr. No.	Name of district.	No. of raids/ins -	No. of cases of wrong weight conducted	Cases decided by the Court	Cases pending in the Court	Fine imposed by the Courts.

s &

1	2.	3	4	5	6	7
						Rs.
1.	Ambala	2404	85	30	55	1705/-
2.	Bhiwani	1489	10	—	10	-
3.	Gurgaon	2562	200	92	108	7430/-
4.	Hissar	831	11	—	11	-
5.	Jind	1066	4	—	4	
6.	Karnal	4114	146	43	103	2155/-
7.	Kurukshetra	605	31	—	31	-
8.	Mohindergarh	1641	22	7	15	120/-
9.	Rohtak	713	—	—	—	-
10.	Sonepat	2046	13	—	13	-
11.	Sirsa	1066	6?	41	21	270/-
	Total	18537	584	213	371	11680/-

Illicit Liquor

488. Chaudhri Ram Lai Wadhwa : Will the Minister

for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the district-wise number of cases of illicit liquor detected by the Excise Authorities in the State during the period from 1968-69 to 1975-76 (upto 31-12-1975) together with the number of bottles taken into possession in each district, separately ; and

(b) the district-wise number of cases of illicit liquor as referred to in part (a) above which were (i) dismissed by the Courts (ii) resulted in conviction and (iii) the number of those which are pending in Courts, to date, separately ?

आबकारी तथा कराधान मन्त्री (श्री श्याम चन्द) :

(ए)

व एक विवरण संलग्न है

(बी)

(ए)			(बी)			
क्रमांक	जिले का नाम	पकडे गए केसों की संख्या	कब्जे में ली गई बोलतों की संख्या	कोर्ट द्वारा बर्खास्त किए गए केसों की	कोर्ट द्वारा सजा दिए गए केसों की संख्या	कोर्टस में लम्बित केसों की संख्या

				संख्या		
1	हिसार	2,377	9,983	372	1,485	520
2	रोहतक	137	1,319	--	123	14
3	गुडगावां	77	1,207	8	41	28
4	करनाल	875	5,075	10	833	32
5	अम्बाला	121	490	14	86	21
6	नारनौल	130	1,111 3/4	18	73	39
7	जींद	4,164	4,456	1,403	2,464	297
8	भिवानी	805	3,240 1/4	--	415	390
9	सोनीपत	7	25	--	7	--
10	कुरुक्षेत्र	974	1,751 1/4	--	702	272
11	सिरसा	12	107	--	--	12
12	फरीदाबाद	40	390	2	19	19
कुल जोड़		9,719	29,155 1/4	1,827	6,248	1,644

नोट :- आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्य के लिए फरीदाबाद को एक अलग जिला बनाया गया है, जिसमें बल्लभगढ, तथा पलवल उप मण्डल शामिल हैं ।

Assessment of Sales Tax

489. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Excise **and Taxation be** pleased to state—

(a) the district-wise number of cases of assessment of Sales Tax pending before the Excise and Taxation Authorities of each district as on 31-12-1974, together with the amount involved, separately ;

(b) the district-wise number of new cases of assessment of the Sales Tax for which the District Excise and Taxation Authorities issued notices to the parties during the year 1975, together with the amount involved, separately; and

(c) the district-wise number of cases of assessment of Sales Tax, out of those referred to in parts (a) and (b) above, decided during the year 1975, and the number of those which are pending to date togetherwith the amount involved, separately ?

आबकारी तथा कराधान मन्त्री (श्री श्याम चन्द) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केसों के बारे में मांगी गई सूचना नीचे दी जाती है । जिन केसों का फैसला हो चुका है, उनकी कर राशि भी नीचे दी जाती है । जिन केसों का फैसला नहीं हुआ, उनकी राशि बताना सम्भव नहीं ।

	(ए)	(बी)	(सी)		
नाम	31-12-74	नए असैसमेंट	1975 में (ए) में से	1975 में (बी) मे से	अब तक लम्बित
जिला	को	केस, जिनमें	फैसला किए गए	फैसला किए गए केसों	केसों की संख्या
	-लम्बित	1975 में	केसों की संख्या	की संख्या	
	असैसमेंट	नोटिस जारी			
	केसों की	किए गए, की			
	संख्या	संख्या			
			संख्या	संख्या	(ए) में (बी) में
			राशि	राशि	से से

1	हिसार	5,885	6,340	4,442	41,61,000	2,469	18,38,000	1,443	3,871
2	रोहतक	2,696	4,647	1,379	9,69,506	2,399	10,36,217	1,317	2,248
3	गुडगावां	3,021	4,003	2,191	-2,16,017	2,522	3,28,657	830	1,481
4	करनाल	2,982	5,057	1,270	21,94,957	2,925	4,57,382	1,712	2,132
5	अम्बाला	6,247	13,393	4,732	30,78,538	5,731	35,76,710	1,515	7,662
6	जींद	2,580	2,940	1,888	5,43,984	1,140	3,30,518	692	1,800
7	नारनौल	4,275	3,357	2,796	85,59,605	680	23,50,749	1,479	2,677
8	भिवानी	1,485	2,718	1,111	17,32,212	1,535	5,41,250	374	1,183
9	कुरुक्षेत्र	2,025	4,736	1,516	9,45,048	2,066	7,48,544	509	2,670
10	सोनीपत	1,532	3,031	1,421	20,50,000	1,241	20,00,000	111	1,790
11	सिरसा	3,592	3,991	2,482	8,67,000	1,138	3,43,000	1,110	2,853

12 फरीदाबाद	7,261	9,621	2,621	14,41,739	3,977	14,11,781	4,640	5,644
-------------	-------	-------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-------

नोट :-आबकारी एवं कराधान विभाग के कार्य के लिए फरीदाबाद को एक अलग जिला बनाया गया है, जिसमें बल्लभगढ तथा पलवल शामिल हैं ।

**Appeals Pending Before Excise and Taxation
Commissioner**

490. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the district-wise total number of appeals filed against the orders of the Deputy Excise and Taxation Commissioners and pending before the Excise and Taxation Commissioner or any other officer appointed as Appellate Authority in this respect as on 31-12-1974, together with the total amount involved, separately ;

(b) the district-wise total number of appeals as referred to in part (a) above filed during the year 1975, togetherwith the amount involved, separately ; and

(c) the district-wise total number of appeals out of those referred to in parts (a) and (b) above, decided against and in favour of the appellants during the year 1975, and also the number of those pending to-date, together with the amount involved, separately ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द) : (क ख और न)

आबकारी एवं कराधान विभाग विभिन्न अधिनियमों का प्रशासन करता है जिन में शक्तियां उप आबकारी एवं. कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा अन्य प्राधिकारियों में निहित हैं । माननीय सदस्य द्वारा किए गए प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं है कि वे किस विशिष्ट अधिनियम का उल्लेख कर रहे हैं । इन

परिस्थितियों में कोई स्पष्ट उत्तर देना सम्भव नहीं है ।

Appeal Regarding Sales Tax

491. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the district-wise number of appeals of Sales Tax against the orders of the Excise and Taxation Authorities of each district of Haryana State regarding Sales Tax pending before the Deputy Excise and Taxation Commissioners as on 31-12-1974, together with the amount of Sales Tax involved ;

(b) the district-wise number of appeals regarding Sales Tax filed before the Deputy Excise and Taxation Commissioners against the orders of the District Excise and Taxation Authorities during the year 1975, together with the amount involved, separately ; and

the total number of appeals as referred to in parts (a) and (b) above, disposed of against and in favour of the Appellants during the year 1975 and also the number of those pending to-date, together with the amount involved, separately ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द) : (काख और न) 31- 1 2- 1974 को उप आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के पास निलम्बित अपीलों, वर्ष 1975 के दौरान दायर की गई अपीलों की संख्या और उस अवधि के दौरान उनका निपटान दर्शाने वाला विवरण-पत्र संलग्न है । इन मामलों में सम्बद्ध कर राशि के विषय में स्पष्ट रूप से बताना सम्भव नहीं है क्योंकि यह

सूचना प्राप्त करने से पहले प्रत्येक फाईल की ध्यानपूर्वक छानबीन करनी होगी । इसके अतिरिक्त केसों का अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने के पश्चात ही कर की ठीक राशि का पता लग सकता है ।

विवरण-पत्र

31- 12- 7 4, को राज्य के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त के पास 198 अपीलें सुनने के लिए थीं, उनका जिलावार व्यौरा निम्नलिखित है :-

1. अम्बाला	16
2. करनाल	30
3. कुरुक्षेत्र	2
4. सोनीपत	44
5. रोहतक	30
6. हिसार	35
7. गुडगांवा	22
8. जींद	4
9. महेन्द्रगढ	8
10. भिवानी	7

1975 के दौरान, अर्थात् 1- 1- 1975 से 3 1- 1 2- 1975 तक, इन प्राधिकारियों से 1816 अपीलें की गई थीं । उनका जिलावार ब्यौरा निम्नलिखित है रू-

1. अम्बाला	535
2. करनाल	105
3. कुरुक्षेत्र	117
4. सोनीपत	207
5. रोहतक	209
6. भिवानी	33
7. हिसार	257
8. गुडगावा	187
9. जींद	69
10. महेन्द्रगढ	102
11. सिरसा	14
	1,816

वर्ष, 1975 के दौरान, 1857 अपीलों का निपटान कर दिया गया । इन में से 1192 मामलों में मुापील कर्त्ताओं की अपीले पूर्णतः अथवा अंशतः मान ली गई, जबकि 685 अपीले रद्द कर दी गयीं । 31- 12- 75 को 157 अपीले पैंडिंग थीं ।

Chairmen of the Improvement Trusts

492. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Local Government be pleased to state—

(a) the names and number of the Chairmen of the Improvement Trusts working in the State of Haryana at present, together with their. dates of appointment and qualifications, separately ; and

(b) the criteria adopted by the Government for, the appointments of the Chairmen as referred to in part (a) above, together with the minimum qualifications fixed for this purpose and whether the present Chairmen fulfil such qualifications, if not, the reasons therefor, separately ?

“पोकर राम गोदारा अ. स. पलाक 2-एच. बी.
एस. अक्यू— 4 क 1- 7 6/
2075

मंत्री

स्थानीय शासन विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ ।

दिनांक जनवरी 19, 1978

विषय—विधान सभा अतारांकित प्रश्न सं ० 492, जो चौधरी राम लाल, एम ०एल ०ए ० द्वारा पूछा गया है के बारे सूचना उपलब्ध करने सम्बन्धी ।

प्रिय चौधरी साहिब

मैं आपकी सूचित करता हूँ कि अतारांकित विधान सभा प्रश्न सं० - 492 (जोकि नगर सुधार मंडलों के अध्यक्षों की संख्या, उनकी नियुक्ति की तिथि उनकी योग्यता एं तथा इन अध्यक्षों की नियुक्ति बारे सरकार दवारा क्या आधार अपनाया इस बारे है और चौधरी राम लाल एम. एल. ए. द्वारा पूछा गया है) कमेटी- 1 शाखा हरियाणा सिविल सचिवालय को 9-1-1978 (शाम) को प्राप्त हु आ था । इस प्रश्न का करार विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 19-1-1976 को देय है, किन्तु इस प्रश्न का उत्तर देने सम्बन्धी सूचना बांछित है । वह अमी फील्ड कार्यालयों से प्रतीक्षित है । अतः मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर दिनांक 19- 1-1976 को देना सम्भव न होगा । इन परिस्थितियों में मैं आभारी हूंगा यदि आप इस प्रश्न का उत्तर तैयार करने हेतु कम से कम 10 दिन की बढ़ोतरी दें ।

सादर

श्री स्वरुप सिंह,

आपका,

हस्ताक्षरित

अध्यक्ष,

(पोकर राम गोदारा)

हरियाणा विधान सभा, चन्डीगढ ।

Mutation Cases

493. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the district-wise number of cases of mutations which were pending before the revenue authorities at each district as on 31-12-1974 ;

(b) the district-wise number of cases of mutations filed during the year 1975 at each district ; and

(c) the district-wise number of cases of mutations, out of those referred to in parts (a) and (b) above, disposed of upto 31-12-1975, together with the number of cases pending to-date ?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) रू विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्रमांक	जिला	प्रत्येक जिला में राजस्व अधिकारियों के सम्मुख	वर्ष 1975 में फाईल किए गए इन्तकालों की	(क) तथा (ख) भाग में वर्णित इंतकालों में	इस समय (31-12-75 को) लंबित केसों की
---------	------	---	--	---	---------------------------------------

		31-12- 74 को लम्बित इन्तकालों ही संख्या	संख्या (क)	31-12-75 तक निपटाए गए इन्तकालों की संख्या	संख्या (ख)
1	2	3	4	5	6
1	अम्बाला	1,289	12,492	12,612	1,169
2	करनाल	793	7,742	8,168	367
3	कुरुक्षेत्र	1,446	10,448	9,916	2,018
4	रोहतक	658	10,179	10,138	699
5	सोनीपत	257	7,098	5,600	1,755
6	हिसार	577	13,861	13,874	564
7	भिवानी	399	6,612	6,621	390
8	सिरसा	458	8,583	8,581	460
9	जींद	1,093	6,251	6,527	817
10	गुडगांव	1,667	21,470	24,548	1,589

11	नारनौल	197	6,007	6,101	103
	कुल जोड़	8,834	1,13,783	1,12 686	9,931

Surplus Agricultural Land

497. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the district-wise total number of persons who have declared their surplus agricultural land as required under the Haryana Ceiling on Land Holdings Act, 1972 to-date, togetherwith the district-wise surplus area declared; and

(b) the district-wise number of persons who have been allotted surplus agricultural land as referred to in part (a) above togetherwith the area so distributed ?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरन्जी लाल शर्मा) :

(ए) (1) जिलावर 30-9-1974 तक प्राप्त हुए घोषणा-पत्रों का ब्यौरा निम्न प्रकार है —

जिले का नाम संख्या	घोषणा पत्रों की
(1) अम्बाला	877
(2) करनाल	3,575

(3) हिसार	13,568
(4) रोहतक	927
(5) गुड़गाँव	817
(6) जीन्द	3,825
(7) महेन्द्रगढ़	128
(8) सोनीपत	1,208
(9) कुरुक्षेत्र	4,307
(10) भिवानी	1790
(11) स्पैशाल कलैक्टर, हरियाणा	754

'दी हरियाणा सीलिंग आन लैण्ड, होल्डिंगज एक्ट 1972 में संशोधन करने का इरादा है एक्ट में संशोधनोपरान्त भू-पतियों से पुनः घोषणा-पल लेने पड़ेंगे ।

(2) 'दी हरियाणा सीलिंग आन लैण्ड होल्डिंगज एक्ट, 1972 के अधीन अभी तक कोई भी भूमि फालतू घोषित नहीं की गई है । (बी) शून्य

शोक प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसीदास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़े भारी दिल से और दुख के साथ सदन के सामने यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ रहा है । आज सब जानते हैं कि हमारे, आपके, सबके एक बुजुर्ग नेता ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर का कल अकरस्मात् निधन हो गया । मुसाफिर साहब के बारे में इस सदन का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं या सदन से बाहर भी हरियाणा और पंजाब का कोई ऐसा आदमी नहीं, जो उनकी सेवाओं से, उनके बलिदान से, उनके त्याग से परिचित न हो । मुसाफिर साहब सन् 1930 में राजनैतिक क्षेत्र में आए और अनेक प्रकार की हसीयतों से उन्होंने देश की सेवा की । संयुक्त पंजाब में जब हम लोग भी सब शामिल थे, वे प्रदेश कांग्रेस के वर्षों तक अध्यक्ष रहे । मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला । मैं जिला कांग्रेस कमेटी, हिसार का अध्यक्ष होता था, जब वे प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो मैं उनकी कार्यकारिणी समिति का भी सदस्य होता था । तो उनके बहुत नजदीक बैठ कर मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । वे बड़े गम्भीर व्यक्ति थे, बड़ी सूझ-बूझ वाले थे और उनके दिल में देश के प्रति और देश की जनता के प्रति बड़ी भारी तड़प थी । राजनैतिक क्षेत्र में जो उन्होंने सेवाएँ की हैं, वे कभी भुलाई नहीं जा सकतीं । वे आजादी प्राप्त करने से पहले ही जब केन्द्रीय अन्तरिम विधान सभा बनी, तो उसके सदस्य रहे, कांस्टीच्युएंट असैम्बली के वे सदस्य रहे, पार्लियामेंट के वे वर्षों तक मंबर रहे और जब पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा और पंजाब प्रदेश का अलग गठन हुआ तो वे

पंजाब प्रदेश के प्रथम मुख्य मन्त्री बने और आज— कल वे राज्य सभा के सदस्य थे । तो मुसाफिर साहब ने जीवन भर देश की सेवा की । देश के लिए बलिदान किया और इसके साथ—साथ जहां वे एक राजनैतिक नेता थे, वह एक बड़े भारी साहित्यिक व्यक्ति भी थे । पंजाबी साहित्य में तो उनकी बड़ी भारी देन है । उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, अनेक ऐसी कविताएं लिखीं जिससे सारे देश की जनता को एक बड़ी भारी प्रेरणा मिलती थी । तो मेरा कहने का अभिप्रायरूप यह है कि मुसाफिर साहब का तमाम जीवन इस देश के लिए रहा । वे इस देश के लिए जीए । इस देश के लिए बोले, इस देश के लिए सांस लिया और इस देश की सेवा करते—करते वे इस संसार से चले गए । मुसाफिर साहब का निधन एक ऐसी क्षति है, पंजाब और हरियाणा के लिए ही नहीं, बल्कि सारे देश के लिए, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती । तो अध्यक्ष महोदय यह सारा सदन भारी दिल से और गहरे दुख के साथ उनके निधन पर शोक प्रकट करता है और मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस सदन का यह सम्वेदना संदेश उनके परिवार के सदस्यों व उनके मित्रों, उनके कार्य— कर्त्ताओं तक पहुंचाया जाए और भगवान से यह प्रार्थना को जाए कि भगवान जैसी उनकी आत्मा थी, जैसे उनके ऊंचे कर्म थे, जैहै उनके काम थे, उसी प्रकार उनकी आत्मा को गति प्रदान करे । ऐसी हमारे सारे सदन की भावना है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि उस महान नेता के चरणों में अर्पित करता है ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी) : अध्यक्ष महोदय, जो जजबात लीडर आफ दी हाउस ने एक बुजुर्ग के बारे में जो अब नहीं रहे और थोड़ी ही देर पहले थे, हाउस के सामने रखे मैं उनसे मुकम्मल तौर पर अपने आपको बाबस्ता करता हूँ । मेरा उनसे वास्ता रहा, हम इकट्ठे सैन्टर में कांग्रेस पार्लियामैंट्री पार्टी के मेंबर थे । उस वक्त पंजाब के जो भी एम०पीज० होते थे., उनकी हफ्तावार मीटिंग होती थी । उनमें हम उनकी कविताएं सुनते थे । आखिरी बार मैंने उनके दर्शन तब किए जब बरूआ साहब को छोड़ने गत् । वे एयरपोर्ट पर थे और उस रोज उनकी सेहत बहुत नार्मल नहीं थी । मैंने एक साथी से यह कहा भी कि 77 साल की उम्र में भी कितने तगड़े हैं, लेकिन आज कुछ ढीले हैं । मूझे यह पता नहीं था कि मेरी उनसे यह आखिरी मुलाकात होगी । एक बहुत बड़ा कुर्बानी देने वाला देशभक्त चला गया । उनकी जिन्दगी का दिलचस्प पहलू यह था कि वे बड़े लिटरेरी थे । उनकी सबसे पहली जो किताब थी, वह सी०आई०डी० ने छापी थी । जब वे जेल में थे तो अपनी बीबी के नाम कविताएं लिखा करतें थे । वे कविताएं पंजाबी में लिखते थे और वह सैंसर होती थीं । पंजाबों में सैंसर करने के लिए टाप-मोस्ट आफिसर जो थे, वे पंजाबी नहीं जानते थे, इसलिए वे कविताएं इंगलिश में टूस्लेट की जाती थीं । जिस ट्रांसलेटर के पास वे कविताएं पहुंचती थीं, वह उनकी पोइटिक वैल्यू को समझते हुए उनको कोलैक्ट करता रहा । जब वह रिहा हुए तो उसने इस बात की उनसे परमिशन चाही कि अगर आप इजाजत दें, तो मैं इनको अंग्रेजी में छाप दूँ

। ज्ञानी साहब ने उनका इजाजत दे दी और वह किताब अंग्रेजी लिट्रेचर की एक बेहतरीन किताब थी । स्पीकर साहब, उनकी जो आखिरी लिट्रेरी किताब थी, वह थी पंजाब दे बड्डे वजीर'' । सर सिकन्दर के वक्त से लेकर उन्होंने ज्ञानी बैल सिंह तक, सब को लाईफ स्कैचिज दी । मैंने उनसे शिकायत की कि लिट्रेरी सूरत में तो हरियाणा भी पंजाब का ही एक पार्ट है, आपको हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स के बारे में चौप्टर रेड करना चाहिए था । उन्होंने जाते ही चौप्टर लिखा । राव बीरेन्द्र सिंह, पंडित भगवत दयाल और चौधरी बंसी लाल के बारे में बहुत अच्छा चौप्टर है । उन्होंने अपने पब्लिशर से कहा कि सैकेण्ड एडीशन में इसको भी ऐड किया जाए । मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरी सुजैशन को कबूल किया । आज वे बुजुर्ग यहां नहीं हैं । मैं एक बार फिर अपने बेंचिज की ओर से जो जजबात लोडर आपा दी हाउस ने हाउस के सामने रखे हैं, उनसे अपने आपको बाबस्ता करता हूं ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members I fully associate myself with the deep feelings that have been expressed by the Leader of the House and Sh. Daulata about the passing away of Giani Gurmukh Singh Musafir, Member, Rajya Sabha. The death of this poet-politician of Punjab will be deeply mourned by his friends and admirers in Northern India in General and in Punjab and Haryana, in particular. For about nearly four decades he rendered distinguished services in various capacities in the composit Punjab State. Sh. Musafir was a Member of Constituent Assembly as also of the Provisional Parliament. Later he was elected to the first Lok Sabha. After

the re-organisation of Punjab in 1966 he had the privilege of being its first Chief Minister. He was elected to Rajya Sabha in 1968. Shri Musafir was also a Journalist of repute. He was a true patriot. I shall no doubt convey the sympathies of this House to the bereaved family. Now I request you to kindly observe silence for two minutes' while standing as a mark of respect to the memory of the deceased.

(The House then stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased, Giani Gurmukh Singh Musafir).

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करूंगा कि मुसाफिर साहब हमारे एक बड़े महान नेता थे । पंजाब और हरियाणा के साथ उनका बड़ा सम्बन्ध था । इसलिए उनके प्रति शोक प्रकट करने के उद्देश्य से 4.00 बजे तक के लिए हाउस स्थगित कर दिया जाए ।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, लीडर आफ दी हाउस ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं 'उसका अनुमोदन करता हूं और सभी जानते हैं कि हरियाणा के लोगों से मुसाफिर साहब को बड़ा प्यार था और उनके सम्मान के लिए एक घंटे के लिए हाउस स्थगित कर दिया जाए ।

Mr. Speaker : The House Stands adjourned till 4.00 P.M. today.

(The Sabha then adjourned at 14.55 hours and re-assembled **at** 16.00 hours.)

सदन की मेज पर रखे गए कागज—पत्र

Mr. Speaker : Papers to be laid.

16.00 बजे

Chief Minister (Shri Banarsi Dass Gupta) : Sir, I beg to lay on the table--

(i) The 7th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1973-74, as required under section 69 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

(ii) The statement showing the Loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15th December, 1975 for which the State Government have stood guarantee for payment thereof under Section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

(iii) The Report of the Comptroller & Auditor General of India for the year 1973-74 of the Government of Haryana.

(iv) The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 1973-74.

(v) The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 1973-74.

वर्ष 1975—76 के अनुपूरक अनुमान (दूसरी किस्त)
का पेश करना

Chief Minister (Shri Banarsi Dass Gupta) : Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1975-76.

प्राक्कलन समिति का वर्ष 1975-76 के अनुपूरक
अनुमान (दूसरी किस्त) पर प्रतिवेदन पेश करना

Chairman, Estimates Committee (Shri Nihal Singh) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1975-76.

वर्ष 1976-77 के बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : General discussion on the Budget for the year 1976-77.

चौधरी रिजक राम (राई) : स्पीकर साहब, 1 97 6-77 के साल के-बजट के बारे में मैं थोड़े शब्दों में अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हं, वित्त मन्त्री महोदय ने अपनी तकरीर में और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय प्रोग्राम की काफी चर्चा की है और मुख्य मन्त्री जी ने भी अपना भाषण देते हुए फरमाया था कि प्रधानमन्त्री का 20 सूत्रीय प्रोग्राम पूरा करना सरकार का लक्ष्य है मैंने जो प्रोग्राम देश के मामले में प्रधानमन्त्री की ओर से आया है, उसको अच्छी तरह से देखा है उस पर अच्छी तरह से विचार भी किया है और मैं यह महसूस करता हू कि जो 20 सूत्रीय प्रोग्राम जिस पर कि आज सरकार भी और कांग्रेस पार्टी भी बड़े दावे करती है वो कोई नया

प्रोग्राम नहीं है और कांग्रेस पार्टी के आबादी इजलास ने जो सन् 1955 में हुआ था, उसमें भी हम पार्टी ने अपने प्रोग्राम में यह फैसला किया था कि देश में समाजवादी राज्य कायम किया जाएगा, वेलफेयर स्टेट कायम करने का लक्ष्य बनाया था, विधान में भी. इसी लक्ष्य को मान्यता दी थी । 1964 में भुवनेश्वर के इजलास में, कांग्रेस पार्टी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम देश के सामने रखा और उसमें भी यह फैसला किया गया कि वह सारी जनता को रोटी कपडा और मकान व स्वास्थ्य के लिए सभी इन्तजामात करेंगे और बच्चो को तालीम भी देने का प्रबन्ध उसमें शामिल था । 1964 में पार्टी की यह तजवीज थी कि सभी आदमियों को तन ढांपने के लिए कपडा खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान लाजमी तौर पर देंगे । उसके बाद और भी कई सैशनों, नागपुर, बंगलौर और बम्बई, जो कि 1968, 6970 में हुए सभी सैशनों में, मिनिमस नीज पर 10 सूत्रीय कार्यक्रम देश के सामने रखा गया कि वे अपने सारे वायदे जो जनता को दिए गए हैं, सरकार पूरा करेगी । आज जो भी बाते प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्दर हैं, जिनको देखनेसे पता चलता है कि न तो वित्त मन्त्री महोदय के एड्रैस मे और न ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्रोहिबशन के बारे में कोई जिक्र आया है । सन् 1950 से आज तक कांग्रेस पार्टी नशाबन्दी व शराबबन्दी के ऊपर रोक लगाने का नारा लगाती आई है और हमारे विधान में भी ऐसा है, लेकिन आज हम देखते हैं कि वित्तमन्त्री महोदय के भाषण में इस बारे में एक लपज भी नहीं आया है, हालांकि इस 20 सूत्रीय

प्रोग्राम के अन्दर इस प्रोहिबशन के बारे में जिकर है । सरकार को तो लोगों की भलाई का ख्याल नहीं है कि लोगों की हालत सुधरे या न सुधरे ड्हकों वो अपनी रेवेन्यू बनाने की पडी हुई है और आज कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि आज देहात में बस स्टैण्डज पर, शहरों के कोने-कोने में, स्कूल और कालेजों के आसपास सभी जगहों पर शराब के ' ठे-कें खुले हुहु हैं और गरीब किसान 'जो कुछ भी कमाता है, वह वही पर 'खोकर चरन देता है । इसी कारण से लोगों ने अपने मकान जायदादें बेच दीं, जानी बीवियों के जेवर बेच दिए, जिनके कारण घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, लेकिन आज सरकार ने प्रोहिबशन का कोई सवार ही नहीं उठाया! जिमकी वजह में गरीब किसान की सारी कमाई इसी ओर बरबाद हो रही हुए । बल्कि हैने देखा है कि आमतौर पर जहां पर किं ट्रैक्टरों की वर्कगशाप्स हैं, स्पेयर पार्टस की दुकानें हैं, अनाज मण्डियों के पास सरकार ने शराब के ठेको शराब को दुकानें खोर रही हैं, भोले भाले किसान वहां पर आते हैं, टैक्टरों को वहां खडा करते हैं और शराब पीने में लग जाते हैं और स्पेयर पार्टस के पैसे मिस्त्री उनसे मनमानी से लेते हैं, ऐसी हालत हमारे प्रान्त में है । आज से 6 साल पहले 1989 में सरकार ने ऐलान किया था कि हम धीरे-धीरे 2- 3 स्टेजिज में सारे प्रान्त में प्रोहिबशन लागू कर देंगे । किसी भी जगह शराब का ठेका या कोई आदमी शराब नहीं बेचेगा । सरकार ने ऐलान किया था और यह कहा था कि हफते में पहले दो दिन, फिर तीन दिन और फिर चार दिन इस तरह से दुकाने बन्द रखेंगे, लेकिन आज दुकानें

बजाय बन्द होने के, शराब की बिक्री में इस चीज में बढ़ोत्तरी हुई है, कमी नहीं हुई है । मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ आप 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लाए हैं और जनता की भलाई के लिए आवाज उठाई है, वहाँ आज आप सोचें कि इस वक्त अनजान आदमी की हालत क्या है? एक किसान, मजदूर और स्वीपर जौ है, आज उनकी हालत आप देखेंगे कि क्या है, उनकी हालत में सुधार की आवश्यकता है । अनजान आदमी दिन में थोड़ी बहुत मजदूरी करता है और उसकी जो भी कमाई होती है, वह शाम को ठेके पर खर्च कर देगा है । तो भापका ध्यान इस तरफ नहीं है इसके लिए हमें बड़ा आश्चर्य है । कौन-सा प्रोग्राम है, जो आप लागू करना चाहते हैं । बाडिड लेबर के बारे में आपने अपने भाषण में ठीक कहा । बाडिड लेबर का यहाँ कोई मसला नहीं है । आपने कहा कि गरीब आदमियों को उनके कर्बों में सहूलियत दिलाएंगे और फिर आपने कानून भी पास कर दिया है । वह कानून क्या पास किया कि जो मार्जिनल फार्मरज हैं या जिनके पास अढ़ाई एकड़ या उससे कम जमीन है या जो लैण्डलैस लेबरज हैं उनसे कर्ज की वसूली एक साल तक नहीं हो सकेगी और भी प्रानों ने. ऐसे ही कानून बनाए हैं । मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बे-इन्साफी गरीब लोगों के साथ नहीं हो सकती । एक साल के लिए आपने उनके कर्ज मुलतवी कर दिए लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि स्पीकर साहब, आप भी जानते हैं कि आज देहातो और शहरों में उनको अपनी सख्त से सख्त जरूरत के लिए भी चाहे वह अनाज के लिए हो, कपड़े के

लिए हो या अपने बच्चों के इलाज के लिए हो, पैसा उधार नहीं मिलता है । सरकार ने क्या इन्तजाम किया है आज वे अपने जेवरात बेचकर, मकान बेचकर या किसी के पास एक-आध बीघा जमीन है, उसको बेचकर अपने काम चला रहे हैं । क्या आप यही रिलीफ उनको देना चाहते हैं । आपने एक साल के लिए उनके कर्ज मुलतबी करवा कर उनके प्राइवेट आदमियों के साथ ताल्लुकात बन्द कर दिए हैं क्योंकि अब किसी को भी उन पर विश्वास नहीं रहा है । क्या आपने उनको पैसे दिलवाने के लिए कोई दूसरा इन्तजाम किया । आज नैशनेलाइज्ड बैंक्स की हालत का किसको पता नहीं है । नैशनेलाइज्ड बैंक्स के बारे में सरकार कुछ भी कहे लेकिन मुझे जाति तौर पर पता है । कितने ही केसिज में मेरी एजेंट्स से बात हुई है जो कि स्टेट बैंक के इन्चार्ज हैं । वे कहते हैं कि हम तो मजबूर होकर किसी गरीब आदमी को कर्जा देते हैं क्योंकि उस कर्ज की वसूली में हमें बड़ी दिक्कत होती है । वे बड़े-बड़े कारखानेदारों को खुशी से कर्जा देते हैं क्योंकि उनको पता है कि कारखाने वालों से वसूली आराम से हो सकती है । गरीब आदमी को ट्रैक्टर के लिए, मकान बनाने के लिए और अपना धन्धा चलाने के लिए वे पैसा देकर राजी नहीं हैं क्योंकि बैंक करो कहते हैं कि इनको कर्जा देकर हमारे ओवर डियूज और बढ़ जाएंगे । तो नैशनैलाइज्ड बैंक्स से उनको कर्जा नहीं मिलता, को-आप्रेटिव बैंक्स में तरह-तरह की दिक्कतें हैं, लोग लोन लेने से हिचकते हैं क्योंकि सूद की दर बहुत भारी है । कुछ भी हो, स्पीकर साहब, मैं एक बात मुख्य मन्त्री जी के ध्यान

में आपके द्वारा लाना चाहता हूँ कि आपने कर्जे तो मुलतवी कर दिए लेकिन उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए आपने क्या आल्टरनेटिव निकाला? इससे आगे लैण्ड रिफार्मज की बात आती है । स्पीकर साहब, लैण्ड रिफार्मज का मसला कोई नया नहीं है । जैसे आजाद होने से पहले लैण्ड रिफार्मज का जिक्र कांग्रेस के हर सेशन में चल रहा था कि लैण्ड रिफार्मज करेंगे । सन् 1953 में यू०पी० को छोड़कर सब जगह एक्ट पास हुए और सन 1972 में दो बार लैण्ड रिफार्म एक्ट पास हुआ, हमारे सूबे में भी और दूसरी जगह भी । सिक्कोरिटी आफ लैण्ड टिन्योर एक्ट पास होने का क्या असर हुआ? जितने भी हरियाणा प्रान्त में मुजारे थे वे जमीनों से बेदखल हो गए क्योंकि कानून में गुंजायश रखी गई थी कि अगर कोई मुजारा बाकायदा तौर पर लगान नहीं देता तो वह बेदखल हो सकता है । अर्बन रेंट रिसट्रिक्शन एक्ट में तो यह प्रोवीजन है कि अगर किराया बाकी है, तो पहली पेशी कर या 15 दिन के अन्दर-अन्दर या उससे पहले अदा करके बेदखली से बच सकता है लेकिन सिक्कोरिटी आफ लैण्ड टिन्योर एक्ट में ऐसी प्रोवीजन नहीं रखी गई और नतीजा क्या हुआ कि जो सन् 1947 में या 1950-51 में हरियाणा में मुजारे थे उनमें से 10 फीसदी लोगों का भी आज जमीन पर कब्जा नहीं है तो यह सिक्कोरिटी दी आपने कानून के जरिए, अब लैण्ड रिफार्मज के जरिए आप जमीन तकसीम करने की बातें करते हैं । सन् 1971 में तो बहुत शोर था कि हम जमीन देंगे और बहुत से अनजान लोगों को यह ख्याल हुआ कि राय पड़ते ही किल्ले मिल जाएंगे और बहुत लोग

तो दूसरों के खेतों को देख भी आए थे कि हमें यह जमीन मिलने वाली है । चुनाव में कांग्रेस पार्टी सैंटर में ताकत में आई । कुछ दिनों बाद क्या हुआ? मैं आपको सोनीपत की एक बात बताता हूँ । रिकवरी तहसीलदार गांव-गांव में गए, जिन हरिजन आदि की तरफ मकानों के या तकावी के कर्जे बाकी थे उनको इकट्ठा किया और कहा कि सरकार आप लोगों से बहुत खुश है कि आपने कांग्रेस को राय देकर कामयाब किया है । आपको ईनाम मिलेगा । लोग भी बहुत खुश हुए कि हमें जमीन मिलेगी लेकिन आप हैरान होंगे कि उनको वहां से ले जाकर जेल में बन्द कर दिया । एक पंचायत का हरिजन मੈबर था, आप अगर तसदीक करना चाहें तो मैं उसका नाम भी बता देता हूँ, उसका नाम जगन था, वह जेल में बन्द था और चौधरी फूलचन्द ने उससे पूछा कि यहां जेल में कैसे बंटे हो तो जगन ने कहा कि यहां हमारे नाम किल्ले कट रहे हैं क्योंकि 1971 में ये लोग कह रहे थे कि जमीन देंगे । तहसील रोहतक का सरकारी तौर पर सर्वे हुआ । वहां नायब तहसीलदार एग्रेरियन ने सर्वे किया और सर्वे रिपोर्ट में लिखा कि 36 प्रतिशत टेनैट्स को कब्जे मिले हैं लेकिन जब पडताल की गई तो देखा गया कि 5- 6 प्रतिशत लोगों का कब्जा पाया गया और बाकी की जमीन लोगों से छुड़ा ली गई या वह काश्त करने के काबिल नहीं थी । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह लैण्ड रिफार्मज एक बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : शुरु भी आपने

की थी

चौधरी रिजक राम : ठीक है शुरू भी मैंने किया होगा, उसी के तजरुबे पर आपको कह रहा हूँ । आपके पास जमीन नहीं है और जो कानून आपने बनाया है मैं इस वक्त उस पर नहीं जाता लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस कानून से सिवाय इसके कि जो लैण्डलैस लेबरर्ज हैं, जो हरिजन हैं और दूसरी तरफ जो बिस्वेदार हैं, इनमें तलखी बढ़ी है और कोई बात नहीं हुई है । इधर किसान सोचता है कि तुम्हारी जमीन छिनेगी और दूसरी तरफ हरिजन सोचता है कि तुमने इसकी जमीन लेनी है । लेकिन जमीन न किसी को मिलेगी और न कोई मिलने की आशा है, उनकी आपस में लड़ाई हो रही है और उस लड़ाई का फायदा उठाकर आप यहां राज कर रहे हैं । पिछले सेशन में, 1974 में रैवेन्यू मिनिस्टर साहब ने ब्यान दिया था कि हमने साढ़े तीन किल्ले जमीन हरिजनों को दी है । कितनी बड़ी भारी कामयाबी दिखाई, साढ़े तीन किल्लो पर हरिजन आबाद कर दिए । यह जानते हुए भी कि जमीन फालतू नहीं है जो सजा मुख्य मन्त्री जी कहेंगे मैं मानूंगा वे आज भी यह बात कह दें या कोई डैड लाईन रख दें कि इतने साल के अन्दर इतनी जमीन हरिजनों को दे देंगे या वे यह कह दें कि हरियाणा में इतनी जमीन सरप्लस निकलेगी, कोई है ही नहीं जमीन जो दी जा सके । कानून ही आप लोगों ने जानबूझ कर ऐसा बनाया है कि जमीन निकल ही नहीं सकती और न ही निकलेगी । 24 जनवरी, 1971 तक जितनी सेल्ज और

बोनाफाइडी ट्रांसफर्ज हुई थीं, चाहे वे फर्जी भी थीं सब जायज करार दे दी गई । 1971 से पहले कितनी ही भूमि नाजायज तौर पर तबदील करा दी और जायज करार दे दी और 1971 के बाद भी छूट दे दी कि जिस के नाम करना चाहो कर दो । यह हुए आपके लैण्ड रिफार्मज । फिर आपका यह बीस सूत्रीय प्रोग्राम भी आपके सामने है जिसका बहुत चर्चा आज सारे देश में हो रहा है, बड़े-बड़े दावे इसके जरिए किए जा रहे हैं । इसके बारे में एक ही बात बताकर खत्म करता हूं । यहां 1,86,000 हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लोग पाए गए, जिनके पास सौ गज जमीन का टुकड़ा भी नहीं है कि जिस पर वह अपनी रिहायश के लिए मकान बना लें । यहां पर बताया गया कि डेढ़ लाख ऐसे लोगों को सौ-सौ गज जमीन का टुकड़ा दिया गया लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि इस पर सरकार का क्या खर्च हुआ? एक पैसा भी नहीं । पंचायत की जमीन थी, वह उठाकर दे दी, सरकार ने इसमें क्या किया? इस्तेमाल के दौरान सारे हरियाणा में सरकार ने पांच बिस्वे जननि पर-फैमिली को जो इस किस्म की थी, दी थी लेकिन अब यह सरकार सौ गज जमीन देकर बड़े दमगजे मार रही है और भारी दावे कर रही है कि यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, गरीबों को बीस सूत्रीय प्रोग्राम के तहत ऊंचा उठा रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपने यह भी मालूम करने की तकलीफ की है कि इन गरीबों के लिए गांव से एक-एक मील के फासले पर प्लाट काटे गए हैं और जोहड़ों और गड्डों में प्लाट काटे गए हैं और अगर उनको वे हमवार करेगे तो कितना खर्च आएगा? क्या आपका

यही समाजवाद है कि अमीर आदमी तो ऐसी कोठियों में रहते हैं जिनमें दस-दस बैड रूमज हैं लेकिन गरीब आदमी को सौ यख का प्लाट दे रहे हैं ताकि उस मकान में वे सभी बीबी-बच्चे, लड़के, बहुएं, नाती, पोते रूहें और उनको दिन रात बच्चे पैदा करने के सिवाय और कोई काम न रहे । यह तो हुई गांव के गरीबों की बात, जिनको पंचायत की जमीन मुक्त में लेकर सौ-सौ गज के प्लाट देने की बातें करते हैं और एक पैसा खर्च किए बगैर सारा क्रेडिट ले रहे हैं । दूसरी तरफ शहरी गरीबों के बारे कहते हैं कि उनको जमीन खरीद कर नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिज पर सौ-सौ गज के प्लाट देंगे, मकान बनाने के लिए । अगर देहात में मुक्त दी है तो शहर में भी मुक्त दो या कम से कम सबसिडाइज करके दो । वे भी वैसे ही गरीब हैं, जैसे वे हैं, गांव वाले । फिर यह भी देखो कि उस सौ गज पर जो मकान बनाना है, उस पर लागत क्या आती है । तो मैं अर्ज करता हूं कि इस बीस सूत्रीय प्रोग्राम पर अमली तौर पर काम करो । नारे लगाने और ऐलान करने से कोई फायदा नहीं होगा और इस तरह से खाली प्रचार करने से कोई बात बनने वाली नहीं है । ऐलान तो आप खूब करते हैं, लेकिन अमल उन पर कम है । शहरी जायदादों पर सीमा लगाने के बारे में भी आपने ऐलान किया है और कुछ कानून बनाना चाहते हैं । कहते हैं कि शहर में अगर किसी का एक हजार गज का प्लाट खाली पड़ा है, मकान चाहे उसके कितने ही हों, बाजारों के बाजार हों, और मुहल्लों के मुहल्ले हों, कारखाने कितने ही हों, उनको नहीं छेडेगे, लेकिन वह जो एक हजार गज

का खाली प्लाट होगा, उसे ले लेंगे । आठ महीने पहले यह फैसला सरकार ने किया था, जिस पर कानून अब बनाने की सोच रहे हैं । ऐसा कौन बावला होगा जिसने आज तक आठ महीने के अर्से में अपना खाली एक हजार गज का प्लाट रख छोड़ा होगा? सब ऐसे प्लाट रफू चक्कर हो चुके हैं तक्सीम हो चुके हैं लेंगे कहां से? मैं समझता हू कि यह महज एक दिखावा है और कुछ नहीं । कहते हैं कि शहरों में भी सीलिंग का कानून बना रहे हैं । असल में जिन लोगों के पास शहरों में जायदाद है वही तो सारी यह नीति निर्धारित करते हैं । जो ट्रेड में हैं कामर्स और इंडस्ट्री में हैं और बड़ी-बड़ी सर्विसिज में हैं सभी लोग अमीरों के बच्चे हैं और वही लोग हैं जो ये सारी नीति बनाते हैं क्या वे कभी अपने ऊपर सीलिंग का असर होने देंगे? कभी नहीं । आज गुप्ता जी को मौका मिला है कि वह मुख्य मन्त्री बने । मामूली घराने में वह पैदा हुए इसलिए गरीब का दर्द रखते हैं यह मैं मानता हूँ । लेकिन मैं एक बात जानता हूँ । मैं खुद कैबिनेट में रहा हूँ इसलिए मुझे पता है कि वजारत में मुख्य मन्त्री की और यूक वजीर की क्या लिमिटेशन हैं । नीति ऊपर से निर्धारित होती है, हां उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिसकी जैसी रुचि हो वैसे कर सकता है सख्ती से भी कर सकता है नर्मि से भी कर सकता है लेकिन नीति नहीं बना सकता । आज प्रधान मन्त्री ने बीस सूत्रीय प्रोग्राम दिया शगैर उसमें सबसे पहला फिकरा यह आया कि आगे को कोई नैशनेलाइजेशन नहीं होगी । मैं पूछता हूँ कि आपकी वह नैशनेलाइजेशन वाली पालिसी कहां गई जब आप बार-बार यह

कहते फिरते थे कि कन्सन्ट्रेशन आफ वैल्थ नहीं होने देंगे । कहां गए आपके वे सारे ऐलान जब कहते थे कि सारे कारखाने जिन में जरई पैदावार इस्तेमाल होती है किसान की जिनस इस्तेमाल होती है नैशनेनाइज करेंगे चाहे शूगर मिलज हैं राईस मिलज हैं चाहे टैक्सटाइल्ज हैं? वे सारे ऐलान इसलिए हवा हो गए कि आपने उनसे पैसा लेना है लाखों करोड़ों रुपए इलैक्शन के दिनों में लेने हैं और आप लेते हैं? आप उनको नहीं छेड़ते क्योंकि वे आपको थैलियां भेंट करते हैं और आप गरीबों को ही छेड़ना चाहते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ नहीं हैं । वे बेजूबान हैं आप उन पर कितने ही अत्याचार करें उनका सब कुछ छीन लें वे कमजोर हैं, कुछ बोल नहीं सकते जो चाहे करो । तो मैं अर्ज करता हूँ कि इस प्रोग्राम को अमली रूप दो, खाली बातें न करो ताकि लोगों को विश्वास हो सके । आठ महीने से यह आपकी आपात स्थिति लागू है, और इसमें एक तरफा प्रचार चल रहा है, डिसैन्ट की जो आवाज है, वह बन्द है । डिसैन्ट की आवाज अखबारों में प्लेटफार्म पर और लिट्रेचर यानी कलम के जरिए जो आवाज होती है, वह बन्द है । इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि लोगों की परेशानी कम नहीं हुई । अगर प्रजातन्त्र इस देश में चलाना है, तो डिसैन्ट की आवाज बन्द नहीं करनी चाहिए । एक बहुत बड़े फिलासफर ने कहा है कि -- When men's aculties are at they express themselves by some over act". आज का जमाना है । यह बूढ़े आदमियों का नहीं है, नौजवानों का है । लाखों की तादाद में नौजवान देश में बढ़ते जा रहे हैं । जितने नौजवान आज से तीस

साल पहले थे, उनसे आज पचास फीसदी ज्यादा हैं और ये नौजवान इस किस्म की बात को ज्यादा बरदाश्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि प्रजातन्त्र में बोलने, काम करने का और अपने विचार फ्रीली एक्सप्रेस करने का सबको अधिकार है । सात फ्रीडमज संविधान में महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से नेहरू जी ने स देश को दी थीं, वे आज खत्म हैं । मैं इस बात में नहीं जाँना चाहता कि आपात स्थिति की घोषणा ठीक है या गलत है, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत काम किया है । यह स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं और आजादी के अलम्बरदार रहे हैं, इसलिए मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि वह आज इस सारी बात को जो कुछ देश में हो रहा है, इसे निष्पक्ष रूप से देखकर गौर करेंगे कि क्या यह सही है, जो हो रहा है । आपने स्पीकर साहब इतिहास में पढ़ा होगा कि अमेरिका में क्या हुआ । आज आप जानते हैं कि अमेरिका के प्रेजिडेंट को बड़ी भारी ताकत वहाँ के विधान में मिली हुई है और दुनियां में सबसे पावरफुल हैड आफ दि स्टेट है, लेकिन आप देखें जब भी किसी प्रेजिडेंट ने यह कोशिश की कि वह सारी की सारी ताकत ज्यादा से ज्यादा ताकत अपने हाथ में ले ले, उस वक्त लोगों ने उस बात को बरदाश्त नहीं किया और चार प्रेजिडेंट अमेरिका के असैसीनेट हुए – (विधन) – यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है..

श्री गुलाब सिंह जैन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर ।
क्या चौधरी रिजक राम लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि जो

अमेरिका में हुआ, वह यहां भी होगा और यहां भी करवानी चाहते हैं ? (विधन) आखिर उनका यह कहने का मकसद क्या है?

चौधरी रिजक राम : मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन भाईयों के हाथों में आज ताकत है, वे ठंडे दिल से सारी बात को सोचे । आखिर वे सारे आदमी देश की अजादी के लिए लड़े हैं, कितने ही उन में सोशल वर्कर हैं जिन्होंने देश की आजादी में काम किया है और जिन्होंने सारी उम्र अहिंसा पर यकीन किया, अहिंसा के मार्ग पर चले । उन में आज हिंसा के विचार एक दिन में ही बन गये । आखिर आप इन बातों को सोचें । स्पीकर साहब, मैंने ज्यादा समय लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन बातों की तरफ मुख्य मन्त्री जी और इनके साथी गौर फरमाएं अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वह बजट की है । आज बजट पर डिस्कशन हो रही है । गुप्ता जी हमारे मुख्य मन्त्री बने हैं, बड़े शीतल स्वभाव के हैं, समझदार हैं, मुझे उनके साथ नाम करने का मौका मिला है । वे गरीबों के हमदर्द हैं और हमें आशा रखनी चाहिए. उम्मीद करनी चाहिए कि वे बतौरे मुख्य मन्त्री के हरियाणा के सभी वर्गों को निष्पक्ष रूप से आगे बड़ाने के लिए काम करेंगे । इसके साथ ही साथ, चौधरी बंसी लाल जी, जो हमारे पहले मुख्य मन्त्री थे, केन्द्र में चले गए । इस सूबे में उन्हेंने साढ़े सात साल तक राज चलाया और इस दौरान में निस्सन्देह प्रान्त की तरक्की हुई, उन्नति हुई और नाम ऊंचा किया । हरियाणा पिछडा हुआ इलाका था । यह अलग सूबा बना, बनने के बाद अलग रिसोर्सिज

पैदा किए, उद्योग चले ओर हरियाणा का नाम भी ऊंचा हुआ और हरियाणा में बलने वाले लोगों की भी इज्जत बढ़ी । आज वे केन्द्र में हैं और राष्ट्र के निर्माण में उनका बड़ा हाथ होगा । जहां तक हरियाणा का ताल्लुक है, हम सभी भाई और बहन यह आशा करते हैं कि हरियाणा की जो समस्याएं हैं, इस वक्त केन्द्र के रूबरू हैं, जिनकी वजह से हरियाणा की प्रगति में बाधा आई, रुकावट आई, उन को सुलझाने में वे बड़े मददगार साबित होंगे । स्पीकर साहब, अब तक कितने ही ऐसे प्रश्न आए, कई समस्याएं आयीं, जिसमें हरियाणा के लोग यह महसूस करते रहे कि केन्द्र में, चूकि कोई उनका प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए उन के साथ न्याय नहीं हो रहा लेकिन अब मेरे ख्याल में चौधरी बंसी लाल जी के केन्द्र में मन्त्री पद पर पहुंचने पर हरियाणा के लोगों को यह शिकायत नहीं रहनी चाहिए । आज हम देखते हैं कि हरियाणा की तरक्की के रास्ते में कई रुकावटें हैं और हमारी उन समस्याओं को अब तक केन्द्र हल नहीं कर सका । सतलुज लिंक से जो पानी ब्यास और सतलुज का हरियाणा को मिलना है, अभी तक उस हिस्से का फैसला नहीं हो सका कि कितना हिस्सा हमारा बनता है । शड्यूलड के मुताबिक अगर उस डैम पर काम चलता तो स्पीकर साहब, वह डैम अब से पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें देर लग रही है । अब 1976 की बजाय 1977 में पूरा होना है । पहले 1974 में होना था फिर 1975, फिर 1976 और अब 1977 तक होने की आशा है, कहने का मतलब यह है कि समय इतना बढ़ गया है । लेकिन शोक की बात है कि आज तक केन्द्रीय सरकार इस सवाल

का फैसला नहीं कर सकी कि कितना पानी हरियाणा को मिलना है । 1965 में स्पीकर साहब, पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी । उस एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट की थी कि हरियाणा में बहुत ज्यादा इलाके ऐसे हैं, जहां न तो अंडर ग्राउंड पानी है और न ही दरिया का पानी लगता है । बहुत से ऐसे इलाके हैं, जो सूखे व बारानी हैं । इसलिए उस कमेटी ने रिपोर्ट की थी कि 4.8 मिलियन एकड़ फीट पानी हरियाणा को दे दिया जाए । अब पंजाब वाले इस पर आपत्ति उठाते हैं कि री-आर्गेनाइजेशन एक्ट में हरियाणा का हिस्सा नहीं है और हरियाणा को कोई हिस्सा इस पानी में नहीं देना चाहते हैं । कुछ भी हो, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह है कि वह नहर जिसके जरिए हम सतलुज का पानी अपने इलाके तक ले जाएंगे, वह बनानी है । बजट में भी इसका जिक्र है, उस पर 75 करोड़ रुपया खर्च होना है । 1964 में 10 करोड़ रुपया खर्च होमे का अनुमान था, लेकिन अब हमने बजट में खर्च होने का अनुमान बताया है 75 करोड़, 75 करोड़ पर पहुंचे और जब तक मन्जूर होकर यह बननी शुरू होगी तो यह खर्चा और बढ़ सकता है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए । हमारे जो रिसोर्सिज हैं, वे बहुत कम हैं । आज हमारे सामने मुश्किलें स्पष्ट हैं । स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री से कहूंगा कि इस में समय बहुत लगता है, इसका अन्दाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पंजाब के लोगों ने भूमि लेनी है, उसके लिए अवार्ड लेना है, और उसके लिए लैण्ड एक्वीजिशन कुलैक्टर होंगे, वे हमारे इंजीनीयर्स को बनाने दें या खुद बनाने

की जिम्मेदारी लें, इसका पता बाद में चलेगा । अगर हमारे इंजीनियर काम करें तो अन्दाजा यह लगाया जा सकता है कि सारा काम मुकम्मल करने के लिए कम से कम 5-6 साल लगेंगे । ये कहते हैं कि अगले साल ब्यास का पानी सतलुज नदी भाखडा में पहुंच जाएगा, अगर इस नहर को बनाने में 6 साल लगें, इससे ज्यादा अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है, केन्द्र ठीक फैसला करता ही नहीं है । अक्वल तो रावी के पानी के अक्तूबर, 1970 से पाकिस्तान के हकूक खत्म हो गए और पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 55 करोड़ रुपया दे दिया, उस मोहादा के मुताबिक दे दिया, जो उन्होंने किया था लेकिन उस पानी को भी हम इस्तेमाल नहीं कर सके, क्योंकि केन्द्रीय सरकार इन आपसी झगड़ों को नहीं निपटा सकी । इसलिए अगर केन्द्रीय सरकार इस बात का फैसला कर देती है, इतना हिस्सा हरियाणा का बनता है, तो हम चार पांच साल तक पूरा पानी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन यह संशय की बात है कि इसमें हमारा हिस्सा होगा या नहीं, इसका अन्दाजा स्पीकर साहब, आप खुद लगा सकते हैं । रावी का पानी है, थीन डैम प्रोजैक्ट पुराना चल रहा है । कल आपने अखबार में पढ़ा होगा, शेख अब्दुल्ला से ज्ञानी जैल सिंह की बात हुई और इस बात पर सहमत हो गए कि थीन डैम को मिलकर बनाया जाए । रावी और व्यास में हरियाणा का हिस्सा है । अगर रावी का पानी भी नहीं मिला और व्यास के पानी पर भी झगड़ा होता रहा तो हमारी स्टेट की इकोनोमी का, आर्थिक स्थिति का क्या हाल होगा, इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं । जो खबर अखबार में

छपी थी, उसमें ज्ञानी जी ने कहा था कि हम हिमाचल से बात करेंगे, लेकिन हरियाणा का कोई जिक्र नहीं । स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे दृढ़ता के साथ इस बात को केन्द्रीय सरकार के साथ टेक-अप करें कि रावी में हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा है । पंजाब में 80 फीसदी से ज्यादा रकबा को पानी लगता है, होशियारपुर वगैरह के इलाके ऐसे हैं जहां बारिश होने की वजह से नहरों की जरूरत नहीं है । 80 फीसदी रकबा पानी के नीचे लगता है और इसके मुकाबले में हरियाणा में कितना इलाका है, जिस में पानी नहीं है? 34 से 40 फीसदी तक का रकबा आबपाशी शुदा है और वह भी दोनों फसलों की गिरदावरी को जोड़कर करते हैं, अगर फसल की गिरदावरी को देखें, तो 20 फीसदी से ज्यादा आबपाशी नहीं है । उस में भी कहीं ट्यूबवैल लगे हुए हैं कहीं और दूसरे साधन हैं । तीसरा प्वांयट मेरा किसान डैम के बारे में है । 1983 में किसान डैम बनाने के बारे में फैसला किया गया था, लेकिन आज तक उस पर एक कदम आगे चलने की बात नहीं हुई । इसमें एक गलती हुई है । वह गलती यह हुई कि 1963 में यू०पी० के जिम्मे डैम की कंस्ट्रक्शन लगा दी और हरियाणा का इस पानी में हिस्से का सवाल रिओपन कर दिया और हम जमना के पानी का 2/3 हिस्सा लेते रहे । मैं अर्ज करता हूं कि इसी हिसाब से जितना हमारा हिस्सा है, वह मिलना चाहिए । मुझे याद है, चौधरी बंसी लाल जी ने उस वक्त यू०पी० के मुख्य मन्त्री श्री त्रिपाठी से बातचीत करके गंगा का बरसाती पानी लेने की कोशिश की थी । बरसात में पानी

लेने की बातचीत की थी और उन्होंने कहा कि गंगा से बरसात में हरियाणा को पानी मिल सकता है । बरसात के दिनों में उनको नुकसान पहुंचता है और इधर हमारी भूमि पानी के लिए तड़पती है । हुस पानी के लिए भी यत्न कर सकते हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे इलाके हरियाणा में आबपाशी करने के पानी की कमी है, यह बात मानकर मैं आगे चलना चाहता हूं । आज हमने कुछ प्रोजैक्ट्स भी हाथ में लिए हैं । जुई कैनल है वह मुकम्मल है । सिवानी पर काम चल रहा है । लोहारू कैनल और जवाहर लाल नेहरु कैनल पर भी काम चालू है । मैं स्पीकर साहब, इस बात से सहमत हूं कि उस इलाके के हालात को देखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा सहूलियत उसे दें, चाहे वह पानी की है या दूसरी हैं, लेकिन एक बात जरूर अर्ज करूंगा । ये जो प्रोजैक्ट्स हैं और जितना पानी हमारे पास है उसकी तकसीम हम किस तरह से करें यह एक अहम सवाल है । मुख्य मन्त्री जी ने पिछली दफा बोलते हुए कहा कि तीन हजार क्युसिक्स पानी हमने बढ़ाया है । इसमें इन्होंने ट्यूबवैल्ज भी लगाए हैं, वाटर कोर्सिज पक्के किए हैं और नहरों को पक्का करने लग रहे हैं । लेकिन इसमें एक बात देखने की है । जहां तक मुझे ज्ञान है, जो डायरैक्ट ट्यूबवैल आपने लगाए, वे कामयाब नहीं हुए हैं । नरवाना एरिया में 100 के करीब ट्यूबवैल्ज लगने थे, लेकिन इस वक्त केवल चालीस या पचास लगे हैं । इससे यह हुआ कि पास के जितने कुछ थे, उनका पानी खुश्क हो गया और आखिर वे बन्द करने पड़े । पलवल के एरिया में भी ऐसी ही पोजीशन है । इसी

तरह से वैस्टर्न जमुना एरिया के साथ-साथ हुआ । कोई ज्यादा दूर नहीं, स्पीकर साहब अगर आप बिझौल जाएं, और वहां रैस्ट हाउस से थोड़ी दूर के आसपास के गांव में जाकर देखें तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है । मैं वहां गया हुआ था । अभी तीसरा ही दिन था इन डायरैक्ट ट्यूबवैल्क को चालू हुए जो आपने नहरों में पानी डालने के लिए लगाए हैं । गढ़ी बादशाहपुर वहां एक गांव है । वहां मैं गया । मैंने देखा कि जितने कुएं वहां थे वे सब खुश्क थे । जोहड़ों का पानी खुश्क हो गया था । 60 फुट की गहराई पर जिन ट्यूबवैल्ज से वे पानी ले रहे थे, वे भी पानी देना बन्द कर गए । दो सौ फुट वाले ट्यूबवैल्ज भी मैंने देखे, उनके पम्प भी पानी को ऊपर नहीं उठाते थे । बात क्या हुई? इंजीनियर ने जो प्रोजैक्ट बनाया, डायरैक्ट ट्यूबवैल्ज लगाने का वह डिफैक्टिव था । उन्होंने यह बात नहीं देखी कि हरियाणा में जो स्टैटा है, पानी का वह एक है । उसमें जो ऊपरली सतह है, पानी की और निचला जो स्ट्रेटा है, उसकी एक लेयर है । बीच में कोई और इमपरवियस लेयर नहीं है । गहरे ट्यूबवैल्ज चलने जब शुरू होते हैं, वे ऊपर का पानी भी खींच जाते हैं और नीचे का पानी भी खींच जाते हैं और सारे ट्यूबवैल्ज और कुएं आदि खुश्क हो जाते हैं । इसी तरह की पेचीदगियां, मुख्य मन्त्री जी को भी इल्म होगा, यहां भी पैदा हुई हैं । स्पीकर साहब, आज हमारी सरकार वाटर कोर्सिज को पक्का करने में लगी हुई है । इसकी कौस्ट एक मीरन पर 75 हजार पए बैठती है । आज यह सब उधार लेकर किया जा रहा है और आने वाले सालों में यह मय सूद

लोगों से वसूल होगा । खैर यह तो आगे की बात होगी लेकिन आज हमको देखना चाहिए कि इसका और क्या नुकसान हो रहा है । स्पीकर साहब, जितने नहरी इलाके हमारे हैं, जैसे करनाल का इलाका है, रोहतक, सोनीपत आदि का इलाका है, उसमें पानी नीचे बहुत खारी है । ऊपर का सीपेज का पानी जाने से तो पीने का पानी लोगों को मिल जाता है । अगर यह पानी सारे का सारा बन्द हो गया तो बड़ी भारी कैलेमिटी का सामना हरियाणा के लोगों को करना पड़ेगा और पीने का पानी सरकार को देना पड़ेगा जो कि मुमकिन बात नहीं है । जबसे हरियाणा अलग बना है यानी 1966-67 से या 69 से ही आप देखें जब से चौधरी बंसी लाल ने काम करना शुरू किया, कोई 771 गांव और टाउनज को ये पानी दे पातु हैं । स्पीकर साहब, मुझे हैरानी हुई यह बात देखकर कि जिला रोहतक और जींद, सोनीपत आदि में जहां कि पीने के पानि की कोई मुश्किल नहीं थी, वहां बहुत से कुओं का पानी खारी हो गया, क्योंकि सीपेज का पानी बन्द हो गया और नीचे पानी है नहीं । हरेक गांव में यह कसर पैदा हो रही है । अब यह कैसे हरेक गांव को पानी दे सकते हैं, जबकि करोड़ों रुपए खर्च करके अभी तक 6-7 सौ गांव को पानी दे पायु हैं । सारे गांव को पानी देना इनके बस की बात नहीं होगी । (घंटी) स्पीकर साहब, मैं थोड़ा-सा टाईम और लगा । मैं यू ० पी० में गया था । वहां उन्होंने इसी तरह चैनल्ज को, नहरों को पक्का करने का प्रोग्राम बनाया था । उनके जो इंजीनियर्ज हैं, उनसे मेरी बात हुई । उन्होंने कहा कि हमने यह प्रोग्राम छोड़ दिया । छोड़ने

का मुख्य कारण यही बताया कि जितने ट्यूबवैल्ज थे, प्राईवेट वैल्ज थे, उनका पानी खुश्क हो गया या खारी हो गया । उन्होंने मुझे बताया कि अब वे ट्यूबवैल्ज से पानी निकालकर कच्ची नहरों में डाल देते हैं । हमसे पानी का उपयोग भी हो जाता है और सीपेज भी बन्द नहीं होता । जिद्द की बात नहीं है । इससे कहीं ऐसा न हो कि कहीं औरे कठिनाई और समस्या हुस प्रान्त के लिए पैदा हो जाए । स्पीकर साहब, वित्त मन्त्री साहब ने अपनी स्पीच में हरियाणा में जरई पैदावार बढ़ाने की बात की है । निस्सन्देह सन 1969 के बाद जरई पैदावार काफी हुई है । लेकिन यदि गौर से देखें कि इन सालों में यह जो पैदावार बढ़ी है इसके क्या मुख? । कारण हैं, किन-किन वजुहात से यह बढ़ी है तो आप देखेंगे कि सन 1950- 51 से लेकर 1971-72 तक जितनी भी कल्चरेबल वेस्ट लैण्ड थी, जितनी भी फ़ैलो लैण्ड थी, वह सारी काशत में आई है । आज हरियाणा में कल्चरेबल वेस्ट लैण्ड कहीं दस बीस एकड़ को छोड़ करके कहीं नहीं है । सारी को तकरीबन नौ तोड कर दिया गया है । 1971-72 में आप देखें कि 15 लाख 58 हजार हैक्टेयर रकबा (कौण्ड एरिया) मजीद जेरे काशत है और क्रोण्ड एरिया में 45 परसेन्ट वृद्धि हुई है । इसके अलावा 1971-72 तक उपज में बढ़ोतरी के और भी कारण हैं । पानी फालतू मित्रा, खाद अच्छी मिली, बीज मिला तथा और भी लोगों को सहूलियात मिलीं । लेकिन. स्पीकर साहब, रकबा ज्यादा जेरे काशत आना भी एक मुख्य कारण है । 1971- 72 के बाद आप देखेंगे कि जब वह रकबा खत्म हो गया तो इनकी पैदावार घटनी शुरू हो गई । यह

सबसे ज्यादा चिन्ताजनक बात है । सारे कागजात और रिकार्ड इस बात को बताते हैं कि 1971-72 के बाद जरई पैदावार बढ़ी नहीं, बल्कि घंटी है । इसके बाद स्पीकर साहब, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जौ प्रति एकड़ उपज है, वहाँ दूसरे प्रान्तों की अपेक्षा कम है । सारी ताकत लगाने के बावजूद भी आज हम अपने देश की दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में, दुनियां की बात आप छोड़ दें, वह तो बहुत आगे है, पीछे है और हमारी पैदावार कम है । 1971-72 में हमारी चावल की पैदावार 18. 3 क्विंटल पर-हैक्टेयर थी । इसके मुकाबले में तमिलनाडु की 20. 1 और पंजाब की 20. 5 है । गेहूँ की पैदावार हमारी 20. 4 और पंजाब की 24.1 है । ज्वार की हमारी 2. 3 तमिलनाडु की 7. 8 और पंजाब की 4. 9 है । दूसरे प्रान्तों में और भी ज्यादा है । बाजरे में हमारे प्रान्त में 7.1 क्विंटल फी हैक्टेयर पैदावार है, जबकि पंजाब में 11.8 और गुजरात में 8. 7 है । इसी तरह से शुगरकेन की पैदावार के आंकड़े भी हमारे बहुत कम हैं ।

इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भूमि पर आज भार बहुत ज्यादा है । जो लोग भूमि पर अपना गुजारा करते हैं, खेती पर अपना गुजारा करते हैं । हरियाणा में उनकी तादाद बहुत ज्यादा है । आज 76 फीसदी के करीब ऐसे लोग हैं, जो जमीन पर गुजारा करते हैं । जहां जमीन पर इतने लोगों का गुजारा है, तो जमीन की उपज भी कम होती चली गई है । तो इससे प्रान्त की इकनोमी पर उल्टा असर पड़ता है । इससे कोई भी इन्कार

नहीं कर सकता ।

मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में फरमाया है कि वे लोग जो खेती का काम नहीं करते हैं, उनको रोजगार देना चाहते हैं । दे पाएंगे, यह मुश्किल है । यह तो सब का काम है । हम सारे मिलकर ही काम में हाथ बंटाए । लेकिन अब एक बात देखें जहां तक हमारी अब तक की नीति है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि हमें बड़ी सफलता मिली है । उसमें आप देखिए कि भूमि पर काम करने वाले, भूमि पर गुजारा करने वाले लोगों की तादाद बढ़ी है, घटी नहीं है । सन् 1870 से अब तक का भी रिकार्ड आप देखें, सन् 1891 में जो आबादी खेती पर गुजारा करती थी, वह 60 फीसदी से ज्यादा नहीं थी । 1901 में वह 65 फीसदी थी । सन् 1911 में 70 फीसदी थी और 1950 में 72 फीसदी थी लेकिन आज वह आबादी 78 फीसदी है, जो जमीन पर गुजारा करती है । दूसरे देशों में इस अर्से में खेती पर निर्भर लोगों की तादाद बहुत कम हुई है ।

आप सन् 1842 और सन 1852 की सैन्सीज रिपोर्ट को देखें, उस टाइम पर खेती मजदूर नाम मात्र भी नहीं थे लेकिन आज खेती मजदूरों की बड़ी भारी तादाद है । आज जो लैण्डलैस हैं, उनके गुजारे का सवाल है और यह समस्या है आज हमारे सामने ।

हमें आज यह देखना है कि किस तरह से ऐग्रीकल्चर

प्रोडक्शन बढ़ सकती है । आज तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घटती जा रही है । स्पीकर साहब आज इस हालत में प्रोडक्शन बढ़ाना कोई आसान बात नहीं है । पानी की कमी है, बिजली की कमी है, जितनी हमें चाहिए, उतनी हमारे पास नहीं है । इसके साथ-साथ जमीन इतने छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटती जा रही है, बड़ी तेजी के साथ, फिर आप कोई भी योजना बनाएं, कोई भी टैक्नीक इस्तेमाल करें, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकती ।

दो या अढ़ाई एकड़ का मालिक ट्यूबवैल नहीं लगा सकता है, वह उपज बढ़ाने में कैसे कामयाब हो सकता है । वह आज कोई भी योजना नहीं बना सकता । ट्रैक्टर का प्रयोग नहीं कर सकता । आज हम देखते हैं कि हमारे प्रान्त में 21 लाख के करीब मालिकान अराजी हैं । एक हैक्टेयर तक के मालिकान नौ लाख से भी ऊपर हैं । अढ़ाई एकड़ से पांच एकड़ तक के दरमियान तीन या साढ़े तीन लाख है । इस प्रकार 12-13 लाख मालिकान ऐसे हैं, जिनके पास अढ़ाई एकड़ से और पांच एकड़ से, कम जमीन है ।

आप सन् 1981 की मर्दमशुमारी देखें, हरियाणा प्रान्त में पांच एकड़ के मालिकान 16 फीसदी थे । आज अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया की भूमि सैन्सीज रिपोर्ट छपी है, उसके अनुसार हरियाणा में आज 88 फीसदी किसान हैं, जो पांच एकड़ से भी कम के मालिकान हैं । सारे देश में पचास फीसदी है और हरियाणा प्रान्त में 88 फीसदी है । इनके मुख्तलिफ कारण हैं ।

एक तो इनहैरिटैन्स ला है । कुछ तो लोगों ने जमीन दूसरों के नाम करा दी, कुछ बेच दी ।

स्पीकर साहब एक बात की तरफ में खासतौर से तवज्जह दिलाना चाहता हूं, वह हिन्दू सकसैशन एक्ट है । हिन्दू सकसैशन एक्ट सन् 1956 में बना । जितनी फरैगमेंटेशन इस कानून की वजह से हुई, शायद इससे ज्यादा और किसी वजह से नहीं हुई । देहली हमारे साथ लगता हुआ सूबा है । आप आश्चर्य मानेंगे कि देहली सूबे में हिन्दू सकसैशन एक्ट लागू नहीं है । वहां बहिन को भाई के साथ बाप के मरने पर हक नहीं मिलता है । वहां तो पहले की भांति केवल लड़के को हक मिलता है । लड़के के बाद दूसरे हकीकियों अथवा को-लेटरज को हक मिलता है, लड़की और बहिन विधवा आदि को नहीं मिलता है । देहली भूमि सुधार कानून की धारा 48, 54 के अनुसार फीमेलज विरासत में अधिकार नहीं ले सकती हैं । यूपी. में भी नहीं मिलता है, वहां भी इसी तरह के कानून हैं । हरियाणा उनके साथ लगता हुआ सूबा है । इसमें एक मालिक के मरने के बाद दस-बारह जगह पर जमीन बंटती है । इस बात को कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । पहले लड़का है, लड़की है, फिर लड़की की लड़की है और लड़की की लड़की न हो तो उसकी लड़की की लड़की हो यानी कोई भी मिल जाए उसको हक चला जाएगा । मुश्किल यह कि लड़कियों को हक मिलने पर उनके पति उन पर दबाव देते हैं कि तुम अपना हिस्सा अलग कराकर बेचकर रकम बनाओ । विरोधियों को वह

बेच जाते हैं, जिससे झगड़े और मुकद्दमेबाजी उनके गले पड़ जाती है ।

Mr. Speaker: wind up. बहुत ज्यादा टाईम हो गया है

।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, अभी खत्म करता हूँ । स्पीकर साहब, आप देखें कि हिन्दू संकसैशन एक्ट इतनी बे-इन्साफी का कानून है, कोई और नहीं हो सकता । शिडयूल्ड दो पर आप देखेंगे कि अगर किसी के लड़का होते हुए भी लड़किया, नहीं है तो फिर son's daughter's, sons's duaghter's daughter, duaghter's sons sons, daughter's son's duaghter, को अधिकार मिलता है अगर मृतक के भाई, भतीजे । चाचा आदि को नहीं । यही नहीं आपदेखेंगे कि अगर चार भाई हैं, एक लावल्द मर जाए, एक की बेवा है, एक के लड़के हैं और चौथा भाई जिन्दा है । सारा हक, मुख्यमन्त्री साहब नोटिस फरमाएं,भाई को मिलेगा,भतीजे को नहीं, भाई की बेवा को नहीं । अगर भाई भी न हो, तो सिर्फ अकेले भतीजे को मिलेगा, फिर भी बेवा को नहीं मिलता है । उसको पांचवीं कैटेगरी में रखा है और आप हैरान होंगे कि मृतक भूस्वामी के नजदीकी रिश्तेदार चाचा, ताया आदि दो तीन पीढ़ी में मिलने वालों की अपेक्षा brother's duaghter, sister's duaghter, mother's mother, mother's mohter's sister आदि को अधिकार जाएगा और इनकी अपेक्षा फादर्ज, विडोज वगैरह बाद में हैं । यह कानून इस किस्म का है, जिसमें बेइन्साफी

है, फरैगमेंटेशन बड़ी भारी हो रही है । जब तक इस विधेयक में कोई तरमीम नहीं देंगे, आप बेशक कहते रहें, जमीन की पैदावार नहीं बढ़ेगी ।

जिस प्रान्त में अढाई एकड़ तक के 9-10 लाख मालिकान बैठे हैं, उसमें क्या स्कीमें कामयाब होंगी । मार्जनल, मार्जनल फारमर्ज की स्कीम है, उनका कितना इम्पैक्ट है, यह सब को मालूम है । स्पीकर साहब, आज हरियाणा में 90 फीसदी किसान मफरूर हैं । बहुत सारे किसानों की सारी जमीनें बैंक में रहन लिखी हुई हैं । आज उनकी सारी जमीन रहन रखी हुई है, चाहे सिक्योरिटी के तौर पर दी हुई है, या वैसे ।

हम देहातों में को-आप्रेटिव बैंक वालों को वसूली के लिए काग करते देखते हैं । सैक्शन 67-ए की रू से कर्ज की वसूली पालिया के तौर पर करते हैं । उसके लिए आपने कानून भी बना दिया है । नैशनेलाइज्ड बैंक वाले हैं, या तकावी वाले हैं, उनकी रात को जीप आती है । लोग जीप का खडका सुनते ही ओटडों से कूदते फिरते हैं, ईखों में छुपे फिरते हैं । कोई गडगोयी में छुपता है, चाहे उसमें आंच ही क्यों न हो । वे तो अपनी जान बचाते फिरते हैं । आज इन बेचारों की यह हालत है । वह बड़े भारी ऋणी हैं । अभी रिजर्व बैंक ने सर्वे कराया । रिपोर्ट में बताया है कि हरियाणा में बड़ी भारी तादाद में लोग मकरुज हैं ।

स्पीकर साहब, मैं लास्ट प्वांयट कहना चाहता हूँ । देहली में बैठे हुए जो नीति निर्धारित— कर्ता हैं, उनका ख्याल है कि देश में किसान बड़े धनाढ्य हैं । स्पीकर साहब, एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन सन् 1985 में बना । उसके चेयरमैन श्री धर्म नारायण थे । वे बहुत बड़े घर से हैं, इकोनोमिस्ट भी हैं । उनकी मैंने किताबें भी पढ़ी हैं, आर्टिकल्ज भी पढ़े हैं । बड़े दिलचस्प हैं । उन्होंने लिखा है कि मंहगे भाव बढ़ते जा रहे हैं, पैदावार बढ़ती जा रही है । इसकी वजह से किसान के पास धन इकट्ठा होता जा रहा है । अगर इनका धन नहीं निकाला गया तो देश में इनफ्लैशनरी प्रैशर्ज होकर सारी इकोनोमी द्रहम —ब्रह्म हो जाएगी । इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है और अपनी आर्टिकल में लिखा है कि तीन ही तरीके हैं, जिससे इन पर कन्ट्रोल हो सकता है । नम्बर एक, वे कहते हैं कि इजनास को जो किसान बेचे, उसको सस्ते से सस्ते दाम पर दे, बल्कि वह दाम मार्कीट प्राइस से भी कम हो । जो चीजे उन्हें खरीदनी पड़े वे मंहगी से मंहगी हों, और टैक्स इन पर ज्यादा से ज्यादा लगे । ये तीन सुझाव उन्हें दिए हैं । वे चेयरमैन एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन हैं । इस कमीशन का कोई भी सदस्य किसानों का नुमाइंदा नहीं है ।

हर साल आप वह रिपोर्ट भी देखते रहे हैं । कमीशन की कोई भी रिपोर्ट किसानों के हित में नहीं है । आज भी दाम चाहे गन्ने के हों, बाजरा, ज्वार, चावल या कपास के हो, या गेहूँ के हो, मार्कीट प्राइस से कम हैं । अभी आपने देखा कि अक्तूबर

तक तीन सौ रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर गुड बिक रहा था और बाजरा 175—178 रुपए बिक रहा था ।

इसके बावजूद कमीशन की रिपोर्ट पर बाजरे का 78 रुपए भाव और ईख का साढ़े आठ रुपए प्रति क्विंटल नियुक्त किया गया । इस कारण गुड़ और बाजरे के भाव 200 रुपए व 80 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए । तो मैं ज्यादा तफसील में न जाते हुए इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा । इसके अलावा जो दूसरा तक' यह दिया है कि आज देश की आय (आमदन) का आधा भाग किसानों को मिलता है । कहने का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर सैक्टर की जो कमाई है, वह देश की आमदन में आधी के करीब है । स्पीकर साहब, उन्होंने कहा है कि कृषि क्षेत्र की आमदन 42 फीसदी है । इसलिए उस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगना चाहिए और उसको भाव भी कम मिलना चाहिए । लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची कि 42 फीसदी जो आमदनी है, उसमें आज 76 फीसदी लोग गुजर करते हैं और दूसरे सैक्टर की आमदनी जो 58 प्रतिशत के करीब है, वह आमदनी 24 फीसदी लोग इस्तेमाल करते हैं । उसमें भी 50 प्रतिशत हिस्सा 10 प्रतिशत जो बड़े-बड़े धनाढ्य हैं, उनको मिलता है और बाकी गरीब आदमियों के हाथ आता है । हुस तरह से 10 फीसदी आदमी आज देश की आधी आमदनी इस्तेमाल करते हैं और बाकी 90 प्रतिशत आदमी आधी आमदनी पर गरीबी से तिलमिल रहे हैं और कर्ज से दबे पड़े हैं । तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य

मन्त्री जी समाजवादी प्रोग्राम में यकीन करते हैं और उनकी तकरीरें मैंने सोनीपत में भी सुनी हैं और अखबारों में भी आई हैं । दूसरी जगहों जैसे जिसे और खानपुर के मुकाम पर भी उन्होंने तकरीरे फरमाई और किसानों से हमदर्दी जाहिर की है । जो किसानों के साथ बे-इन्साफी हो रही है, उसको दूर करने में कामयाब होते हैं या नहीं, यह तो वक्त बताएगा । लेकिन मैं बैठने से पहले उनसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्राइसिज के बारे में व फूड जोनज के प्रति कौन आदमी यह कह सकता है कि यह दुरुस्त है । नरेला हमारे एरिया से लगता हुआ दिल्ली सूबा में है । सूबा दिल्ली में फसल के मौके पर अढाई सौ-दो सौ रुपए के भाव से गेहूं बिकता है गुजरात में तीन सौ रुपए बिकता है, लेकिन हरियाणा का किसान मजरूम है, उसके घरों में छापे लगते हैं, क्योंकि वह गेहूं ज्यादा पैदा करता है, उसको मजबूर किया जाता है कि सौ रुपए के भाव वह अपना गेहूं बेचे, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली का किसान अढाई सौ और तीन सौ रुपए के भाव से बेचे । क्या इससे ज्यादा भी कोई बे-इन्साफी हो सकती है । आप कहते हैं कि अनाज की कीमतें कम करनी पड़ती हैं, क्योंकि गरीब आदमी को सस्ता अनाज देना है । ठीक है गरीब आदमी को सस्ता अनाज मिलना चाहिए, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि वह मंहगा खरीद कर अपने बच्चों को पाल सके, चाहे वह मुलाजिम है या हरिजन हैं, या दूसरे गरीब हैं, परन्तु गरीब लोगों को आप कहां सस्ता अनाज देते हैं । 1973 में आपने 75-78 रुपए फी क्विंटल पर गेहूं किसान से लिया और 1974 फरवरी में 105 रुपए के भाव

का एलान किया । देश भर में जितना भी पुराने अनाज का स्टॉक था वह आपने सरकारी डिपोज पर मंहगे भाव बेचना शुरू कर दिया और सरकार ने 136 रुपए और 154 रुपए के भाव पर आटा और गेहूं बेचा । आज सरकार गरीब आदमी के नाम पर किसान से मुनाफा लेवे, क्या यह ठीक है । फटीलाइजर की भी ऐसी ही पोजीशन है । स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी को यह नोट कराना चाहता हूं, चाहे वह तहकीकात कर लें, जिस वक्त

1974 में फटीलाइजर की कीमत बढ़ी, 12-13 लाख टन फटीलाइजर देश के मूखतलिफ डिपोज पर था । 4,000 से ऊपर डिपोज हैं । एक-एक डिपो पर पच्चीस पच्चीस सौ रुपया सरकार ने कमाया । पुराने स्टॉक को भी सरकार ने नए दाम पर बेचा । जो चार-पांच गुना दाम बड़े थे, वह किसान के लिए और कई करोड़ रुपए मुनाफा कमाया । इस सूबे में भी और यूपी. में भी, गेहूं बाजरे और चने के स्कैण्डल हुए। बाहर सरकार अनाज मुनाफे पर बेचती रही । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कम अर्ज कम एक बात तो सरकार के हाथ में है कि इन भोले भाले लोगों को जो बेजुबान हैं, अनजानेपन को एक्सप्लायट तो न करे । आपको इन की पैदावार पर दिल्ली की सरकार से बोनस मिला । उसको आपने किसान को न दिया । सरकार ने यह फैसला कर दिया कि जो बोनस मिलेगा, वह डिवैल्पमेंट के कामों पर खर्च होगा । आज कितने ही ऐसे अदायरे हैं जिनके जरिए सरकार किसानों को बेवकूफ बनाकर मुनाफा कमा रही है । यह बेवकूफ

बनाने की बात खत्म होनी चाहिए । इसलिए मैं आपके द्वारा उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने कहीं हैं, उन पर सरकार गौर फरमाएगी और किसान के साथ जो बेइनसाफी आज इस प्रान्त में और देश में हो रही है, उसको दूर करने में हमारे मुख्य मन्त्री जी और उनकी सरकार पूरा प्रयत्न करेगी और पूरी ताकत से काम करेगी । ऐसी मेरी आशा है कि 20 सूत्रीय प्रोग्राम जिसके बारे में सारे भाई फरमाते हैं, उसको दिल से कामयाब बनाने के लिए भी सरकार काम करेगी और केवल नारेबाजी तक इसको सीमित न रखेगी । स्पीकर साहब, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया । शुक्रिया । (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई ।)

17.00 बजे

चौधरी शिव रामवर्मा (नीलोखेडी) : आदरणीय उपाध्यक्षा, महोदया यह अगले वर्ष यानी 1976-77 का बजट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और इस पर विचार विमर्श चल रहा है । हर साल ही बजट आता है और हमारे वित्त मन्त्री जी अपने सुरीले कण्ठ से, मधुर शब्दों द्वारा अपना भाषण सुनाते हैं । उसे सुनकर हमारी यह आशा बंधती है कि शायद जो पीछे नहीं हुआ, वह आगे जरूर होगा । लेकिन साल गुजर जाने के बाद फिर नतीजा वही मिलता है । अभी चौधरी रिजक राम जी ने सारी बातें काफी खोलकर आपके सामने रखीं हैं । किसान की हालत उन्होंने बतलाई । वह सौ फीसदी सही है । लेकिन सरकार को पता नहीं कि किसान की हालत आज क्या है । पता नहीं वे क्यों यहां आकर भूल जाते हैं

। आते गांव से हैं, रहते किसानों के बीच में हैं, लेकिन यहां बैठकर किसानों की हालत मूल जाते हैं और अपने मन में यह सोचते हैं कि किसान तो पता नहीं कितना अमीर हो गया । मैं कुछ थोड़े से आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं । मैं यह बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से कितना खर्च करने के बावजूद सरकार ने भी खर्च किया और किसान ने भी बच? किया, पैदावार घटी या वहीं की वहीं रही । जब खर्च ज्यादा और पैदावार वहीं रही, तो इसका मतलब यह हुआ कि पैदावार मंहगी रही, लेकिन सरकार ने उसको सस्ता बेचने का प्रबन्ध करके किसान को मारने का प्रयत्न किया । जैसे कि चौधरी रिजक राम जी ने कहा, मैं समझता हूं कि जो धर्म नारायण की किताब में सिफारिश की गई है, वह एक सोची समझी तरकीब से किसान को खत्म करने की बात चल रही है, क्योंकि तीनों बातें कि किसान की पैदावार सस्ती बिकवाओ, किसान की जो जरूरत की चीजे हैं, वह मंहगी दो और उस पर टैक्स लगाओ, उसी का एक हिस्सा है और किसान को मारने वाली हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अधिक इस ओर न जाते हुए आपके सामने नहरों और खेती के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । कहा जाता है कि खेती पर नहरों पर काफी खर्च हुआ और नहरों की लम्बाई काफी बढ़ी है । मैं इस बारे में आंकड़े पेश करना चाहता हूं— 1 967-68 में नहरों की लम्बाई 5 हजार 668 मील थी वह 1974-75 में 6 हजार 519 मील लम्बी हो गई, यानी 853 मील लम्बी बढ़ी और इस लम्बाई को बढ़ाने पर काफी खर्चा हुआ । इसके साथ ही आप टयूबवैलों

की बात लें, क्योंकि मैं सबसे पहले सिंचाई की बात करने लगा हूँ । 1967-68 में बिजली 5 हजार 368 लाख किलोवाट पैदा होती थी और 1974-75 में 12 हजार 384 लाख किलोवाट पैदा हुई और फिर उसमें से किस प्रकार खेती के लिए दी गई, यानी 1967-68 में खेती के लिए 20.5 प्रतिशत दी जाती थी और 1974-75 में कुल पैदावार यानी 12 हजार छह 4 लाख किलोवाट का 44.1 प्रतिशत खेती के लिए दी गई और ज्यादा बिजली दी गई, तो किसान को पैसा भी ज्यादा देना पड़ा । 1967-68 में 32,989 ट्यूबवैल्ज थे, लेकिन 1974-75 में 1 लाख 84 हजार 740 ट्यूबवैल्ज और पंपिंग सैट्स लगे । इस पर भी किसान का खर्च काफी हुआ । सरकार ने भी इस पर पैसा खर्च किया लेकिन वह पैसा भी तो किसान को ही अदा करना पड़ेगा । बिजली, नहर, ट्यूबवैल्ज आदि पर इतना खर्च करने के बाद भी पैदावार जो बढ़ी उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ । 1967-68 में 39 लाख 70 हजार टन पैदावार हुई थी और 1968-69 में 27 लाख 64 हजार टन हुई । 1973-74 में 38 लाख 36 हजार टन हुई यानी 1967-68 से भी कम पैदावार हुई । 1974-75 में 33 लाख 37 हजार टन पैदावार हुई । अगले सारन का अनुमान ज्यादा है । मैं अनुमान की बात नहीं करता । मैं तो सिर्फ सरकार के आंकड़ों की बात करता हूँ, यानी इतना खर्च करने के बाद भी पैदावार घटी है, बढ़ी नहीं है और इसका असर किसानों पर पड़ा है, क्योंकि किसानों को ज्यादा खर्च करके पैदावार करनी पड़ी । इसप्रकार पैदावार महगी पड़ी । डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब आप

रकबे में जो बढ़ौतरी हुई, वह भी देखे । 1967-68 में नैट छुरिया जो बोया गया वह है 35 लाख 14 हजार हैक्टेयर, 1968-69 में 32 लाख 73 हजार हैक्टेयर और 1973-74 में 35 लाख 88 हजार हैक्टेयर । इसका मतलब हुआ कि इतना खर्च करने के बाद 52 हजार हैक्टेयर बढ़ा । टोटल क्राप्ड एरिया, जो 1967-68 में था, वह है 51 लाख 50 हजार हैक्टेयर, 1968-69 में 40 लाख 53 हजार हैक्टेयर था और 1973-74 में था 51 लाख 50 हजार हैक्टेयर । यानी 1967-68 में भी उतना ही एरिया था और 1973-74 में भी उतना ही । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इसमें कोई बढ़ौतरी नहीं हुई । खेती की ज्यादा पैदावार हुई, आप उसका भी हिसाब सुन लीजिए । एवरेज ईल्ड आफ फूडग्रेन पर-हैक्टेयर किलोग्राम 1967-68 में 1 हजार 5 किलोग्राम 1968-69 में 887 किलोग्राम पर हैक्टेयर, 1973-74 में 928 किलोग्राम पर-हैक्टेयर । डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1967-68 में पर हैक्टेयर 1005 किलोग्राम थी और 1973-74 में 928 किलोग्राम रह गई, यानी पैदावार घटी । पैदावार घटने का असर किस पर पड़ा, वह भी किसान पर पड़ा, क्योंकि किसान ने ज्यादा खर्च किया और उसको कम रिटर्न मिली । सरकार ने जो कुछ खर्च किया वह तो सरकार किसानों से वसूल कर ही लेगी । सिंचाई के साधन भी बढ़े । किसान ने और सरकार ने पैसा भी -द्य-वादा खर्च किया लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी आंकड़ों के अनुसार पैदावार नहीं बढ़ी! रकबा नहीं बढ़ा, पर-हैक्टेयर पैदावार नहीं बढ़ी । इसका आखिरी जो परिणाम निकला वह किसानों को

कमजोर करने का निकला । सरकार ने कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया कि खर्च करने के बावजूद भी कोई बढौत्तरी नहीं हो रही है । हमारे भाई यहां बैठकर सोचते हैं कि हम खेती की वजह से मौज कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि वह खेती की वजह से मौन नहीं कर रहे हैं, वह किसी और चीज की वजह से मौज कर रहे हैं । उनको याद करना चाहिए कि वे खेती की वजह से आनन्द नहीं उठा रहे हैं । उन्हें याद करना चाहिए कि खेती वाले की कितनी मौज हो सकती है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसीलिए मैंने सारे आंकड़े आपके द्वारा सदन के सामने रखे हैं । सारे देश के अन्दर हमारे प्रान्त का बड़ा शोर-शराबा है कि इतनी पैदावार बड़ी है । यह सारे आंकड़े भी मैंने सरकार की किताब से ही रखे हैं और यह अपने आपमें मुंह बोलती तस्वीर है कि न हरियाणा प्रान्त की पैदावार बड़ी है, न किसानों की पैदावार बड़ी है । मैं आपके द्वारा अपनी सरकार से और अपने वित्त मन्त्री महोदय से कहना चाहता है क्योंकि उन्होंने बजट अनुमान के भाषण में कहा है कि 16 करोड़ 30 लाख का जो घाटा है, यह शायद कर लगाकर पूरा करना पड़े । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हर बार किसानों पर कर लगाया जाता है, लेकिन इस बार कृपा करके जो टैक्स लगे वह किसान पर न पड़े । आखिर पड़ेगा, तो किसान के ऊपर किसी न किसी तरह, लेकिन उनकी समझदारी इसी में है कि वह टैक्स गरीब आदमी पर और किसान पर न पड़े वरना किसान की हालत और भी खराब हो जाएगी । चौधरी रिजक राम ने बताया कि किसान जो पैदा करता है, उसका क्या भाव है और

जो चीज उसको दी जाती है, उसको कितने मंहगे भाव पर सप्लाई की जाती है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, खेती के लिए किसान को फर्टीलाइजर खरीदना पड़ता है और उसका भाव आप देखे 1973-74 में यूरिया का भाव 53 रुपया परबैग था, 1974-75 में 104 रुपया पर बैग हो गया और 1975-76 में 104 रुपया वारना 96 रुपया पर बैग कर दिया और अब ढोल पीटते हैं कि हमने कम कीमत कर दी । बढ़ाया तो इन्होंने 53 रुपए प्रति बैग से 104 रुपए प्रति बैग और घटाया है 104 रुपए प्रति बैग से 96 रुपए प्रति बैग । तो इसलिए यह इतनी मंहगी खाद डालने से किसान के पल्ले क्या रहा । दूसरी एक और किस्म की खाद है, डाई अमोनियम फास्फेट (डी.ए.पी.) जो किसान समझते हैं कि सबसे बढ़िया है । यह 1973-74 में 66.81 पैसे पर-बैग थी और 1974-75 में 192 रुपए पर-बैग इसकी कीमत हो गई और अब 1975-76 में इसको घटा दिया और 14 रुपए पर-बैग कर दी यानी सारा बोझा गरीब किसान के ऊपर ही पड़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद मैं लैण्ड रेवेन्यू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा कि वह पिछले वर्ष ही कई गुणा बढ़ाया गया और अब इस साल इस फसल में आख्यान) जो था, वह ढाई से तीन गुना हुआ है, सीधी ही छलांग लगाई है इस सरकार ने किसान की गर्दन तोड़ने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए यह सब कुछ सरकार ने किया है । उसी प्रकार बिजली को भी ले लीजिए पिछले साल थी 1 5 पैसे यूनिट

और इस साल 19 पैसे यूनिट मिली है । बैंकों का ब्याज पहले 9 रूपए सैकड़ा था और अब 12 से 18 रूपए सैकड़ा हो गया है । इसके साथ साथ आप डीजल की भी बात ले लीजिए, पिछले साल 90 पैसे लिटर था और इस साल यह बढ़ाकर 1. 41 पैसे पर-लिटर कर दिया है । आप देखें कि एकदम कितनी लम्बी छलांग लगाई और एकदम 51 पैसे पर लिटर डीजल का रेट बढ़ा दिया गया । पिछले साल जो ढोल 220 लिटर का होता है, और 198 रूपए में आता था इस साल वही ढोल 310. 20 पैसे में आ रहा है । यह सब कुछ किसानों को दबाने के लिए किया गया है और इस के साथ-साथ जो मजदूरी थी, वह भी एक दम छलांग लगा कर बढ़ गई है, मजदूर का भी इसमें कोई कपूर नहीं क्योंकि आजकल मंहगाई भी बहुत ज्यादा है जिसका ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है । 31 दिसम्बर को सरकार ने एक नोटीफिकेशन जारी किया था, जिसमें मजदूर की मजदूरी बढ़ाई गई है । उपाध्यक्ष महोदया सरकार को कम से कम किसान की हालत को देखना चाहिए क्योंकि इन सभी बढ़े हुए भावों का असर डायरैक्ट किसान पर पड़ता है, जिस को सहन करना किसान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है । जैसा मैंने ऊपर बताया कि खाद का भाव बढ़ाकर 53 रूपए पर-बैग से 104 रूपए प्रति बैग कर दिया, डी.ए.पी. खाद 66. 81 पर-बैग थी, उसको बढ़ाकर 140 रूपए पर बैग कर दिया, बिजली 15 पैसे पर यूनिट से बढ़ाकर 19 पैसे कर दी, लैण्ड रेवेन्यू बढ़ा जो आब्याना था, वह ढाई से तीन गुना कर दिया, डीजल जो था वह 90 पैसे से 1.41 पैसे पर लिटर कर दिया,

मतलब कि सारी चीजों के भाव बढ़ा दिए गए जब डीकल का भाव 90 पैसे लिटर था, तब गेहूं का भाव 120 रुपए और 130 रुपए क्विटल, धान का भाव था 80 रुपए से 120 तक, मोटी जीरी 80 रुपए और बासमती 120 रुपए क्विटल और अब 1974-75 में धान बिका । 74 रुपए से 90 तक यानी 74 रुपए से हाई यीलडिंग 90- 95 तक बिका, धान बासमती, गेहूं 105 रुपए क्विटल, 120- 130 रुपए-पर-क्विटल की बजाय 105 बिका, उधर भाव बढ़े., और इधर पैदावार के भाव कम हो गए । मतलब कि किसान को अपनी खेती बाड़ी के लिए जिस-जिस सामान की जरूरत होती है, उन सब चीजों के भाव तो बढ़- गए, लेकिन उसकी पैदावार के भाव बहुत ही घट गए तो इस प्रकार किसानों की हालत बिगड़ती चली गई । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि यह सरकार किसानों के बारे में समझ ही नहीं सकी या फिर समझने की कोशिश भी नहीं की गई या फिर जानबूझ कर किसानों को मारने की योजना बना रही है । फिर किसानों पर टैक्स लगाने की कोशिश भी की जा रही है, डायरैक्ट तो लगाए जाते हैं अब इन-डायरैक्ट टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर किसान कंजूमर बनेगा, तो उस पर टैक्स लगेंगे ही । सो मेरा सुझाव है कि किसानों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी दयनीय स्थिति को सुधारना चाहिए । किसानों की दूसरी जरूरत की चीजें भी ठीक दाम पर नहीं मिलतीं । उनके लिए प्रांतीय सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया कि वह सही दामों पर चीजे ले सकें । आप यूक बात ही ले लीजिए । राशन की

दुकानों में चीनी 400 ग्राम प्रति व्यक्ति एक महीने के लिए मिलती है, कभी साढ़े' तीन सौ ग्राम भी मिलती है, अगर वे बेचारे इस चीनी की नस्वार भी ले तो भी खत्म हो जाए, इतनी थोड़ी चीनी होती है, खाने की बात तो छोड़िए । इसके अलावा उन्हें कई गुना चीनी बाजार से खुले दामों पर खरीदनी पड़ती है, जो कि बहुत मंहगी होती है, इससे किसान का बोझ और बढ़ता है और इसके साथ में यह बताऊं कि सरकार का चीजों के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है । आप किसी भी चीज की बात करें, सभी चीजें । प्रान्त से बाहर बेची जा सकती हैं, लेकिन किसान अपना गेहूं अपने प्रान्त से बाहर नहीं बेच सक्ता । अगर उसकी गाड़ी का मुँह यमुना की तरफ देखा जाता है तो उसे झट से गिरफ्तार कर लिया जाता है चालान किया जाता है और जेल में बन्द कर दिया जाता है कि तू तो स्मगलिंग के लिए यूपी. की तरफ अपना गेहूं ले जा रहा था और या फिर रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है । इसलिए सरकार किसान की हालत को समझने का प्रयत्न करे तभी तो इसका भला हो सकता है किसान तो देश की रीढ़ की ली है वह तो मंहगाई से इतना तंग है उस पर बहुत से कर्जे चढ़े हुए हैं । रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए तो आदमी सीधा बैठ भी नहीं सकता खड़े होने की बात तो छोड़ो । इसी प्रकार किसान कमजोर होगा तो हरियाणा भी उन्नति नहीं कर सकता । तो इस लिए मैंने यह बताया कि किसानों के ऊपर किस तरह से बोझा बहाया जा रहा है और दूसरी तरफ गेहूं के भाव कितने कम होते जा रहे हैं लेकिन सरकार हर सात्र कहती है कि हम किसानों के लिए यह कर रहे हैं

वह कर रहे हैं लेकिन इसका सही नक्शा मैंने आपके सामने रखा है । इस का परिणाम यह होगा कि किसान कमजोर होगा । उपाध्यक्ष महोदया, किसान की हालत इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह अपना कर्जा उतारने के काबिल भी नहीं रहा । जैसे कि हमारे भाई चौधरी रिजक राम जी ने कहा कि किसान जीप की लाईट को देखकर कि जब सरकारी जीपें उनके दरवाजे पर कर्ज की वसूली के लिए आती हैं घर से बाहर भाग जाते हैं, चाहे बाहर तूफान हो, बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी हो । सारी तकलीफें गरीब किसानों पर ही आती हैं । आप हवालातों में जाकर देख लीजिए, वहां पर कोई अमीर आदमी, सरमाएदार नहीं होगा, वहां पर सभी गरीब आदमी ही होंगे, जिनके घर में खाने को दाना भी नहीं है— (घंटी) । उपाध्यक्ष महोदया, अभी तो शुरू किया था हैने

उपाध्यक्ष । : आपको 25 मिनट बोलते हुए हो गए हैं —

चौधरी शिव राम वर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, 10-15 मिनट ही मुझे बोलते हुए हो गए हैं., मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा । मैं पहले मोबिल आयल की बात को कहना भूल गया था । मोबिल आयल एकदम इतना चढ़ गया है कि क्या बताएं । पहले पांच लिटर का डिब्बा 10 रुपए का होता था, फिर 24 का हुआ, और अब 55 से 60 रुपए हो गया है, कुछ हिसाब ही नहीं है । चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, पैदावार के भाव कम हो रहे हैं । पैदावार भी कम होती है । पहले 10 मन पैदावार होती थी और अब घटकर 9 और 8 मन की पैदावार होगई है । यह इन की किताबों

के आंकड़े है जो अभी मैंने बताए हैं । उपाध्यक्ष महोदया, भाव इतने कम होने से आप ही बतलाइए कि किसानों को कहा पड़ता खाएगा । तो इस लिए इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए । यदि नहीं सोचेगी, तो कुछ दिनों में स्थिति डावांड़ोल हो जाएगी ।

इसके बाद यह जो कर्जों का जिक्र आया कि गरीब आदमियों के कर्जें मुलतवी कर दिए । माफ करने की बात नहीं कही, लेकिन मुलतवी करने में भी एक बात और कह दी । वित्त मन्त्री महोदय ने ब्रैकिट में उसमें लिख दिया सरकारी कर्जों को छोड़कर' । तो सरकारी कर्जें नहीं हटाए, उनकी वसूली भी नहीं हटाई । चाहे वे कर्जें बैंक से लिए हों, को-आप्रेटिव सोसायटी से लिए हों, तहसीलदार से लिए हों, या बीडीओ से लिए हों, उनके मुलतवी करने का कोई जिक्र नहीं है । मैं तो यह कहता हूं कि अगर यह सरकार सही मायनों में गरीब लोगों की मदद करना चाहती है, तो जितने भी कर्जें हैं, उन सब को माफ कर दे, चाहे वे कहीं से भी लिए गए हों । फिर तो मैं समझता हूं कि लोगों को एहसास होगा कि यह सरकार हमारी भलाई कर रही है । लेकिन अब जो आपने किया है, इससे तो आपने उनकी लड़ाई छिडवा दी है । जिस आदमी ने किसी साहूकार से कर्जा लिया है, उसका तो आपने मुलतवी करवा दिया, लेकिन जिसने बैंक से या को-आप्रेटिव सोसायटी से लिया है, उसका मुलतवी क्यों नहीं करवाया? जिसने साहूकार से कर्ज लिया है, वह भी गरीब है और

जिसने बैंक या सोसायटी से लिया है, वह भी गरीब है, तो दोनों में मतभेद क्यों रखा गया है । तो यह जो कर्जों का इस तरह से ढोंग रचा गया है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है । मैं तो यह कहूंगा कि अगर आपने गरीब लोगों को राहत देनी है, तो सभी किस्म के कर्ज माफ होने चाहिए और आगे के लिए उनको अपने मकान बनाने के लिए या और जरूरतें पूरी करने के लिए जो पैसा चाहिए वह बिना सूद और बिना जमानत के उनको दिया जाए, तब लोगों की हालत सुधरेगी । अगर आप जमानत मांगेंगे तो गरीब आदमी जमानत कहां से लाएगा । जमानत के लिए वह किसी बा-हैसियत आदमी के पास जाएगा और वह आदमी क्यों उसकी जमानत देगा । या तो जमानत देने वाला उससे कुछ हिस्सा मांगेगा और या उसे इनकार कर देगा । इसलिए जमानत वाला काम बन्द होना चाहिए और ब्याज भी बन्द होना चाहिए तब जाकर वह कुछ पैसा बचा सकेगा, नहीं तो ब्याज पड़ता रहेगा । कर्जा मुलतवी के कारण लोगों ने गरीबों को कर्जा देना बन्द कर दिया है, क्योंकि वे डरते हैं कि जो पिछला दिया हुआ है, अभी तो वही मिलना मुश्किल है, आगे कहां से दें । आज लोगों की हालत बहुत खराब है, इसलिए सरकार उनको रुपया देने का इन्तजाम करे । यदि हम उनकी हालत सुधारना चाहते हैं, तो सब से बड़ा काम हमें यह करना होगा कि छोटे उद्योग, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग ये जबरदस्ती गांव में हमको चलाने पड़ेंगे । सरकार को यह नहीं देखना चाहिए कि लोग उसकी खुशामद करें, तब उनको 500 या 1000 रुपया कर्जा दें । जिस ढंग से अब लोन मिलता है,

इसके लिए तो बेचारे को दो चार महीने इधर-उधर भागदौड़ करनी पड़ती है और फिर कर्जे की राशि में दो चार सौ खर्च भी करना पड़ता है तब जाकर कर्जा मिलता है, तो इस प्रकार उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता । अगर आपने उसकी मदद करनी है, तो आप उसके धर के अन्दर उद्योग लगाएं और उसको पूरा प्रशिक्षण दें, प्रशिक्षण देने के बाद उद्योग उसे सौंप दें, फिर वह अपनी हालत सुधार सकता है । आज घरों में पुराने ढंग के सारे उद्योग बन्द हो गए हैं । पहले स्त्रियां घर में कपास बेलती थीं, कपास से रूई और बिनौले अलग निकाल कर रूई को कातती थीं, इसी तरह जुलाहे घर में कपड़ा बुनते थे और लुहार खेती के औजार बनाते थे लेकिन आज ये सब काम बन्द हो गए हैं । बन्द इसलिए हुए हैं, कि उनको पड़ता नहीं खाता । इसी तरह से कोहलू से गन्ना पेलते थे, उसमें से काफी खराब चला जाता है और जो थोड़ा बहुत बचता है उसका गुड़ सस्ता बिकता है, इसलिए गांव के कोहलू बन्द हो गए । तो सरकार ने कुटीर उद्योग सारे बन्द कर दिए और अब फिर प्रचार है कि फिर शुरू करेंगे । पता नहीं कब करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे चौधरी रिजक राम जी ने एक बार एक बात सुनाई थी कि एक आदमी था वह जब रात को अपने बच्चों के साथ खाना खाने बैठता है, तो उसके बच्चे उसे कहते हैं कि बापू कोई बात सुनाओ तो वह कहता है कि मैं एक दो हजार रुपए की भैस खरीद कर लाऊंगा उससे हम लोग खूब दूध घी मक्खन और लस्सी पीआ करेंगे । रोटी खाने के टाइम रोज बच्चे उसे कोई बात सुनाने के लिए कहते और वह

वही बात सुनाता जाता । एक महीना बीत गया तो एक दिन उसकी घर वाली कहने लगी कि क्यों यूँ ही बच्चों को बहकाया करते हो, भैस तो आपने लानी नहीं है, क्यों बच्चों को झूठ बोलते हो । तो बच्चों ने फिर बात सुनाने के लिए कहा तो उसने कहा तुम्हारी माँ गुस्से होती है, वह कहती है कि तुमने भैस लानी तो है नहीं और यूँ ही बात क्यों सुनाते हो, तो बच्चे कहने लगे कि बापू भैस चाहे न लाओ, लेकिन बात सुना दो, क्योंकि हमारा दिल लगा रहता है, तो ये भी वही बात कहते हैं कि जमीन देंगे, कहां से जमीन देंगे —(घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं जल्दी ही खत्म कर रहा हू ।

उपाध्यक्ष : आपको बोलते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया, दूसरे आनरेबल मेंबरों ने भी बोलना है, इसलिए आप अब खत्म करें ।

चौधरी शिव राम वर्मा : मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा । अब यह रुपए का जो लारा देते हैं, पहले जमीन का लारा दिया था, जिसकी वजह से लोगों ने बटाई पर जमीन देनी छोड़ दी, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर गिरदावरी मुजारे के नाम हो गई तो कचहरी में झगड़ा चलेगा । इसके बाद थोड़ा सा मैं बिजली बोर्ड के बारे में बता दूँ । सारे हरियाणा में कुल 6,669 गांव हैं, लेकिन विलेज इलैक्ट्रिफाई इन्होंने किये हैं 8,73 1 तो ये 82 गांव पता नहीं कैसे बढ़ गए । या तो इन्होंने मुहल्ले गिन लिए होंगे, तो इनको

Deputy Speaker : Shri Verma Ji, please wind up

your speech.

चौधरी शिव राम वर्मा : एनुअल रेट आफ ग्रोथ जो हुआ है, वह 1967-68 में था, 6.5 प्रतिशत, 1988-89 में वह रह गया 3.9 और 1973-74 में 5 प्रतिशत तो 1967-68 में 8.5 था और 1973-74 में 5 रह गया इसके बाद पर-कैपिटा इन्कम 1967-68 में 399 थी और 1968-69 में रह गई 354 और 1973-74 में 433 यानी 1967-68 से सिर्फ 34 रुपए बड़ी, तो इस तरह यह खुशहाली का नक्शा आपके सामने है । इसके बाद मैं पशुधन के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि पशुधन भी किसान के साथ चलता है, तो पशुधन के बारे में इस सरकार ने जितना प्रचार किया, उतना काम नहीं किया । क्योंकि गरीब को एक भैंस अगर कर्जे पर दे भी दी तो क्या हुआ, अगर भगवान न करे कि भैंस मर जाए या दूध से भाग जाए, तो बेचारा कहां से देगा कर्जा इसलिए इसमें उसको सुविधा मिलनी चाहिए । यदि पशुधन बढ़ाना है, दूध बढ़ाना है, तो आप उसे इतनी रियायत दें जिससे कि वह आगे बढ़ सके । अगर पशुधन बढ़ेगा, तो दूध बढ़ेगा जिससे देश की ताकत बढ़ेगी क्योंकि दूध के बिना अनाज की लागत ज्यादा होती है, अनाज का खर्च ज्यादा होता है

श्री के० एन० गुलाटी : आन ए प्वांयट आफ आर्डर । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप टाइम फिक्स कर दे या फिर जब आप बैठने के लिए किसी मੈबर साहब को कहे तो उसे बैठ जाना चाहिए । हमने भी बोलना है इसलिए मੈबर साहब को जब आपने कह

दिया तो उसे बैठ जाना चाहिए ।

चौधरी शिव राम वर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेंबर साहब मेरा टाइम खामख्वाह खराब कर रहे हैं, इस तरह से बीच में बोल बोल कर, यह ठीक नहीं है.....

उपाध्यक्षा : आपको पता होना चाहिए कि बजट की डिसकशन पर बहुत सारे बोलने वाले हैं इसलिए आप अब वाईड-अप करें और बैठ जाएं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : बस जी मैं अब खत्म ही करने लगा हूं । तो मैं अर्श कर रहा था कि पशुधन के बिना दूध नहीं बढ़ेगा । अगर एक आदमी चार रोटियां खाता है उसे एक गिलास दूध मिल जाए तो तीन रोटियां खाएगा और एक गिलास लस्सी का मिल जाए तो दो रोटियां खाएगा और इस तरह अनाज का खर्चा घट जाएगा । अनाज की पैदावार तो कहते हैं बड़ी है लेकिन जिस हिसाब से अनाज की पैदावार बड़ी होगी उसी के हिसाब से कहते हैं कि आबादी भी बढ़ी है और आज सारे देश में पचास लाख टन अनाज बाहर से मंगाने की सोच रहे हैं । इस लिए हमें जहां खेती की पैदावार को बढ़ाना है वहां यह भी बहुत जरूरी है कि पशु धन को भी बढ़ाया जाए और उसकी तरक्की की जाए क्योंकि पशु धन के बढ़ने से दूध की पैदावार बढ़ेगी । यह पशु धन तब बढ़ेगा अगर हम इसके लिए लोगों को इनसैटिव देंगे पशु पालन की सारी सुविधायें देने बिना ब्याज के कर्जे देंगे और उसकी वसूली भी

आसानी से करेंगे । इसी तरह से खेती भी बगैर इनसैंटिव के नहीं बढेगी ।

गृह ताय़ा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्रीमती शारदा रानी) :
आन ए प्वांयट आफ आर्डर मैडम । मैं मैंबर साहब से यह कहना चाहूंगी कि वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें । उन्होंने 1980-61 के आंकड़े कोट करके बताने की कोशिश की है कि हमारी पर-कैपिटा इनकम 1967- 68 में 389 रुपए थी 1969-70 में 429 रुपए और 1974-75 में 431 रुपए थी लेकिन यह आंकड़े जो हैं ये 1980-61 के प्राइस इनडैक्स के आधार पर हैं जो कि उन्होंने गलत तौर पर पढ़े है और हाउस को गुमराह करने की कोशिश की है -- (विघ्न) - मेरा निवेदन है कि आज की प्राइस के आधार पर 1973-74 की पर-कैपिटा इनकम 1168 रुपए हैं । उनका गलत तौर पर पुराने आंकड़े कोट करके हाउस को मिसलीड करना उचित नहीं है, यह मेरा निवेदन है ।

चौधरी शिव राम वर्मा : 1960-61 की प्राइस सब पर लागू होगी 1973-74 पर भी लागू होगी और दूसरे सालों पर भी लागू होगी । तो हस्में फर्ज क्या निकला किसी बात का पता न हो तो बीच में बोलना जरूरी नहीं होता(विघ्न)

श्रीमती शारदा रानी :

चौधरी शिव राम वर्मा : 1960-61 के आंकड़े सब सालों पर लागू होते हैं अकेले एक साल परे ही लागू नहीं होते हैं । तो

मैं यह कह रहा था कि.....

Deputy Speaker : I will request the hon. Member to conclude his speech.

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो उन्होंने कहा कि यह रिमार्कस एक्सपंज कर दिए जाएं, यह ठीक नहीं ।

Deputy Speaker : If any such thing has been said by the hon. Member, that should be expunged.

चौधरी रिजक राम : मैंबर साहब के बारे भी जो कहा गया किमे भी एक्सपंज कर दिए जाएं ये भी ठीक नहीं हैं ।

चौधरी शिव राम वर्मा : तो मैं यह कह रहा था कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान को इनसैंटिव देना चाहिए और इनसैंटिव देने के लिए उसकी उपज की कीमत उचित देनी चाहिए । जब हम कहते हैं कि किसान को उसकी खेती की उचित कीमत दो तो कहते हैं कि खाने वाला ऐडजस्ट नहीं कर सकेगा उसे मंहगा अनाज मिलेगा । मैं अर्ज करता हूँ कि यह जो पचास लाख टन अनाज बाहर से आएगा यह बहुत मंहगा आएगा और इस पर विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी तो उसको कैसे खाने वाले के लिए ऐडजस्ट करेंगे । अगर बाहर से मंहगा अनाज मंगाकर ऐडजस्ट कर सकते हैं तो अपने किसान को इनसैंटिव देने से कैसे ऐडजस्टमेंट खराब हो जाती है । हम किसान को इनसैंटिव देकर

उसकी पैदावार बढ़ा कर विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं अपने देश में अनाज की पैदावार बढ़ाकर देश को खुशहाल बना सकते हैं— (घंटी)— बस जी मैं एक मिनट में एक बात परिवार नियोजन के बारे में कह कर खत्म करता हूँ । यह जो परिवार नियोजन का प्रोग्राम चल रहा है इसमें बड़ी भारी कमी है और इस सारे प्रोग्राम से सहमत नहीं जिस तरह से कि यह चल रहा है । जिस तरह से यह चला आ रहा है इस तरह से परिवार नियोजन नहीं होगा बल्कि मैं समझता हूँ देश खस्सियों का बन जाएगा । होता यह है कि कोई कर्मचारी अफसर कितना ही लायक हो कितना ही अपने काम में माहिर हो ऐफीशियट हो लेकिन परिवार नियोजन के आंकड़े अगर उस के कम रहेंगे तो वह लायक एफिशियेंट अफसर या कर्मचारी नहीं माना जाता । किसी अफसर की योग्यता चाहे वह किसी महकमे का है बी. डीओ. है, पंचायत अफसर है या एसडीएम. है इस बात पर निर्भर करती है कि उसने परिवार नियोजन का कितना काम किया है । इस से यह होता है कि अफसरों का कर्मचारियों का काम करने का उत्साह मारा जाता है । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए टीचरों को धमकियां दी जाती हैं कि अगर उनका फ़ैमिली प्लानिंग के काम का रिजल्ट कम रहेगा तो उनको हटा दिया जाएगा । कंवारी लड़कियां जो टीचर सिलैक्ट होती हैं उनको कहते हैं कि सिलैकशन तो हो गई लेकिन जब तक परिवार नियोजन के दो— दो केस नहीं लाएगी उनको अप्वायटमेंट आर्डर नहीं मिलेंगे — (घंटी) — ।

Mr. Speaker : Order please. No repetition please.

चौधरी शिव राम वर्मा : बस जी एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ (विधन) —तो मैं कहना चाहता हूँ कि किसी कर्मचारी की योग्यता परिवार नियोजन के काम से नहीं आंकी जानी चाहिए बल्कि जिस विभाग का वह कर्मचारी है उस विभाग में जो उसने काम किया है उससे आंकी जाए । बिचारे कर्मचारी दो—दो सौ रुपया देकर केस पकड़ कर लाते हैं जबकि उनकी खुद की तनखाह तीन चार सौ रुपए होती है । — (घंटी)— अच्छा जी मैं खत्म करता हूँ और यही अर्ज करता हूँ कि जो बातें मैंने कही हैं सरकार उन पर विचार करे देश की जो स्थिति आज है उसे देखे और हालत को सुधारने का प्रयत्न करे ।

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार) : स्पीकर साहब, हाउस में गवर्नर साहब के एड्रैस पर काफी भाई बोले और आज भी बजट की जनरल डिसकशन पर अपोजीशन के भाईयों ने बहुत बातें कहीं हैं और चर्चा की है । मैं कुछ बातें जो गवर्नर साहबके एड्रैस की डिसकशन पर कही गईं, उन पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ । मेरे माननीय सदस्य दौलता साहब ने गवर्नर साहब के अभिभाषण पर बोलते हुए कुछ अजीब सी बातें इस हाउस में कहीं । ऐसा मालूम होता था कि उनके बोलने का मकसद आज के मौजूदा मुख्य मन्त्री की खुशामद करना ज्यादा था और गवर्नर साहब के एड्रैस की बातों की तरफ ध्यान दिलाना कम था । वह बहुत मुद्दत से इस कोशिश में हैं कि उनको कांग्रेस में ले लिया जाए, लेकिन उनको

लिया नहीं जाता । उन्होंने इस बारे में सवाल भी किया कि उनको क्यों नहीं कांग्रेस में लिया जाता, इसका उनको पता नहीं चलता । मैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्या कारण है..

कई अध्यक्ष : आप उनकी मदद कर दें – (हंसी) ।

श्री गुलाब सिंह जैन : मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन बदकिस्मती से वह इस वक्त हाउस में नहीं हैं । हिन्दू शास्त्रों में एक कहानी आती है ध्रुव भक्त की कि उन्होंने बहुत घोर तपस्या की कि उनको भगवान के दर्शन हों, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए । जब नारद जी उनके पास आए, तो ध्रुव भक्त ने इसका कारण पूछा कि उनको भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते । तो नारद जी ने उनसे कहा कि उनकी तपस्या में कुछ कमी जरूर है । दौलता साहब की तपस्या में क्या कमी है वह शायद उनको मालूम ही होगी, और अगर उनको वह कमी मालूम है, तो जब वह उसे दूर कर देंगे, तो उनको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, मेरा मतलब है कि उनको कांग्रेस में ले लिया जाएगा । हां तो मैं अर्ज कर रहा था कि नारद जी ने ध्रुव से कहा कि उनकी तपस्या में कमी यह है कि आपकी अपनी सौतेली मां के प्रति जो भावना है, वह कटु है और आप सब की भलाई तो चाहते हैं लेकिन अपनी सौतेली मां की भलाई नहीं चाहते इसलिए जिस दिन उन्होंने ध्रुव से कहा कि आप अपनी सौतेली मां के प्रति कटु भावना का त्याग कर देंगे और कह देंगे कि आपकी सौतेली मां का भी भला हो, उसी दिन आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे । एक बात उन्होंने

और कही कि भगवान के दर्शन करने से पहले गुरु जरूर धारण करना पडता है । धरुव जी ने ऐसा ही किया और नारद जी को अपना गुरु बनाया । तो मैं दौलता साहब को बताना चाहता हूं कि आमतौर पर वह यह कहते रहते हैं कि वह जातपात और कम्यूनिलज्म से कोसों दूर हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि उनके रोम-रोम के अन्दर कम्यूनिलज्म बसा हुआ है । मैंने पहले भी उनके बारे में कहा था

इस हाउस के अन्दर कि मुझे तो वह रंगे हुए गीदड़ की तरह नजर आते हैं । मैं उसी अपनी बात को फिर दोहराता हूं और उसे कन्फर्म करता हूं कि उनके दिल में कुछ है और जबान से कुछ कहते हैं ।

आज उन्होंने कहा कि हमने डा. गोपी चन्द को बरदाश्त किया, हमने सच्चर साहब को बरदाश्त किया, भगवत दयाल को बरदाश्त किया और आज गुप्ता को भी बरदाश्त करना पड़ेगा । मैं कहता हूं किवे कौन होते हैं बरदाश्त करने वारने? हरियाणा की जनता के अन्दर कम्यूनिलिज्म नहीं है, लेकिन उनके दिल में जरूर है । स्पीकर साहब, उन्हेंने अजगर का शब्द इस्तेमाल किया था, पंडित भगवत् दयाल के बारे में बोलते हुए कहा था कि इनसे हम अजगरों ने हकूमत को छीना है । जिनके इस तरह के ख्यालात हों, मैं उन से कहूंगा कि वे इस रंग को छोडकर सही रंग में आ जाएं जिसको आज की जनता चाहती है और देश को जरूरत है, तब कहीं वे कसीडर होंगे, वरना जब तक उनके ख्यालात

कम्युनलिजम ढंग के बने रहेंगे, तब तक कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी में उनके लिए कोई जगह नहीं है । उन्होंने हमारे आदरणीय चौधरी बंसी लाल जी के बारे में कहा, मुझे दुःख है क्योंकि इधर तो उन की चापलूसी करते रहते हैं कि किसी तरह से उनका काम बन जाए, वे उनको अपना रिश्तेदार भी बतलाते हैं, उनके बारे में उन्होंने यह कहा कि वे क्रिटिसिजम को मुआफ नहीं करते । यह बात गलत है, चौधरी बंसी लाल जी क्रिटिसिजम को हमेशा वैलकम करते रहे हैं । इस हाउस में बीसों मिसालें ऐसी हैं कि जब कभी अपोजीशन के भाईयों ने ठीक सुझाव दिए हैं, उन्हें उसी वक्त उनको माना है, ऐसा अनेक बार हुआ है । मैं जानता हूँ कि उनका दिल कितना विशाल है, उसके बारे में मैं ज्यादा कृउछ नहीं कहना चाहता । मैं क्या कहूँगा, आज सारा देश उनके बारे में कह रहा है । मैं उनके करैक्टर को मानता हूँ, उनके डायनामिजम को मानता हूँ । मैं एक मिसाल देकर दौलता साहब को बतलाना चाहता हूँ कि चौधरी बंसी लाल ने फिजूल लोगों की बात को कभी बरदाश्त नहीं किया, वे बेहूदगी को कभी बरदाश्त नहीं करते थे । अगर बेहूदगी ही अपोजीशन का क्रिटिसिजम है तो मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ कि चौधरी बंसी लाल उसको कभी भी बरदाश्त नहीं करते थे । वे विशाल हृदयी थे । आप उनके रवैये को देखें, वे सिकन्दर की तरह थे, जिन्होंने पोरस को माफ किया था । उन्हेंने पोरस से पूछा था कि बताओ, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो उन्होंने कहा था, जैसा एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है । चौधरी रिजक राम को मालूम होगा,

पंडित भगवत दयाल जी. उनके दोस्त हैं । जब उनकी लड़की की शादी थी, तो इन्होंने सगुन भेजा, अपनी मुबारकबाद भेजी । पंडित भगवत दयाल ने कहा कि आज मैं जेल में हूँ, मेरा मेजर आप्रेशन होना है, पता नहीं मैं जिन्दा रहूँ या मरूँ । मेरी दो ख्वाहिशें हैं । चौधरी रणबीर सिंह के द्वारा उन्होंने ये बातें कहकर भेजीं । उन्होंने कहा कि मेरी धर्म पानी— हार्ट की बड़ी. सत्त मरीज है । जो प्रेजीडेंट आफ इंडिया का डाक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, उससे इसका इलाज करवाया जाए । दूसरी बात यह है कि जब वे भिवानी में जाएं! तो मेरी लड़की की शादी में शामिल हों और उसको आशीर्वाद दें । जब यह मैसेज चौधरी बंसी लाल जी के पास पहुंचा तो उन्होंने बड़ा महसूस किया । पंडित भगवत दयाल, इनको चीफ मिनिस्टरशिप से हटाने के लिए फिजूल चार्ज लगाने में सबसे आगे रहते थे लेकिन उन्होंने अपनी दरियादिली का सबूत दिया । उन्होंने उसी वक्त डाक्टर करोली को टैलीफोन किया कि तमाम खर्चा मेरा होगा, आप फौरन मिसिज भगवत दयाल का इलाज शुरू कर दें । यही नहीं, जब वे भिवानी गए, तो अपने मकान पर पीछे गए, सबसे पहले वे उस लड़की के घर आशीर्वाद देने के लिए गए और उसे कहकर आपु' कि तुम मेरी बेटी हो और सारी उम्र मेरी बेटी रहोगी । मैं जानता हूँ, चौधरी बंसी लाल जी जो बात कहते हैं, उसको हमेशा पूरा करते रहे हैं और वे इसे हमेशा बेटी मानेंगे । यही नहीं, जब उनके पास यह बात पहुंची, तो उन्होंने उसी वक्त आई.जी पुलिस को फोन किया कि पंडित भगवत दयाल पर से तमाम रिस्ट्रिक्शन्ज हटा दी जाए, उनको

रिलीज कर दिया जाए । उन्होंने यहां तक कहूँ कि तुम्हारे इलाज का तमाम खर्चा मैं दूंगा । इधर आज उस शख्स के बारे में दौलता साहब संकुचित हृदय की बात कह रहे थे, उधर उन की खुशामद करते हैं और गांव पकड़ने की कोशिश करते हैं, चापलूसी करते हैं कि कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए वे इस तरीके से क्रिटिसीजम करते हैं और ब्लैक मेल करना चाहते हैं, यह तरीका ठीक नहीं । मैं उनको बतला देना चाहता हूँ कि चौधरी बंसी लाल किसी से ब्लैक-मेल होने वाला नहीं है । आज चौधरी बंसी लाल के बारे में कोई गलत बात कहना, सूरज की तरफ मुँह करके थूकने के समान है, जो थूकने वाले के मुँह पर ही पड़ता है, सूरज का कुछ नहीं बिगडता, वह उसी तरह चमकता है । तो मैं दौलता साहब से मुअद्बाना अर्ज करूंगा कि वे इस तरीके की बातें छोड़ दें, हैल्दी क्रिटिसीजम करें । हैल्दी क्रिटिसीजम चौधरी बंसी लाल भी सुनते हैं, बरदाश्त भी करते और उसको मानते भी थे, ऐक्ट भी करते थे आज का मुख्य मन्त्री भी इस क्रिटिसीजम को सुनेगा और मानेगा । आप लाख खुशामद करें, वे भी गलत बात नहीं सुनेंगे, न चौधरी. बंसी लाल बरदाश्त करते थे और न हमारा मौजूदा माननीय मुख्य मन्त्री बर्दाश्त करेगा ।

स्पीकर साहब, इसके बाद एक चीज और मजेदार हुई । चौधरी फूलचन्द (रोहट) बोल रहे थे । वे बहुत मीठा बोलते हैं, मीठा बोलने में माहिर हैं, उनकी शक्ल से, उनकी बात से अन्दाजा

नहीं लगाया जा सकता कि यह कितनी कनिगली बात कर रहे हैं । जब बोल रहे थे, तो मैं ऐसा समझ रहा था कि वे गवर्नर एड्रैस पर बात कर रहे हैं या इस बात की कोशिश में हैं कि आयंदा के लिए उन को गिरफ्तार न किया जाए । वे अपनी गिरफ्तारी का रोना रो रहे थे । मैं हाउस में बैठकर उनकी बात को बड़ी शांति के साथ सुनता हूँ, मैं उनको बड़ा इंटैलीजेंट मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ वे रिसोर्सिज कमेटी के मेंबर हैं । मैं समझता हूँ कि वे बहुत ठोस सुझाव देंगे, सरकार का ध्यान बहुत अच्छी बातों की तरफ दिलाएंगे सरकार की कमियां बताएंगे, ताकि सरकार उन कमियों को ठीक करे, क्योंकि अपोजीशन का यही रोल होता है । वे ग्रेजुएट भी हैं, एल. एल. बी. भी हैं, और बहुत पुराने विधायक भी हैं अच्छे पोलिटिशियन हैं । लेकिन उनकी तमाम स्पीच का एक ही मुद्दा था कि कभी ऐसा न हो, कि बाहर निकले और फिर न पकड़े जाएं । हमारेरू मुख्य मन्त्री साहब ने इसका जवाब दे दिया था कि आपको पकड़ा होगा, तो आप अन्दर ही अन्दर कुछ कर रहे होंगे, तभी पकड़ा है, वरना किसी आदमी को हम गलत नहीं पकड़ते । एक चीज उन्हेंने और कही जिसका मुझे जरूर दुख हुआ । या तो आदमी साफ कहे, साफ तो वे कहते नहीं । उन्होंने कहा कि चौधरी बंसी लाल जी की जो कारगदंगी थी, हरियाणा की डिवैल्पमेंट में जो इनका हाथ था, जो इनकी डायनामिजम थी, वह ठीक नहीं थी, इन्होंने उसको बी-लिटल करने की कोशिश की कि जो हरियाणा में तरक्की हुई है, वह तो वक्त की वजह से हुई वह वक्त का तकाजा था, वक्त ने उनका साथ दिया । मैं उनसे पूछना

चाहता हूं, अंग्रेजी में एक कहावत है कि वक्त को जो पकड़ता है मजबूती से वह भी तो कारगरदगी है । बहुत से लोग हैं, जिनको मौका मिलता है, वे उस मौके को वेस्ट कर देते हैं, लेकिन चौधरी बंसी लाल के अन्दर यह गुण था कि वे मौके को हाथ से जाने नहीं देते थे । स्पीकर साहब, मैं इस मामले को बहुत तफसील के साथ लम्बा नहीं करना चाहता ताकि चौधरी बंसी लाल जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सके, लेकिन मैं चौधरी फूलचन्द जी को यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज वे उस हरियाणा के सबूत के बारे में, जिस पर एक एक हरियाणवी को नाज है उसने जो कुछ हरियाणा के लिए किया उसका अहसान हमारी पुश्तें नहीं उतार सकतीं । उनकी कारगरदगी को उनकी अचीव मैट्स को बी-लिटल करने की कोशिश न करें इसलिए कि चौधरी बंसी लाल जी ने उनको कुछ अर्से के लिए जेल में रखा । अगर जेल में न रखते तो वे ऐसा न करते । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो बातें गवर्नर अभिभाषण के ऊपर माननीय सदस्यों ने कहीं हैं वे बातें कुछ ठीक नहीं थी । आज बजट पर बोलते हुए चौधरी रिजक राम ने कुछ कहा है । वे बहुत सुलझे हुए पोलिटीशियन हैं मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं । काफी बातें उन्होंने ठोस भी कहीं हैं । ज्यादा अर्सा तो वे हरियाणा के बारे में न बोलकर, गवर्नमेंट आफ इण्डिया की पालिसी पर ही बोलते रहे । लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं वे तोड़ मरोड़ कर कहने की कोशिश की ऐसा नक्शा पेश करने की कोशिश की कि जैसे सैन्ट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट केवल अमीरों के लिए है, अमीरों की ही वकालत करती

है, अमीरों के लिए बीफ हाथ में लिए बैठती है और 'गरीब के लिए कुछ किया ही नहीं और न ही आगे के लिए गरीबों के लिए किया जा रहा है । ऐसा कुछ उनके भाषण से नजर आता है । उन्होंने 20 प्यांवाट प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले कहा । (चौधरी रिजक राम की तरफ से विधन) प्रचार वो डैमोक्रेसी में सब चाहते हैं । जो अच्छा काम करता है उसकी व्याख्या वह करता ही है । हर एक को इस बात का शौक होता है कि जो अच्छा काम हो उसको वह कहे । एक आदमी अगर अच्छा सूट बनवा लेता है तो वह गर्व के साथ चलता है बड़ी-बड़ी बातें करता है । जिन को हम कह नहीं पाते उनको कहने की प्रैस हमारे पास नहीं है, वह तो विरोधी लोगों के पास है । चौधरी रिजक राम जब बोल रहे थे तो मैंने उनको टोका नहीं । हम आफ दी प्वांयट जाएंगे तो सबको पता चलेगा आप भी वकील हैं और मैं भी वकील हूं वकील होते हुए पता होता है कि हम कहां रहते हैं ।

18.00 बजे

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बीस सूत्री प्रोग्राम के बारे में उन्होंने अपनी बात शुरू की । मैं समझता हूं कि बीस सूत्री प्रोग्राम हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम हैं जैसे कि हमारे जैनीजम में पांच अनाव्रत होते हैं । बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम भी हमारे हैं लेकिन this is the minimum which the Government of Inida wants to do, which the Congress party wants to do. इसकी बैकग्राउंड जो है वह हरियाणा को लेकर नहीं, चौधरी रिजक राम को लेकर नहीं

बल्कि जिस समय हमारी आदरणीय प्रधान मन्त्री ने यह प्रोग्राम रखा उस समय उनके सामने हरियाणा नहीं था चौधरी रिजक राम नहीं थे अपितु तमाम कटरी की तस्वीर थी । मैं मानता हूं कि हरियाणा में बाउंडिड लेबर नहीं है लेकिन स्पीकर साहब, शापको भी तथा दूसरे सदस्यों को भी मालूम होगा कि कितने ही सूबों में कितने लाखों लोगों को राहत मिली है । बाउंडिड लेबर भारत के माथे पर यूक कलंक था जिसको हमारी प्रधान मन्त्री ने मिटाया है । जिस वक्त चौधरी फूल सिंह जी गवर्नर ऐड्रैस पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि 20 सूत्री प्रोग्राम उन्हें जबानी याद है और इस हाउस के दूसरे सदस्यों को इसका पता ही नहीं । मैं यह सुनकर बड़ा हैरान हुआ । मैंने सोचा कि जिसको कुछ करना ही नहीं है वह तो कहता है कि मुझको जबानी याद है और जिन्होंने इसे एक्जीक्यूट करना है या जो इसे एक्सीक्यूट कर रहे हैं उन्हें वे कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है । यह कितनी बेतुकी सी बात थी । स्पीकर साहब, प्रधान मन्त्री ने एलान किया कि इन्कम टैक्स का जो मिनिमम रेट है जो लिमिट है उसको वे बढ़ाएगी और उसे उन्होंने 6000 से उठाकर 8000 कर दिया । इसका बहुत से लोगों को फायदा पहुंचा । प्रधान मन्त्री ने एलान किया कि उन्होंने हथकरघे को, हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना है । आज आपको मालूम है कि इस सम्बन्ध में क्या कुछ किया जा रहा है । हमारे मुख्य गली जी ने भी और वित्त मन्त्री जी ने भी अपने भाषणों में कहा कि हम किस तरह से वीवर्ज कालोनीज खोलकर हथकरघे को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । प्रधान मन्त्री ने एलान

किया कि हम लेबर को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं इंडस्ट्रीज के अन्दर और उसके लिए इफेक्टिव स्टैप्स उठाए जा रहे हैं । प्रधान मन्त्री ने ऐलान किया कि विलेज इंडैटिडनैस के लिए कुछ कदम उठाने हैं । मैं मानता हूँ कि यह प्रोग्राम भी केवल हरियाणा के लिए नहीं है लेकिन अपने माननीय सदस्यों की नालेज के लिए मैं फिर अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस वक्त इस प्रोग्राम का ऐलान किया गया उस वक्त प्रधान मन्त्री के सामने हिन्दुस्तान की तस्वीर थी हरियाणा की नहीं । मेरे दोस्त हिन्दुस्तान के दूसरे सूबों में मेरे साथ चलें । इनको पता लगा जाएगा कि विलेज इंडैटिडनैस की क्या हालत थी । स्पीकर साहब, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र में बड़ी भारी इंडैटिडनैस थी विलेजर्ज के अन्दर और सरकार ने यह कदम उठा करके उस इंडैटिडनेस को मॉरेटोरियम दिया है । मैं ऐसा समझता हूँ कि इसको बिल्कुल खत्म करने के लिए भी बाद में करूर कोई कानून आएगा । फिलहाल हमको ब्रीदिंग टाईम चाहिए था और वह ब्रीदिंग टाईम दे दिया गया । I welcome it. I am a democrat हम डैमोक्रेसी के प्रोडक्ट हैं । अगर ऐसा नहीं होता तो आज गुलाब सिंह जैन यहां नहीं होता । मैं कहीं मुंशीगिरी करता होता । न ही गुप्ता जी यहां होते । रिजक राम जी का तो मुझे मालूम नहीं शायद बड़े लैण्ड लार्ड हो रहे हों लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि कोई बड़े लैण्ड लार्ड यहां होते नवाब और राजे महाराजे यहां होते । हम डैमोक्रेट हैं । डैमोक्रेसी के बाहर हम कैसे जा सकते हैं? जिस वक्त मेरे अपोजीशन के भाई यह कहते हैं कि डैमोक्रेसी खतरे में है मुझे बड़ी हैरानी होती है ।

खैर, इस वक्त मैं इस तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहता । मैं तो अर्ज कर रहा था कि आज वे चलें मेरे साथ दूसरे प्रान्तों में और देखें कि लोगों को इनडैटिडनैस से कितनी तकलीफ थी और इस मोरेटोरियम की वजह से वहां के लोगों को कितनी बड़ी राहत मिली है, कितना बड़ा फायदा हुआ है । बीस सूत्रीय प्रोग्राम में ब्लैक मनी के खिलाफ भी प्रधान मन्त्री ने कहा और आपने देखा कि सरकार ने सैन्ट्रल गर्वनमेंट ने जो स्टैप्स लिए उनकी वजह से 14— 15 करोड़ रुपया इनकम टैक्स एक्ट वैल्थ टैक्स एक्ट, ऐस्टेट ड्यूटी एक्ट और गिफ्ट टैक्स एक्ट आदि के तहत बाहर निकला है । यह सब कुछ अगर अपोजीशन के भाई देखने की कोशिश करें तो ये महसूस करेंगे कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया इस मामले में बड़ी सीरियस है । कितनी कड़ी सजाएं इसने रखी हैं और तमाम मशीनरी को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है । इससे पहले भी दो डिसक्लोजर स्कीम्ज आई थीं लेकिन उनमें इतना डिसक्लोजर नहीं हुआ था । इसकी वजह यही है कि आज एक—एक पूंजीपति को डर है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया बड़ी सीरियस है जो कानून बनाए जा रहे हैं वे बड़े सख्त हैं और उन कानूनों पर सीरियसली अमल होगा । मैं परसों इकॉनोमिक टाइमज में एक आर्टिकल पढ़ रहा था । उसमें लिखा था कि सेल्ज टैक्स एक्ट, गोल्ड कन्ट्रोल आर्डर और कम्पनी एक्ट की कुछ दफात के बारे में जो क्लैरिफिकेशन आई वह कुछ लेट थी । अगर वे जल्दी आ जातीं तो हमारे एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि आज जो डिसक्लोजर हुआ है यह उससे चार टाइम ज्यादा होता । एक तारीख को जब मैं कांग्रेस

का सैशन अटैण्ड करने आ रहा था तो इस प्रोग्राम के बारे में मैंने माननीय चौधरी बंसी लाल जी से बात की थी और कहा था कि आप इसकी डेट और बढ़वा दें, क्योंकि मेरे ख्याल में आज लोगों में एक टैम्पो बना है, लोग यह महसूस करते हैं कि ब्लैक मनी को सरकार रखने नहीं देगी, लोग आज इस मूड में हैं, कि अपनी ब्लैक मनी को डिसक्लोज करके अपने आप को धो लें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ और स्टैप्स लेंगे और अब इसकी डेट नहीं बढ़ाई जा रही है । खैर, गवर्नमेंट आफ इण्डिया वे स्टैप्स तो लेती ही, लेकिन इससे एक बात बिल्कुल साफ हुई है कि आगे जो ब्लैक मनी जैनरेट होता था, वह आज बन्द होता जा रहा है, क्योंकि ऐसा होने के जो कारण थे, उनको गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने समझा और उनके लूपहोल्ज को प्लग-अप किया ।

इसी तरह स्पीकर साहब, स्मगलिंग के बारे में भी हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं । आज बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जो इसके तीन बड़े सैन्टर थे, सूने पड़े हैं । आज वहां यदि कोई स्मगलिंग की घड़ी लेना चाहे, तो वह आसानी से नहीं मिलेगी, नकली भले मिल जाए । फौरेन के नाम से भारत की बनी हुई घड़ी आपको मिल जाएगी, लेकिन हकीकत में फारेन में बनी हुई चीज आज इण्डिया में आपको नहीं मिलेगी । आज भी स्पीकर साहब, जगह-जगह छापे पड़ रहे हैं । रोजाना अखबारों में इसके आंकड़े आते हैं । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, स्पीकर साहब, मेरे फाजिल दोस्त यह नहीं कह

सकते कि हमारा जो बीस-सूत्रीय प्रोग्राम है, उसका उनको ज्यादा से ज्यादा पता है और हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है । दूसरे यह कहना भी बिल्कुल गलत है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ईस बारे में सीरियस नहीं है । तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ! वह यह है कि बीस सूत्रीय प्रोग्राम हमारी बेसिक बातें हैं और छोटी-छोटी बातें हैं जिन्हें जल्दी से किया जा सकता है । यह नहीं कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया का यही प्रोग्राम है । इसके और भी प्रोग्राम हैं । कांग्रेस पार्टी का स्पीकर साहब, आपको मालूम है, सबसे पहला प्रोग्राम था, देश को आजाद कराने का और चौधरी रिजक राम ने देखा, हमने भी देखा, हमारे बच्चों ने भी देखा और बुजुर्गों ने भी देखा, अपने जमाने में ही कि देश आजाद हुआ । मजाक करते थे मेरे अपोजीशन के भाई जिस वक्त हम हिन्दुस्तान की आजादी का नारा लगाते थे । मुझे एक बात याद है । जब 1930 में मैं आजादी की लड़ाई में भाग लेने लगा, तो मैं स्कूल में पढता था । मैंने अपनी स्वर्गीय माता जी से कहा कि मुझे चरखा चलाना सिखा दो । वे बुरउर्ग औरते थीं, सीधी सादी थीं, कहने लगीं कि मैं चरखा चलाती हूँ, तेरी बुआ चरखा चलाती है और तेरी दादी चरखा चलाती है लेकिन अभी तक तो अंग्रेज गए नहीं । मैंने कहा कि मुझे मालूम नहीं । बापू गांधी का हुक्म है कि चरखा चलाना सीखो, वरना कांग्रेस में जगह नहीं । मैंने देश के लिए काम करना है, इसलिए मुझे चरखा चलाना सिखा दो । यह उस चरखे की झन्कार थी जिसने देश को आजाद कराया । यह ऐरा है, जिसे गांधी पेरा कहते हैं, गांधी युग कहते हैं । इसके बाद

माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के हाथ देश की बागडोर आई । उन्होंने यह देखा कि एक हजार साल की गुलामी से हिन्दुस्तान आज पिसा पड़ा है और इसमें न कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का है और न ही ऐग्रीकल्चर का है ।

जब देश आजाद हो जाता है, तो उसके चारों तरफ दुश्मन भी हो जाते हैं, जो उसको हडपना चाहते हैं । सबसे पहले उन्होंने इस देश को ऊंचा उठाने के लिए यहां पर पंचवर्षीय योजना द्वारा वह इन्फ्रास्ट्रक्चर पैदा किया, जिसकी मेहरबानी से हम अमेरिका से अनाज लेते थे, बन्द किया । पहले हम अमेरिका पर निर्भर करते थे । सन् 1965 में पाकिस्तान का हमला हुआ, भारत को हथियार देने बन्द कर दिए तो हमने विदेशों का मुकाबला किया । आज मेरे अपोजीशन के भाई माने या न मानें चाहे डूम की तरह से कहते रहें कि "मैं न मानूं, मैं न मान" वह अलग बात है, लेकिन यह सब उनकी पंचवर्षीय योजनाओं के कारण हुआ । सन् 1947 के हिन्दुस्तान में ओर आज के हिन्दूस्तान में बहुत ज्यादा अन्तर है । सन् 1967 का हरियाणा और आज सन् 1975 के हरियाणा में बहुत बड़ा फर्क है । मुझे तो शर्म आती है, कम से कम (पुनको ईमानदारी तो बरत लेनी चाहिए । जो कुछ यहां पर हो रहा है, उसको तो मान लेना चाहिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए ।

आजकल जो 20 सूत्रीय प्रोग्राम चल रहा है, उसकी भी उन्हेंने चर्चा की । जो कुछ देश में हो रहा है, उसका भी मजाक

उड़ाने की कोशिश की जाये, यह उचित नहीं है । कमियां हम में जरूर रहेगी! कमियां काम करने बारने में जरूर होती हैं, बोलने वाले में नहीं होतीं । जो काम करता है, वह परफैक्ट नहीं होता, कोई परमात्मा से मिलना चाहे! तो इस तरह से नहीं मिल सकता । अगर ठीक तरीके से चले, नियमों का पालन करे, तो अच्छा आदमी बन सकता है । चौधरी रिजक राम जी को कहूंगा कि हम लोगों में कमियां हो सकती हैं । रूलिंग पार्टी परफैक्ट नहीं हो सकती । पहले जब वे इसमें थे, तब भी वे परफैक्ट नहीं थे । परफैक्शन कभी हुआ नहीं करती । -- (विधन) -- चौधरी रिजक राम जी और चौधरी फूल चन्द जी दो- दो और तीन-तीन घंटे बोरने हैं, मैंने उनकी स्पीच में कोई दखल नहीं दिया था ।

Mr. Speaker : Order please. No direct talks please.

श्री गुलाब सिंह जैन : स्पीकर साहब, अब मैं प्रोहिबिशन की बात कहना चाहता हूँ । ठीक है कांग्रेस का प्रोग्राम प्रोहिबिशन का है । हम यह भी समझते हैं कि इससे आमदनी है । हम उस पर यकीन भी करते हैं कि प्रोहिबिशन लागू की जाए । अगर आप अखबारात का मुतालबा करते हैं, तो अभी पिछले दिनों हमारी प्रधान मन्त्री जी ने प्रोहिबिशन के बारे में कहा था । वह 12 प्वांयट प्रोग्राम है, वह देश के सामने रखा ीए । आप आर्य समाज के लीडर हैं मुझे तो उससे वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन रोहतक जिला जो पहले सोनीपत का हिस्सा था, वहां पर पहले मुकम्मल तौर पर प्रोहिबिशन की थी । वहां पर चौधरी रिजक राम जी ने ही ढील

करवाई । हमें मजबूर होकर वहां से विदड़ा करना पडा । क्योंकि दिल्ली का रेवैन्यू बड गया और हमारा घट गया । एक बात स्पीकर साहब, मैं और कहना चाहता हूं कि प्रोहिबिशन लागू करने से, इस पर अमल दरामद करने में कुछ सरकार की मुश्किलात हैं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि प्रोहिबिशन होनी चाहिए । मैं चौधरी रिजक राम जी से बिल्कुल सहमत हूं ।

I am one wiht him in this respec. I am talking presonatly. I am with him in this behalf. लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहता हुं कि जिन किसानों की भलाई का यहां हाउस में अपोजीशन वाले आंसू बहा-बहा कर रोना रोते रहे हैं, कि वे बड़े दुखी हैं । स्पीकर साहब, अगर मैं गलती परूर न हूं तो जो 20 करोड़ का रेवैन्यू हमें एक्साइज से आता है, इसमें से 15 करोड़ तो अपने आप आ सकता है । आप उनको शराब पीने सेरोकिए । मेरा तो ख्याल है कि अगर पचायत रेजोल्यूशन पास कर दे कि हमारे गांव में बैंड न हो, तो सरकार नहीं खोलेगी, मुझे पक्का मालूम नहीं है लेकिन मुझे ऐसा ख्याल है । प्रोहिबिशन के बारे में हमारी प्रधान मन्त्री ने 12 सूत्रीय प्रोग्राम देश के सामने रखा है । उस पर अमल दरामद होने पर प्रोहिबिशन की बात काफी हद तक हल हो जाएगी ।

एक चीज रूरल इनडैटिडनैस के बारे में मैं कहना चाहता हूं । मैं मानता हूं कि कर्जा किसानों को दबाता जा रहा है, लेकिन जो किसान कर्जा लेते हैं उसमें से कुछ हिस्सा तो वे

फिजूलखर्ची में लगा देते हैं । सबसे बड़ा ईवल, सोशल ईवल जो है, वह ब्याह शादियों का है । आज चौधरी रिजक राम जी को मालूम है कि गांवों के लोग भी शहरों की नकल करने लग गए हैं । हमारी पार्टी ने दो तीन दिन हुए यूक बिल अप्रूव किया है कि हम सोशल रिफार्म लाना चाहते हैं । अगर अपोजीशन के भाई किसान की तकलीफ को समझते हैं । वे इस फर्जी रोने की बजाय, देहातों में जाएं, और जो फिजूलखर्ची करते हैं, उसको रोकने का प्रचार करें, तो अच्छा पेशा । मैं तो इस बात को उनके लिए ज्यादा बेहतर समझता हूं ।

यहां पर एक चीज और भी कही गई कि किसानों को आसानी से कर्जा मिलना चाहिए । सस्ते सूद पर कर्जा मिलना चाहिए । तो इस बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने गवर्नर के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा कि अभी हमने रूरल बैंक्स खोलने शुरू किए हैं । भिवानी में खुल गया है जो किसान भाइयों को देहात वालों को बिना जमानत के कर्जा देगा । बिल्कुल सूद न ले, यह तो मुमकिन नहीं हो सकता लेकिन उसका बहुत थोड़ा सूद होगा । वह सूद किसी कमर्शियल बैंक से जो इंडस्ट्रीज के लिए लोग देता है, उससे कम होगा । उनका सूद तो 15-18 और 17 परसैन्ट तक है । जहां तक मैंने सुना है, यह पांच या छः परसैन्ट सूद पर देहाती भाइयों, किसान भाइयों को कर्जा देगा । जैसा कि अपोजीशन के भाइयों ने कर्जे के बारे में कहा था, उसके लिए तो हमारी सरकार आलरेडी कर

रही है । (चौधरी शिव राम वर्मा की ओर से विधन) – Please do not disturb me. I never disturb you.

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता है कि एक टाइम ऐसा था, जब कि नेशनलाइज्ड बैंक्स देहातों की तरफ ध्यान नहीं देते थे । वे कैपिटलिस्ट को फीड करते थे । हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारी प्रधान मन्त्री ने जब यह देखा कि नान गर्वनमेंट बैंक्स कैपिटलिस्ट को फीड करते हैं तो उन्होंने उनको नेशनलाइज किया था । आपको मालूम है कि इन बैंक्स की वजह से कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुई, Nationalisation of banks was one of the reasons of congress split. उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज किया, उन्होंने सोशलाइजेशन का नारा लगाया । यह नारा चौधरी रिजक राम जी के दोस्तों का है । हमारा नारा नेशनलाइजेशन का था । That was the difference of opinion और नेशनलाइज करने के बाद काफी उनमें फर्क पड़ा है । एक दिन में तो कोई चीज होती नहीं लेकिन दिनों दिन आप देखते हैं कि जब हिसार से देहली को बसों से जाते हैं, तो देहातों में आप देखेंगे कि बोर्ड लगे हुए हैं It was a thing which was unheard of यह तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि देहातों में आसान किशतों पर, आसान ढंग से रुपया दिया जाएगा । यह मैं मानता हूँ कि कुछ फील्ड में लोग शरारत करते हैं । आपको मालूम है कि उसके रोकने के रास्ते में मैं और आप ही हैं । जो लोग गलत काम करें, उनको सजा दिलारा । बिना वजह उनकी सिफारिश न करें । जब सरकार उनको पकड़े तो उनको छुड़ाने की हमें सिफारिश नहीं करनी

चाहिए । ओपन आइज से हमें देखना चाहिए, एक ही तरीके का व्यवहार करना चाहिए । ऐसा करने से काफी ज्यादा सुधार आ सकता है । लैण्ड रिफार्म की बात यहां पर कही गई है । मैं तो बड़ा हैरान था । मैं तो यह बात ऐसे सख्श से सुन रहा हूं जिसको यह बात जैब नहीं देती । उन्होंने कहा कि हरियाणा के अन्दर हम गैर कानूनी तौर पर जमींदारों से जमीन छीन कर हरिजनों में तकसीम कर रहे हैं । कांग्रेस पार्टी ने या हरियाणा सरकार ने या गवर्नमेंट आफ इंडिया ने या हमारी प्रधान मन्त्री ने कभी ऐसा नहीं कहा । हमने तो एक ही बात कही है कि जो फालतू जमीन हमारे पास होगी, वह हम जरूर लेवे और उसको लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फालतू जमीन नहीं हए, तो हमने यह कहा है, कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि हम उन भाइयों को जिनको जमीन नहीं मिली है, उनके लिए दूसरे रोजगार मुहैया करने कीकोशिश करेंगे ।

आज मुझे. इस बात का गर्व है कि हमारी हरियाणा सरकार और हमारे माननीय चौधरी श्याम चन्द जी जो सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, इस बात पर हर वक्त सोचते रहते हैं कि नयी स्कीमें लाकर उन भाइयों को ज्यादा से ज्यादा काम दिलाए, जिनको हम जमीन नहीं दे सकते, या जिनको जमीन नहीं मिल सकती । यहां पर फ़ैगमैंटेशन आफ होल्डिंग की बात हुई, हिन्दू सक्सेशन एक्ट की बातहुई । मैं कई दफा अपने किसान भाइयों से यह बात कहा करता हूं, कि आपको अपने बच्चों को एक बात

सिखानी चाहिए. जो जमीन पर निर्भर करना चाहते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है और जमीन कोई रबड़ नहीं है जो खींच कर बढ़ा दें । फ्रैगमेंटेशन को आप रोक नहीं सकते । हिन्दू सक्सेशन एक्ट इसके लिए मेन रीजन नहीं है । जो मेन रीजन है, वह यह है कि आबादी तेजी से बहु रही है । आपको आबादी को रोकना चाहिए । आपको फ्रैगमेंटेशन को रोकना चाहिए । मैं तो उन आदमियों में से हूँ, जो यह कहूंगा कि रूल आफ प्राइमो-जनाइचर होना चाहिए । मैं यह बात सरकार की तरफ से नहीं कहता, जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं यह कहता हूँ कि रूल आफ प्राइमो-जनाइचर होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त अन-इकोनोमिक होल्डिंग हो जाती है, तो पैदावार गिर जाती है । हमको होल्डिंग अनइकोनोमिक नहीं होने देनी चाहिए । अगर आप रूल आफ प्राइमोजनाइचर के साथ चलें, तो इसके साथ मैं यह सजैस्ट करूंगा कि जैसे चार आदमियों के पास अनइकोनोमिक होल्डिंग है, उनसे लेकर आप एक ही आदमी को 8 एकड़ जमीन कर दें और बाकी के तीन को दूसरे काम में लगा दें ।-- (व्यवधान) --

चौधरी पीर चन्द: आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । जैसे कि जैन साबह ने फरमाया है कि हम जमींदार की जमीन नहीं लेना चाहते-- (व्यवधान) -

Mr. Speaker : Order Please. Order Please. No interruptions

श्री गुलाब सिंह जैन : स्पीकर साहब, एक चीज और

कही गई कि इलैक्शन के टाइम पर कुछ बातें कही जाती हैं और उसके बाद उन पररु अमल नहीं होता । लेकिन मैं मुअदबाना अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे पता नहीं चला कि वह कौन सी बात थी, जिस पर हमने इलैक्शन पर कहा और उस पर कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से अम्मल न करने की कोशिश की हो । जमीन की बात हमने कही कि हम जमीन देंगे और हमने कब यह कहा कि हम नहीं दे रहे हैं और देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं । हम बाकायदा यह कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन लोगों को दें । हाउस साइट्स के बारे में चौधरी फूल चन्द जी ने मजाक उड़ाने की कोशिश की । मैं एक बात जरूर अपने फाजिल दोस्तों और आनरेबल मेंबर से अर्ज करूंगा कि वह गलत ब्यानी करने की कोशिश न करें । वे फर्जी कहानियां बनाने की कोशिश न करें । चौधरी रिजक राम जी बड़े बुजुर्ग आदमी हैं और बड़े पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं । उन्होंने यह कहा कि. एक मील त्र जमीन, गांव से बाहर अलाट कर दी गई, जमीन खड्डों में काट दी गई । मैं बहुत बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेजीडैन्ट जरूर हूं । हमने बाकायादा तमाम ब्लाक समितियों के मेंबरों की मीटिंग बुलाकर सबको कहा कि आप अपने अपने गांव से हमें यह खबर दो कि कौन से गांव के अन्दर या तो प्लाट काटे ही नहीं गए और अगर काटे गए हैं तो गलत जगह पर काटे गए हैं । उस मीटिंग में बहुत ज्यादा तादाद में हरिजन भाई भी आए थे । एक मील की शिकायत तो हमारे पास कभी नहीं आई । यह बात जरूर आई कि किसी-किसी जगह पर यह

कोशिश की गई कि गलत जगह पर प्लाट काढे, गढी में या ऐसी जगहों पर जो उनको ष्ट न करते हों । सिर्फ एक गांव की शिकायत आई हमने उसको टूर कराया । स्पीकर साहब, आप भी देहाती हलके में गए हैं, आप अराने हल्के में जाते हैं, जब आपको मौका मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल में.. आपके नोटिस में भी इस किसर की शिकायत नहीं आई होगी डिम एक-एक मील दूर प्लाट दिए गये हों । यह ठीक है कि हमने पंचायत की जमीन ली । लेकिन मैं यह नहीं मानता कि यह किसी अकेले की मलकीयत है । हमने उसकी मलकीयत बना दी । आखिरकार इण्डिया में हम एक कौमन बेसिज मानते है कि वह सब की मु इतरका चीज है और फेंस मुश्तरका चीफ में से सब के फायदे के लिए जो भी चीज हो सकती है, वह हमने करने की कोशिश की है. । एक चीज यहां पर बोलते हुए 'कैपिटलिस्टों', बड़े आदमियों के बारे में कही गई । मैं कैपिट- लिस्टों का वकील तो हूं नहीं इंकम टैक्स के मुकदमें फीस लेकर जरूर करता रहता हूं । चौधरी रिजक राम जब बोल रहे थे तो मेरी तरफ देखरहे थे, वह क्या कहना चाहते थे, मैं बखूबी समझता हूं । मैं यहां बता दूं कि कैपिटलिस्टों का वकील नहीं हूं । I am a products of poverty. I now what poverty is मैं यह अज' करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कैपिटलिस्टों को प्लीड नहीं किया हमने उन से कभी पैसा भी नहीं त्रिया और नैशनेलाईज भी किया । मैं आपके द्वारा एक बात सदन के मेंबरान को बताना चाहता हूं कि जब पिछले चुनाव हुए, तो यी जो इंश्योरेंस कम्पनी वाले थे, उनको बड़ा ख्याल था कि इंश्योरेंस

कम्पनी जो है, यह नैशनेलाइज नहीं होगी । मेरा कुछ दोस्तों से जिक्र आया । उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की और उनके एमपी की बड़ी इमदाद कर रहे हैं । इसके अलावा भी कई बातें कहीं गयीं और जब वह यी कहते थे तो मैं हंसता था क्योंकि वह तो अपोजीशन का गलत प्रोपेगण्डा था न तो कैपिटलिस्ट्स से गवर्नमेंट ने पैसा लिया और न ही लेना था । मुझे हुस बात का पता था कि यह नैशनेलाइज होने वाली है । लेकिन इलैक्शन के दिनों में यह बात करने की थी वह बड़े खुश थे । आपने देखा कि चुनाव के बाद सबसे पहला कदम जो हमारी प्रधान मन्त्री ने लिया, वह इंश्योरेंस को नैशनेलाइज करने का था । तो मैं अर्क करना चाहता हूं कि आज गरीब की भलाई के लिए हमने सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट इण्डिया को बनाना है जो कि कांग्रेस पार्टी का ध्येय है, इसके अन्दर कोई दो राय नहीं हैं और उस तरफ चलते हुए जो कदम हम ले सकते हैं, कांग्रेस पार्टी ले सकती हैं, हम ले रहे हैं । हमने नैशनेलाइजेशन को छोड़ा नहीं हमारी प्रधान मन्त्री ने क्या कहा? उन्होंने यह कहा कि पहले हम जो कुछ नैशनेलाइज कर चुके हैं, उसको स्ट्रमिलाईन करना चाहते हैं । आपने देखा होगा कि हमारी पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्री मुनाफा नहीं दिखा रही हैं । उनमें कुछ बदइन्तजामी थी, क्योंकि केडर नहीं था । जब देश आजाद हुआ तो आईसीएस. के अंग्रेज लोग चले गए और हमारी फौज के जो अंग्रेज जरनल थे, वह चले गए । अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था "Freedom at midnight" किस तरीके से जब यह चेंज आती है, तो दिक्कतें आती हैं ।

हमने यह कदम लिया और डैमोक्रेटिक तौर पर यह कदम लिया । मैंने हाउस में बोलते हुए पहले भी कहा था कि आज देश क्या चाहता है, आनरेबल मेंबरज क्या चाहते हैं? वे टोटैलीटेरियन रिजल्ट चाहते हैं । टोटैलीटेरियन रिजल्ट डैमोक्रेटिक मीन्ज से नहीं आया करते । अगर हम थोड़ा सा कदम भी उठाते हैं तो यह चिल्लाने लग जाते हैं कि साहब जम्हूरियत का खून हो रहा है । अभी प्रैस के बारे में कह रहे थे कि आजादी ही नहीं रही । यह कहा गया कि प्रैस की आजादी नहीं रही । हमने गलत बातों के प्रचार को रोका तो कहने लगे कि आजादी नहीं रही । तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप डैमोक्रेटिक मीन्ज से टोटैलिटेरियन रिजल्ट एक्सपैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डैमोक्रेटिक मीन्ज' से हम ऐसा नहीं कर सकेंगे । उससे रिजल्ट जरा सलो होता है, आहिस्ता-आहिस्ता चलना पड़ता है । मैं यह अर्ज कर रहा था कि इंडस्ट्रिज की नैशनेलाइजेशन का प्रिंसिपल गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने या कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा नहीं । हम उन इंडस्ट्रीज को जो नैशनेलाइज कर चुके हैं, कन्सोलिडेट कर रहे हैं । हमारा प्रिंसिपल क्या था? यह था कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, हम उनको नैशनेलाइज करेंगे । तो बेसिक इंडस्ट्रीज के लिए कोई नया लैटर आफ इंटैन्ट किसी प्रा-इवेट पार्टी को इशु नहीं किया जा रहा है । तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का प्रिंसिपल था, उससे कांग्रेस पार्टी दूर-वहीं जा रही । एक चीज और यहां पर बोलते हुए कही गई ।

चौधरी रिजक राम : मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर टाइम बढ़ाना चाहें, तो थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि जैन साहब खत्म कर लें ।

श्री गुलाब सिंह जैन : कल भी तो सेशन चलेगा । स्पीकर साहब, यहां पर एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की बात कही गई । मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ । चौधरी रिजक राम उस कमेटी के चेयरमैन थे और मैं तो उसका मेंबर था । राज कमेटी ने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को यह सुझाव दिया था कि एग्रीकल्चर इंकम पर इन्कम टैक्स लगाया जाए । और हमने बैठकर उस कमेटी में यह सोचा, हमारे मुख्य मन्त्री भी नहीं चाहते थे कि किसान को इस झंझट में डाला जाए और गवर्नमेंट आफ इण्डिया को मनाने का एक तरीका सोचा कि लैण्ड रेवेन्यू को बढ़ा दिया जाए और राज कमेटी की जो रिपोर्ट थी कि एग्रीकल्चरल इंकम टैक्स लगा दिया जाय । हमने हरियाणा में वह टैक्स नहीं लगने दिया और लैण्ड रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हमने बहुत आंकड़े लिए ।

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2.00 P.M. tomorrow.

18.00बजे

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Tuesday, the 20th January, 1976.)